LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Wednesday, August 9, 2023 / Sravana 18, 1945 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. Kirit P. Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, August 9, 2023 / Sravana 18, 1945 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

REFERENCES RE: HOMAGE TO FREEDOM FIGHTERS & MARTYRS ON 81st ANNIVERSARY OF 'QUIT INDIA MOVEMENT' AND 78TH ANNIVERSARY OF DROPPING OF ATOMIC BOMBS ON HIROSHIMA & NAGASAKI	**1**
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 281 – 300)	**1A – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 3221 – 3450)	**51 – 280**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, August 9, 2023 / Sravana 18, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, August 9, 2023 / Sravana 18, 1945 (Saka)

C ON T E N T S | **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 85
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	286
COMMITTEE ON PETITIONS 49th to 53rd Reports	287
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION 30th and 31st Reports	288
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING 59th Report	288
STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 32nd Report	288
STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION Statements	289
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES 24th Report	290
STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS 43rd and 44th Reports	290
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES Statement	291

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 54th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON FINANCE– LAID Shri Pankaj Chaudhary	291
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 24th, REPORT OF STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION – LAID Sadhvi Niranjan Jyoti	291
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 336th, 355th & 370th REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE– LAID Dr. Jitendra Singh	292
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERVATIONS IN 171st & 174th, REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON COMMERCE AND INDUSTRY – LAID Shrimati Anupriya Patel	293
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	294 - 305
Shri Mohanbhai Kundariya	294
Shri Jayant Sinha	294
Shrimati Queen Oja	295
Dr. Ramapati Ram Tripathi	295
Shri Subhash Chandra Baheria	296
Shri Parbatbhai Savabhai Patel	296
Shrimati Rama Devi	297
Dr. Dhal Singh Bisen	297

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava	298
Shri Sanjay Seth	298
Shri Naranbhai Kachhadiya	299
Shri Mukesh Rajput	299
Shri Suresh Pujari	300
Shri Akshaibar Lal	300
Shrimati Riti Pathak	301
Shri Kodikunnil Suresh	301
Shri S. Jagathrakshakan	302
Shri N. Reddeppa	302
Shri Vinayak Bhaurao Raut	303
Shri Chandra Sekhar Sahu	303
Shri Kesineni Srinivas	304
Shri Hasnain Masoodi	304
Kumari Agatha K. Sangma	305
Shri Tejasvi Surya	305
Shrimati Pratima Monday	305
Shrimati Sangeeta Azad	305
Shri Hanuman Beniwal	305

MOTION OF NO CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS (Contd.-- Inconclusive) 306 - 420

Shri Rahul Gandhi	306 - 12
Shrimati Smriti Zubin Irani	313 – 26
…	327
Shri P.V. Midhun Reddy	328 - 29
Shri Rajiv Ranjan Singh ‘Lalan’	330 - 37

Shri Ram Kripal Yadav	**338 - 44**
Dr. Kakoli Ghosh Dastidar	**345 - 49**
Shrimati Kanimozhi Karunanidhi	**350 - 56**
Shri Nama Nageswara Rao	**357 - 61**
[$]Shri K. Subbarayan	**362**
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	**363 - 66**
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	**367 - 75**
Dr. Farooq Abdullah	**376 - 79**
Shrimati Anupriya Patel	**380 - 84**
Shri E. T. Mohammed Basheer	**385 - 87**
[@]Shri Anumula Revanth Reddy	**388**
Shri Amit Shah	**389 - 418**
…	**419 - 420**

[$] For English translation of the speech made by the hon. Member Shri K. Subbarayan in Tamil, please see Supplement (PP 362–A to 362–C)

[@] For English translation of the speech made by the hon. Member Shri Anumula Revanth Reddy in Telugu, please see Supplement (PP 388–A to 388–C)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, August 9, 2023 / Sravana 18, 1945 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS PAGES

XXX XXX XXX XXX

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

MOTION OF NO CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS 362A - 62C & 388A - 88C

xxx xxx xxx xxx

Shri K. Subbarayan 362A - 62C

xxx xxx xxx xxx

Shri Anumula Revanth Reddy 388A - 88C

(1100/KDS/SMN)
1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों के शहीदों को श्रद्धांजलि के विषय में उल्लेख

और

हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 78वीं वर्षगांठ के विषय में उल्लेख

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सम्पूर्ण राष्ट्र भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर देशवासियों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी और अपने अटल संकल्प को 'करो या मरो' के नारे के माध्यम से अभिव्यक्त किया था।

भारत छोड़ो आंदोलन भारत वासियों में एकता की शक्ति और अन्याय एवं अत्याचार के विरूद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध का प्रतीक है।

इस अवसर पर, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उन उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुन: समर्पित करते हैं, जिनके प्रति हमारे स्वतंत्रता सेनानी सदैव निष्ठावान रहे।

माननीय सदस्यगण, आज से 78 वर्ष पूर्व 6 और 9 अगस्त, 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे लाखों निर्दोष नागरिकों के जीवन की क्षति हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के लोग परमाणु रेडिएशन के दुष्प्रभावों से पीड़ित हैं।

आइए, आज के दिन हम सामूहिक विनाश के हथियारों के उन्मूलन के लिए प्रयास करने और शांति तथा बंधुत्व के प्रसार के लिए मिलकर कार्य करने हेतु पुन: संकल्पित हों।

अब सभा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और जापान के परमाणु बम के पीड़ितों के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन रहेगी।

तत्पश्चात् सभा थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रही।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 281, श्रीमती लॉकेट चटर्जी।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 281)

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): My question is this. Has the Government received recommendations to formulate a plan to connect all the cities of the country through Railway network on the lines of NHDP and PMGSY? If so, what are the details and the action taken?

Has the Government proposed to fix any time limit for the expansion of Rail network? If so, what are the details? I also want to know if some regions are beyond the reach of Railways due to unfavourable geographical conditions and do these areas need to be opened to Railway for removing regional inequalities in economic growth? If so, what are the details.

(1105/MK/RU)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद रेल विभाग में जो बदलाव किए गए हैं, उनमें नई रेल सेवा शुरू करना, मौजूदा रेल सेवा के फेरों को बढ़ाना, गाड़ी चलाना, डायरेक्ट करना, यह हम कमर्शियल वैल्यु को देखते हुए करते हैं। … (व्यवधान)

1105 बजे

(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री ए. राजा, श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के बारे में सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वहां पर सरकार जमीन की उपलब्धता नहीं देती है, इसलिए वहां कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में रुके पड़े हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। आपको जवाब मिलेगा। प्लीज, आप प्रश्न काल चलने दीजिए। यह महत्वपूर्ण समय है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल का समय महत्वपूर्ण है। आप इसको चलने दीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्न काल को चलने दीजिए।

माननीय सांसद, सप्लीमेंट्री प्रश्न।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जुगल किशोर शर्मा जी।

… (व्यवधान)

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे प्रश्न संख्या 281 पर बोलने का मौका दिया। … (व्यवधान) जब से दश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी बने हैं, तब से उनके नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने बहुत उन्नति की है, विशेष तौर पर जम्मू-कश्मीर के लिए भी बहुत अच्छे कदम उठाये हैं। … (व्यवधान) अभी आपने देखा होगा कि 6 तारीख, रविवार को उन्होंने 508 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण की जो आधारशीला रखी है, यह देश में बहुत ही सराहनीय कार्य देश के प्रधान मंत्री जी ने किया है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वंदे भारत और हेमकुंट, ये दो ऐसी ट्रेन्स हैं, जो एक हरिद्वार के लिए जाती है और दूसरी दिल्ली के लिए आती है। दोनों ट्रेन्स बहुत ही कामयाब हैं। … (व्यवधान) लेकिन, मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक और वंदे भारत ट्रेन जम्मू और दिल्ली के बीच चलाई जाए और दूसरी हेमकुंट ट्रेन की तर्ज पर एक और ट्रेन हरिद्वार के लिए चलाई जाए, ताकि श्रद्धालुओं और यात्रियों को सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकें और उनको इंतजार न करना पड़े। … (व्यवधान) इन दोनों ट्रेनों में बहुत भीड़ रहती है। भारी भीड़ के कारण लोग कहीं पर भी छूट जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से प्रार्थना है कि क्या वे ये दो ट्रेन्स एक हरिद्वार के लिए और दूसरी दिल्ली के लिए चलाने की कृपा करेंगे। … (व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: अध्यक्ष महोदय, रेल विभाग में नई गाड़ी चलाना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। यह स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर करता है। … (व्यवधान) आज की स्थिति में जम्मू और कश्मीर में आंशिक रूप से पड़ने वाली अभी एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना चल रही है, जिसकी लम्बाई 272 किलोमीटर है। … (व्यवधान) माननीय सदस्य ने रेल चलाने के संबंध में प्रश्न पूछा है तो रेल चलाने की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। … (व्यवधान) अगर संभव हुआ तो मैं माननीय सदस्य को ऑफिस में बुलाकर बता दूंगा। … (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 282)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 282, श्री हैबी ईडन जी।

… (व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।… (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 283)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 283, श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' जी।

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति: अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कौशलेन्द्र कुमार जी।

… (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 284)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 284, डॉ. तालारी रंगैय्या जी।

… (व्यवधान)

DR. TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Sir, India is a cotton producing country. India's cotton productivity per hectare is reported to be lower than that of other major cotton-producing countries. … (*Interruptions*) This is mainly due to the use of outdated farming practices, inadequate rural credit, irrigation facilities and poor seed quality. What measures are being taken by the Government to transform the cotton sector? … (*Interruptions*)

(1110/SJN/SM)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : महोदय, ये टेक्सटाइल मंत्रालय का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने सीसीआई के बारे में पूछा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो निर्णय लिया है, ताकि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। उसके लिए जो भी प्रयास करने हैं, हमारी सरकार ने पूरी तरह से वह किया है।…(व्यवधान) यह सरकार इको सिस्टम से काम करती है। उन्होंने जो सवाल किया है, वह इससे संबंधित है।…(व्यवधान) मैंने बार-बार यहां से बताया है कि हमारे यहां 75 सालों में जो भी उत्पादन हुआ है, तो वह कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी। जैसे-जैसे समय बीतता गया, तो कपड़ा बनाने में बदलाव आता गया।…(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि बेस्ट क्वॉलिटी का कॉटन कैसे मिले और उसके लिए बीज कैसे मिले। पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्टर ने साथ में मिलकर स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग की और इको सिस्टम की बात की।…(व्यवधान) आजादी के इतने सालों के बाद जो हंगामा हो रहा है, उनको यह करना चाहिए था कि किस तरह से बेस्ट क्वॉलिटी का कॉटन उत्पादित हो, उसकी बिक्री बढ़े, छोटी-सी जगह में सबसे अच्छा कॉटन हो, उनको कॉटन का अच्छा बीज मिले, लेकिन उन्होंने वह नहीं किया। हम लोगों ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए कृषि मंत्री जी के साथ मिलकर वैज्ञानिक ढंग से एक सिस्टम बनाया है।…(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, तो उन लोगों को कपड़ा बनाने के लिए कच्चे कपास की आवश्यकता होती है। सीसीआई के माध्यम से सेंटर्स लगे हुए हैं, जिसमें साल में एक बार कपास की कीमत तय की जाती है।…(व्यवधान) उनके संचालन के लिए हम लोगों ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से उनको यह उपलब्ध कराया जाता है। बाद में यह वीविंग में जाकर स्पिनिंग करके कपड़ा बनकर निकलता है।…(व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 285)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।…(व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 286)

माननीय अध्यक्ष : श्री रवनीत सिंह जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

SHRI SOM PRAKASH: Sir, a Statement is laid on the Table of the House. …(*Interruptions*)

(ends)

(प्रश्न 287)

माननीय अध्यक्ष : श्री कृपानाथ मल्लाह जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।…(व्यवधान)

(इति)

(Q 288)

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): Post bifurcation of Andhra Pradesh State in 2014, what specific measures are being taken by the Government of India to promote industrial growth in Andhra Pradesh?… (*Interruptions*) In Andhra Pradesh Reorganisation Act, it was mentioned that a steel plant would be set up at Kadapa… (*Interruptions*) The hon. Prime Minister assured in this august House that special category status will be given to the newly formed Andhra Pradesh for a period of 5 years, while the then opposition party and the present ruling party demanded special category status for AP for 10 years… (*Interruptions*) In view of the above, may I know from the hon. Minister what specific steps were taken to fulfil the above assurances of a steel plant at Kadapa and special category status for Andhra Pradesh in order to promote industrial growth?… (*Interruptions*)

SHRI SOM PRAKASH: Sir, in Andhra Pradesh, we have 11 industrial corridors and a total number of 32 corridors are being set up in different places…(*Interruptions*) So, maximum numbers have been given to Andhra Pradesh… (*Interruptions*) Five corridors are being set up at different places like Visakhapatnam, Kopparthy, Chittoor, Machillipatnam and one more is being established… (*Interruptions*) Andhra Pradesh has got the maximum numbers… (*Interruptions*)

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): Sir, under the National Industrial Corridor Programme, the Government of India has approved development of 11 industrial corridors with 30 projects… (*Interruptions*) As part of the East Coast Economic Corridor (ECEC), the development project of Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor has been approved under Phase-I and the works are under progress… (*Interruptions*)

(1115/RP/SPS)

I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India will assist the State in completing this project on time and also by extending the timeline, if need be, till March, 2024.

SHRI SOM PRAKASH: Sir, there is a process for establishing any project. The State Government has to arrange land and get clearances. Only after that, the Government of India will release the funds. You have to arrange the land; make a comprehensive plan; and then, the funds will be released. (ends)

(प्रश्न 289)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नं. 289 श्री के. सुधाकरन जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, a statement is laid on the Table of the House. (ends)

(प्रश्न 290)

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विभिन्न खातों की संख्या और धनराशि डाकघरों में पड़ी हुई है, जबकि इन खातों की योजनाएं परिपक्व हो गई हैं। सरकार द्वारा उन खाताधारकों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि उनका पैसा वैध तरीके से उन्हें वापस किया जा सके?

श्री देवुसिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विभाग ने आज उन अनक्लेम्ड अमाउंट, जिनका कोई वारिसदार नहीं है या किसी वजह से नॉमिनीज़ ने फॉर्म भरते वक्त अपना नॉमिनीज़ नहीं बताया है, उनके लिए एक अलग इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। … (व्यवधान) वर्ष 2016 के बाद सीनियर सिटीजन वेलफेयर फण्ड आया और इस फण्ड से हम हर साल 30 सितंबर को अनक्लेम्ड अमाउंट को डिक्लेयर करते हैं। … (व्यवधान) हमारा विभाग इन अनक्लेम्ड अमाउंट्स की डिटेल ऑनलाइन भी करता है। हमारा विभाग पूरे देश में ट्रस्टवर्दी है। हमारा जीडीएस हर घर में जाकर यह प्रचार-प्रसार भी करता है। … (व्यवधान)

मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज तक जो अनक्लेम्ड अमाउंट था, हमने वह सारा अनक्लेम्ड अमाउंट पूरे भारतवर्ष में सेटल किया है।… (व्यवधान) मार्च, 2020 में 27,149 अकाउंट्स के 77 करोड़ रुपये वापस किए हैं, मार्च, 2021 में 68,700 के आसपास अकाउंट्स के 117 करोड़ रुपये दिए हैं, मार्च, 2022 में हमने 71 हजार अकाउंट्स के 126 करोड़ रुपये दिए हैं, मार्च, 2023 में 21 लाख अकाउंट्स सेटल किए और 1,239 करोड़ रुपये दिए हैं और जून, 2023 में 33 लाख अकाउंट्स होल्डर्स को हमने 1,270 करोड़ रुपये वेलफेयर फण्ड से उन अनक्लेम्ड अमाउंट के डिपॉजिटर्स को वैरिफाई करके वापस किए हैं। … (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा में डाकघर कर्मचारियों की भारी कमी है। वहां लोग अपनी छोटी बचत को डाक योजनाओं में लगाना चाहते हैं, किंतु वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि डाक कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं तथा उन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

श्री देवुसिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, हम करीब-करीब हर साल जीडीएस के रिक्त स्थानों पर भर्ती कर रहे हैं। मुझे आपको और पूरे सदन को एक विशेष इन्फॉर्मेशन देनी है कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री अभी रोजगार मेला चला रहे हैं।

(1120/RPS/NKL)

इस रोजगार मेले में अभी तक हमारे विभाग ने 38 हजार से ज्यादा जीडीएस की भर्ती की है।... (व्यवधान) चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि ये परमानेंट लोग नहीं हैं, इसी के चलते जीडीएस लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, बाकी सारी जो सुविधाएं एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती हैं, वे सारी सुविधाएं जीडीएस को भी मिलती है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा विभाग आज पूरे देश में सबसे ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है।... (व्यवधान) इस देश की 140 करोड़ जनता की सेवा में करीब 1 लाख 60 हजार पोस्ट ऑफिसेस और ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस हैं। ... (व्यवधान) इनके चलते हम फाइनेंस सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं और इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। ... (व्यवधान) एक जमाना था, जब कहा जाता था कि डाकिया डाक लाया। आज डाकिया इंश्योरेंस भी देता है और बैंक की सर्विस भी देता है। ... (व्यवधान) आज के दिन मुझे विशेष रूप से यह कहना है कि आपने 'क्विट इंडिया' का उल्लेख किया है। ... (व्यवधान) आज जैसे यह परिवारवाद है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने तुष्टिकरण किया है, इनका दूर होना भी 'क्विट इंडिया' जितना ही आवश्यक है।... (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 291)

डॉ. राजश्री मल्लिक (जगतसिंहपुर): सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि हमारे जगतसिंहपुर जिले में कितनी पंचायतों को कवर किया गया है और सर्विसेज के लिए कितनी पंचायतें डिप्राइव्ड हुई हैं? इनकी डिटेल्स मैं जानना चाहती हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना फण्ड एलोकेशन हुआ है? I would also like to know the details of the amount of funds allocated by the Government for laying optical fibre network in Jagatsinghpur. … (व्यवधान)

श्री देवुसिंह चौहान: अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने जो सवाल किया है, मैं यह बताते हुए गर्व महसूस करता हूं कि आज तक हमने नबरंगपुर में 2690 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर ले किया हैं। … (व्यवधान) उनकी करीब 351 जीपीज में से … (व्यवधान) आज फेज-2 तक हमने करीब 199 जीपीज में 131 जीपीज को सर्विस-रेडी किया है और 55 करोड़ रुपये का फण्ड एलोकेट किया है।… (व्यवधान)

डॉ. राजश्री मल्लिक (जगतसिंहपुर): सर, मेरा प्रश्न जगतसिंहपुर जिले के बारे में था।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश चन्द्र माझी ।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नबरंगपुर संसदीय क्षेत्र एक आदिवासी इलाका है और नक्सली इलाका है। … (व्यवधान) वहां बहुत सारे गांवों में आज तक ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंचा है। … (व्यवधान) मेरा प्रश्न है कि कब तक नबरंगपुर कांस्टीट्वेंसी के नबरंगपुर, मलकानगिरी और कोरापुट जिलों की सभी पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर लोगों के पास पहुंचेगा? … (व्यवधान)

श्री देवुसिंह चौहान: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने जगतसिंहपुर जिले के बारे में पूछा था, उनके यहां हमने 1200 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर ले किया है और उनके यहां की 333 जीपीज में से फेज-1 और फेज-2 में हमने करीब 39.77 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।… (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं यह बताने में बहुत गर्व महसूस करता हूं कि आज तक पूरे भारत में करीब 2 लाख 64 हजार 38 जीपीज हैं, उनमें से आज हमने 1 लाख 96 हजार जीपीज को ऑप्टिकल फाइबर से कवर किया है। … (व्यवधान) ऑप्टिकल फाइबर ले करने का काम हम फेजवाइज मैनर में कर रहे हैं। अब फेज-3 चल रहा है। … (व्यवधान) आने वाले दिसम्बर, 2023 से पहले बाकी करीब 2 लाख 66 हजार 650 जीपीज को भी कवर करेंगे और उनमें माननीय सदस्य के क्षेत्र की जीपीज को भी कवर करेंगे।… (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 292)

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार जेनेटिक बीमारियों के नए-नए वैरिएंट्स से निपटने के लिए रिसर्च कर रही है? … (व्यवधान)

(1125/YSH/SPR)

मेरा दूसरा सवाल यह है कि विशेष तौर पर ऐसी जेनेटिक बीमारियां, जो केवल ह्यमुन ट्रेंड के रूप में विकसित होती हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और जेनेटिक बीमारियों के वैश्विक प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने क्या प्रयास किए हैं?… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ… (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, अच्छा रहता कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य भी इस समय इसको ध्यान से सुनते, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य से भी संबंधित है।… (व्यवधान) प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कोविड की आपदा का सामना करते हुए न केवल भारत ने 143 करोड़ की अपनी जनसंख्या को संभाला, बल्कि विश्व के दूसरे देशों को भी कोविड का पहला वैक्सीन इजाद करके उपहार के तौर पर दिया और वही वैक्सीन हमारे विपक्ष के सभी सदस्यों ने भी लगवाई, तभी उसकी संख्या 2.2 बिलियन हो गई। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर उनके लिए भी उतना ही महत्व रखता है, जितना कि दूसरे पक्ष के लिए रखता है।… (व्यवधान)

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है तो इसका सीधा-सीधा उन बीमारियों से ताल्लुक है, जो एनिमल रिसोर्सेज़ से पैथोजन के तौर पर आती हैं जैसे हेमरैजिक फीवर, बर्ड फ्लू, जेपनीज एन्सेफलाइटिस।… (व्यवधान) यह वर्ष 2014 के बाद ही हुआ कि जहां एक ओर प्रधान मंत्री जी ने स्वास्थ्य को उच्चतम प्राथमिकता दी, वहीं स्वास्थ्य का बजट भी बढ़ाया और हमें यह सिखाया कि साइलोज में काम करके हमें पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती है।… (व्यवधान) इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक एप्रोच, होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच, जिसने कोविड में विजय हासिल की और उसी प्रणाली को लेकर के, उसी पद्धति पर चलते हुए आज माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि हम न केवल डब्लयूएचओ के साथ सहयोग कर रहे हैं, बल्कि पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में उनके दिशा-निर्देश पर एक कंसोर्टियम बनाया गया है, जिसमें वेटनरी का विभाग, साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग, स्वास्थ्य का विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट तथा एनिमल हसबेंडरी, सभी सामूहिक तौर पर विचार करेंगे, शोध करेंगे और ऐसे 24 अलग-अलग विभाग रहेंगे, जो एक साथ एक ही प्लेटफार्म से ऑपरेट करेंगे।… (व्यवधान) मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूँ कि कोविड की सफलता के बाद हमारे यहां चार और वैक्सीन्स इस समय ट्रायल स्टेज पर है, जिनका दुनियाभर में स्वागत हो रहा है।… (व्यवधान) एक एन्थ्रेक्स को लेकर है, एक ब्रुसेलोसिस को लेकर है, एक स्वाइन फीवर को लेकर है और लेप्टोस्पाइरोसिस को लेकर है।… (व्यवधान) इन चारों बीमारियों का वैक्सीन पहली बार हिन्दुस्तान से दुनिया को तोहफे के तौर पर मिलेगा और मुझे विश्वास है कि विपक्ष के सदस्य भी उसके लाभार्थी होंगे।… (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 293)

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to state that even if India obtains significant reserves of rare earth minerals, it does not have the technical infrastructure or know-how to commercially utilize them in any meaningful way. I would like to ask the hon. Minister, through you, as to what steps the government is taking in this regard … (*Interruptions*)

In addition to ramping up exploration and mining activities, there is a need to place emphasis on recycling rare earth minerals … (*Interruptions*) Although it is a comparatively lengthy and challenging process, it will surely be cost-effective in the long run as it will reduce the need for mining while maximising the overall utility of existing critical minerals. What steps are being taken by the Government in this regard?

(1130/RAJ/MMN)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, हो सकता है कि उसका औचित्य आठ-नौ साल पहले तक रहा हो।…(व्यवधान) लेकिन सन् 2014 के बाद प्रधान मंत्री जी ने अनेक ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। उसमें आज भारत एटॉमिक एनर्जी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत प्रथम श्रेणी के देशों में आकर खड़ा हो गया है। हमारी प्रगति न केवल उसी स्तर की है, बल्कि हमारे द्वारा किए हुए शोध का लाभ भी वे देश उठाते हैं।…(व्यवधान)

जहां तक इनका कहना है कि पर्याप्त बजट एलोकेशन नही है, तो मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से अंतरिक्ष विभाग को प्रधान मंत्री मोदी जी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए इजाजत दे दी थी, उसी प्रकार से एटॉमिक एनर्जी के विभाग में ज्वाइंट वेंचर के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए सन् 2016 में निर्णय लिया गया।…(व्यवधान) इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री मोदी जी के ही कार्यकाल में वर्ष 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट में संशोधन किया गया।…(व्यवधान) बाइलेटरल एग्रीमेंट्स एंड और बल्क एप्रूवल 10 इंडीजिनस रिएक्टर्स के बारे में एक ही कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया।…(व्यवधान) आज तक ऐसा कभी नहीं हो पाया था।…(व्यवधान)

जहां तक इनका कहना रीइसाइक्लिंग के बारे में है, तो यह एक क्रिटिकल इश्यू है। जिसके ऊपर समय-समय पर संज्ञान लिया जाता है।…(व्यवधान) इसके अतिरिक्त मुझे

यह भी कहने में हर्ष है कि वर्ष 2014 से पहले एक समय था कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों तक सीमित थे। जैसे कि आंध्र प्रदेश, जहां से माननीय सदस्य चुन कर आई हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पश्चिम में महाराष्ट्र और कुछ-कुछ गुजरात में, ये होते थे।...(व्यवधान) आज हमने उनका फैलाव दूसरे प्रदेशों में भी किया है।...(व्यवधान) जहां हम खड़े हैं, इससे 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखपुर नामक स्थान पर हमारा एक नया रिएक्टर इंस्टॉल हो रहा है।...(व्यवधान) इतना ही नहीं, बल्कि प्रधान मंत्री मोदी जी के कार्यकाल में एटॉमिक एनर्जी को इज ऑफ लिविंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी जागरूकता पैदा की गई।...(व्यवधान) चाहे वह एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या सब्जियों और फलों की सेल्फ लाइफ कैसे लंबी की जाए, इनके लिए भी एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से व्यवस्था की गई है। ...(व्यवधान) चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तरीके से क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टाटा मेमोरियल और उसके साथ जितने भी संबंधित अस्पताल हैं, जिनमें से एक का उद्घाटन स्वयं प्रधान मंत्री जी ने पिछले वर्ष मोहाली, चंडीगढ़ के नजदीक किया है।...(व्यवधान) वहां पर आधुनिक किस्म के यंत्र एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से नागरिक हित के लिए इस्तेमाल करने का भी प्रयोग किया गया है।...(व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नम्बर 294, श्री चंद्र शेखर साहू।

…(व्यवधान)

(प्रश्न 294)

श्री चंद्र शेखर साहू (बरहामपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे मूल प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया है। मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका उन्होंने उत्तर दिया है।…(व्यवधान)

सर, मेरा एक स्पेशल प्रश्न था कि अभी यूनियन गवर्नमेंट की जो एसओपी एवं गाइडलाइंस हैं, उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स जरूरी हैं। गाइडलाइंस के अनुसार जिन लोगों को जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था, किसानों को जितना बेनिफिट चाहिए था, उतना उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है।…(व्यवधान)

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये एसओपी में कुछ मॉडिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स करेंगे?…(व्यवधान)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : सर, इसका जवाब देने के लिए मुझे दो मिनट लगेंगे।…(व्यवधान) मैं आपका संरक्षण भी चाहूंगी।…(व्यवधान) आज सुबह जब हमने हाउस शुरू किया, तो हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है।…(व्यवधान) आज क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ भ्रष्टाचार छोड़ो, परिवारवाद छोड़ो एवं तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ो।…(व्यवधान) हमारे यहां अंग्रेजों ने 100 साल शासन किया।…(व्यवधान) इसके बाद आजादी से 75 साल हुए।…(व्यवधान)

उनका सवाल सिल्क से रिलेटेड है।…(व्यवधान) उनका पहला सवाल कपड़ा से संबंधित है।…(व्यवधान) कॉटन का उपयोग स्वदेशी आंदोलन से शुरू हुआ।…(व्यवधान) अब जो सवाल है, वह सिल्क से संबंधित है।…(व्यवधान) पहली बार अंग्रेज यहां सिल्क का कोकून प्लांटेशन के लिए बीज लाए थे।…(व्यवधान) माननीय सदस्य ओडिशा से चुन कर आई हैं।…(व्यवधान) ओडिशा में सिल्क बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के साथ हम उनकी मंजूरी देते हैं।…(व्यवधान) मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और टस्सर सिल्क, अलग-अलग प्रकार की सिल्क है…(व्यवधान) जो पूरे नॉर्थ-ईस्ट, जम्मू एवं ओडिशा जैसे प्रदेशों में होती है।…(व्यवधान) उनकी रॉ मैटेरियल बनाने के लिए सिल्क समग्र-2 योजना बनाई गई है।…(व्यवधान)

(1135/KN/VR)

सिल्क समग्र स्कीम-2 के माध्यम से हमने उनको बताया है कि एक से ज्यादा क्रॉप कैसे ली जाए।…(व्यवधान) क्योंकि सिल्क की जो क्रॉप है, जो ठंडे प्रदेश हैं, वहां एक ही बार होती है।… (व्यवधान) लेकिन उसको बढ़ाकर, जैसे कर्नाटक में एक से ज्यादा क्रॉप हो रही है, केस्टर ऑयल जैसे घर के अंदर सिल्क का कोकून हो जाए, इसमें उनको परिवर्तन करना चाहिए।… (व्यवधान) उन्होंने पूछा है कि थर्ड-पार्टी इवैल्यूएशन के बाद अगर हमें यह सहमति मिलेगी तो हम उनको जरूर यह सुविधा देंगे।… (व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।… (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी

से पूछना चाहता हूं कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का रेशम उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इससे रेशम का उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है तथा किसानों को नुकसान हो सकता है।... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए किसानों को किस तरह की सुविधाएं देने का विचार है? ... (व्यवधान)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : महोदय, मैं पिछले क्वेश्चन में जो बता रही थी, वही चीज इसमें है। कोकून प्लांट के ऊपर होता है, इसके कारण जलवायु और डिजास्टर का उनके ऊपर असर होता है।... (व्यवधान) घर के अंदर कोकून क्या खा सकते हैं, कैसे पत्ते खाते हैं। प्रधान मंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने सोचा था कि उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्लांटेशन होता है, वह मेरे यहां जंगल एरिया में, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां के लोगों को इसकी जानकारी क्यों न मिले।... (व्यवधान) इसके लिए हमने केस्टर बेस स्कीम डेवलप की है। घर के अंदर कीड़े साइंटिफिक तरीके से केस्टर बेस से बनाए जाएं, वहां उनको पत्ते दिए जाएं, उनको समय-समय से निकाला जाए। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जलवायु का उनके ऊपर क्या असर होता है, तो यह सिल्क के उत्पादन की नई टेक्नीक है।... (व्यवधान) चूंकि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हैं और जापान के बाद सैकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन सकते हैं।... (व्यवधान) हमने एक पीएलआई स्कीम बनाई है। उसके माध्यम से जो फैब्रिक बने तथा टेक्नीकल टैक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए समग्र सिल्क स्कीम-2 का भी इसमें उपयोग किया गया है।... (व्यवधान)

(इति)

(Q.295)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 295 – श्री टी. एन. प्रथापन जी।

... (व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।... (व्यवधान)

(इति)

(Q.296)

HON. SPEAKER: Shri Karti P. Chidambaram.

....(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): A Statement is laid on the Table of the House. *....(Interruptions)*

(ends)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 297 – डॉ. हिना विजयकुमार गावीत जी।

… (व्यवधान)

(Q.297)

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।… (व्यवधान) मैं सरकार और मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अमृत भारत योजना के माध्यम से स्टेशन रीडेवलपमेंट का उत्कृष्ट काम किया है।… (व्यवधान) आज भी हमारे कई स्टेशन्स स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में हैं, वहां डिसेबल फ्रेंडली व्यवस्था की आवश्यकता है। कहीं पर रैंप्स की उपलब्धता नहीं है या कहीं पर लिफ्ट ही नहीं है।… (व्यवधान) मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि सरकार द्वारा एक्सेसिबल रेलवे स्टेशन्स बनाने के लिए क्या प्रावधान है? आज देश में कितने रेलवे स्टेशन्स डिसेबल फ्रेंडली बनाए गए हैं? … (व्यवधान) क्या इन स्टेशन्स की सूची में मेरे संसदीय क्षेत्र नन्दुरबार के रेलवे स्टेशन का समावेश है? … (व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में इस साल अमृत भारत योजना के तहत देश भर में 13900 स्टेशन्स का समावेश किया गया है।… (व्यवधान) इन पर 25,040 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और अभी-अभी चार दिन पहले मोदी जी के हाथों से 508 रेलवे स्टेशन्स का शिलान्यास किया गया है।… (व्यवधान) इसकी कैटेगरी है– अमृत भारत स्टेशन, मॉडल स्टेशन और आदर्श स्टेशन। रेल विभाग ने इन स्टेशनों की कैटेगरी बनाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि स्टेशन का जो विकास किया जाता है, वह स्थानीय परिस्थति देखकर और जरूरत के अनुसार किया जाता है।… (व्यवधान)

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।… (व्यवधान) कुछ दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत रीडेवलपमेंट का जो कार्य शुरू हुआ है, जिसमें मेरे लोक सभा के गुना और शिवपुरी को भी शामिल किया गया है।… (व्यवधान)

(1140/VB/SAN)

इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।… (व्यवधान) इसके साथ ही पूरे भारत में जिन 1309 रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट होना है, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले अशोक नगर जिले को भी शामिल किया गया है, जिसको अगले चरण में लिया जाएगा।… (व्यवधान) इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।… (व्यवधान)

गुणा जिला एक आकांक्षी जिला है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या आकांक्षी जिलों में भारतीय रेल द्वारा कोई प्लांट, प्रोजेक्ट या रेलवे कोच फैक्ट्री लगाने की कोई योजना है? … (व्यवधान) गुणा जिले में रेलवे के पास काफी जमीन उपलब्ध है।… (व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल फैक्ट्री लगाना हर साल और हर बार चलने वाली प्रक्रिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितनी क्षमता है, जितनी रेलवे को जरूरत है, उतनी फैक्ट्रियाँ हमारे पास हैं।… (व्यवधान) (इति)

(प्रश्न 298)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 298, श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर।

… (व्यवधान)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।… (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 299)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 299, श्री बिद्युत बरन महतो।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे।

… (व्यवधान)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।… (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 300)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 300, श्रीमती अपराजिता सारंगी।

… (व्यवधान)

SHRI SOM PRAKASH: A Statement is laid on the Table of the House. … (*Interruptions*)

(ends)

QUESTION LIST OVER

(pp.17-50)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अच्छा होता, अगर आप प्रश्नकाल चलाने देते। मैंने आज सभी 20 प्रश्नों को लिया था। मेरी कोशिश होती है कि प्रश्नकाल में सभी बोलें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रश्नकाल जैसे समय पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका दायित्व होना चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सरकार जवाब देना चाहती है, इसलिए आपको प्रश्न करने का मौका दिया गया। आज सभी 20 प्रश्नों को लिया गया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको नारेबाजी करने के लिए भेजा गया है? जनता आपसे जवाब मांगेगी। मैं फिर आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ, यह तरीका ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्नकाल है और इसके तहत आपको सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका मिलता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1143 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/PC/SNT)

1200 बजे लोक सभा बारह बजे पुन: समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय अध्यक्ष :माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष :अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 2, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) संशोधन नियम, 2023 जो 28 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 562(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन की अंतिम परीक्षा) नियम, 2023 जो 19 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 377(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 555(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा नियम, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 556(अ) में प्रकाशित हुए थे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2023 जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2423(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) का.आ. 2409(अ) जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 329(अ) का अतिलंघन किया गया है।

(2) का.आ. 2410(अ) जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील नानपारा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड-271881 में स्थित रुपैडीहा भूमि पत्तन को "एकीकृत जांच चौकी" के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(3) का.आ. 2695(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील करीमगंज, जिला करीमगंज, असम, भारत, पिन कोड-788712 में स्थित सुत्तारकांडी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(4) का.आ. 2696(अ) और 2697(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तहसील सबरूम, जिला दक्षिण त्रिपुरा, त्रिपुरा, भारत, पिन कोड-799145 में स्थित सबरूम भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(5) का.आ. 2698(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील रक्सौल, जिला पूर्वी चम्पारण, बिहार, भारत, पिन कोड-845305 में स्थित रक्सौल भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(6) का.आ. 2699(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील पेट्रापोल, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल, भारत, पिन कोड-743405 में स्थित पेट्रापोल भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(7) का.आ. 2700(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील फारबिसगंज, जिला अररिया, बिहार, भारत, पिन कोड- 854238 में स्थित जोगबनी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(8) का.आ. 2701(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील मोरेह, जिला तेंगानौपाल, मणिपुर, भारत, पिन कोड- 795131 में स्थित मोरेह भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(9) का.आ. 2702(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील डेरा बाबा नानक, जिला गुरदासपुर, पंजाब, भारत, पिन कोड- 143604 में स्थित डेरा बाबा नानक भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(10) का.आ. 2703(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील रामनगर, जिला पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा, भारत, पिन कोड- 799001 में स्थित अगरतला भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(11) का.आ. 2704(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील अटारी, जिला अमृतसर, पंजाब, भारत, पिन कोड- 143108 में स्थित अटारी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - वित्त तथा संचार (2023 का संख्यांक 16) (अनुपालन लेखापरीक्षा) ।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार – स्वदेश दर्शन योजना के बारे में, पर्यटन मंत्रालय (2023 का संख्यांक 17) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 34 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985:-

(i) The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Regulations, 2022 published

in Notification No. F.No. APEDA/PAD/2017-18/000044 in Gazette of India dated 13th June, 2022.

(ii) The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Amendment Regulations, 2022 published in Notification No. F.No. APEDA/PAD/2017-18/000044 in Gazette of India dated 23rd November, 2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (2) of Section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016:-

(i) The Flame-Producing Lighters (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.2986(E) in Gazette of India dated 06th July, 2023.

(ii) The Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressors and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2022 published in Notification No. S.O.5972(E) in Gazette of India dated 21st December, 2022.

(iii) The Insulated Flask, Bottles and Containers for Domestic Use (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3140(E) in Gazette of India dated 14th July, 2023.

(iv) The Refrigerating Appliances (Quality Control) Amendment Order, 2022 published in Notification No. S.O.5850(E) in Gazette of India dated 14th December, 2022.

(v) The Resin treated compressed wood laminated (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3139(E) in Gazette of India dated 14th July, 2023.

(vi) The Safety Glass (Quality Control) Amendment Order, 2023 published in Notification No. S.O.1431(E) in Gazette of India dated 27th March, 2023.

(vii) The Potable Water Bottles (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.2988(E) in Gazette of India dated 6th July, 2023.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item Nos. (ii) and (iv) of (1) above.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 124 की उप-धारा (3) के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2023 जो 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 591(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898:-

(i) The Indian Post Office (2nd Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.382(E) in Gazette of India dated 23rd May, 2023.

(ii) The Indian Post Office (3rd Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.462(E) in Gazette of India dated 28th June, 2023.

(iii) The Indian Post Office (Fourth Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.566 (E) in Gazette of India dated 31st July, 2023.

(2) A copy of the Telecom Regulatory Authority of India Repealing Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. RP-4/16/(24)/2021-QoS. in Gazette of India dated 25th July, 2023, under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 1st August, 2023 adopted the following Motion in regard to the Committee on Public Accounts:-
"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one Member from Rajya Sabha *vice* Shri Sukhendu Sekhar Ray, retiring from the Rajya Sabha on 18th August, 2023, to associate with the Committee on Public Accounts for the remaining period of the term of the Committee and do proceed to elect, in such manner as directed by the Chairman, one Member from among the Members of this House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, Shri Derek O'Brien, Member, Rajya Sabha has been duly elected to the said Committee.'

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 8th August, 2023 agreed without any amendment to the Inter-services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 4th August, 2023."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 8th August, 2023 agreed without any amendment the Indian Institutes of Management to (Amendment) Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 4th August, 2023."

याचिका समिति
49वां से 53वां प्रतिवेदन

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड द्वारा भुगतान जारी करने के अनुरोध के संबंध में श्री उमाकांत मिश्रा के अभ्यावेदन के बारे में 49वां प्रतिवेदन।

(2) पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों की धन वापसी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के कथित मनमाने व्यवहार के संबंध में श्री गौरव कुमार सोनी और अन्य के अभ्यावेदन के बारे में 50वां प्रतिवेदन।

(3) उत्तर-पूर्वी राज्यों, विशेषकर मेघालय और असम में वन भूमि के अतिक्रमण और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री फिलिपसन के अभ्यावेदन के बारे में 51वां प्रतिवेदन।

(4) नवोदय विद्यालय समिति/जवाहर नवोदय विद्यालय (*पूर्ववर्ती* आदर्श विद्यालय) में 1 जनवरी, 2004 से पहले अपनी सेवाएं शुरू करने वाले कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत शामिल किए जाने के अनुरोध के बारे में संसद सदस्यों द्वारा अग्रेषित सर्वश्री योगेंद्र शर्मा, राहुल सिंह, योगेंद्र भक्त, एस. कन्नन, श्रीमती के. मंजुला और अन्य व्यक्तियों/संघों के अभ्यावेदन के बारे में अपने 32वें प्रतिवेदन में याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

(5) पर्यावरणीय विधियों के अनुपालन और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)/तटरक्षक बल के साथ प्रभावी संपर्क के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा विशेषज्ञ कार्मिकों को नियोजित करने की आवश्यकता के बारे में श्री विक्रम के अभ्यावेदन पर याचिका समिति के 39वें प्रतिवेदन में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 53वां प्रतिवेदन।

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
30th and 31st Reports

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Sir, I rise to present the following reports (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation:-

(1) Thirtieth Report on action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Tenth Report (17th Lok Sabha) of the Committee on Subordinate Legislation.

(2) Thirty-first Report on action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fifteenth Report (17th Lok Sabha) of the Committee on Subordinate Legislation.

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING
59th Report

SHRI P. C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT): Sir, I rise to present the Fifty-ninth Report (Hindi and English versions) (Seventeenth LokSabha) of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing (2022-23) on the Subject 'Mission for IntegratedDevelopment of Horticulture (MIDH) – An Appraisal' pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department ofAgriculture and Farmers Welfare).

STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
32nd Report

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Sir, I rise to present the Thirty-second Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2022-2023) on the subject – 'Sugar Industry in India – A Review' pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

(1205/CS/KKD)

STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

Statements

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Sir, I beg to lay on the Table the Final Action Taken Statements (Hindi and English versions) showing action taken by the Government on the recommendations contained inChapter I and final replies in respect of Chapter V of the following Action Taken Reports of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2022-2023):-

(1) Twenty-first Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Thirteenth Report on the subject 'Procurement, Storage and Distribution ofFoodgrains by Food Corporation of India' pertaining to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

(2) Twenty-second Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Eighteenth Report on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

(3) Twenty-third Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Nineteenth Report on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

(4) Twenty-sixth Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Twentieth Report on the subject 'Quality Control Cells (QCCs)' pertaining to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति
24वां प्रतिवेदन

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): महोदय, मैं जल शक्ति मंत्रालय – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
43rd and 44th Reports

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to present the following Reports(Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicalsand Fertilizers (2022-23):-

(1) Forty-third Report on the subject 'Planning for Fertilizers production and Import Policy on fertilizers including GST and import duty thereon' pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

(2) Forty-fourth Report on the subject 'Fertilizer Subsidy Policy and Pricing matters including need to continue Urea Subsidy Scheme' pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति
विवरण

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): महोदय, मैं जल शक्ति मंत्रालय – पेयजल और स्वच्छता विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में सोलहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से मैं, आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम और निवेश तथा लोक आस्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ।

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 336TH, 355TH AND 370TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE -- LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to lay the following statements regarding:-

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 336th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 328th Report ofthe Committee on Demands for Grants (2020-2021) pertainingto the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology.

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 355th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 345th Report ofthe Committee on Demands for Grants (2021-2022) pertainingto the Department of Space.

(3) the status of implementation of the recommendations contained in the 370th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 362nd Report ofthe Committee on Demands for Grants (2022-2023) pertainingto the Department of Space.

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS IN 171ST AND 174TH REPORTS OF STANDING COMMITTEEE ON COMMERCE -- LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay the following statements regarding: -

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 171st Report of the Standing Committee on Commerce on 'Issues Affecting the Indian Tea Industry especially in Darjeeling Region' pertaining to the Ministry of Commerce and Industry.

(2) the status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 174th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 167th Report of the Committee on Demands for Grants (2022-2023) (Demand No. 10) pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

____

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1209 बजे

माननीय अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

Re: Setting up of dedicated MSME Bhawan in Rajkot, Gujarat

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): मैं माननीय एमएसएमई मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ, कि मेरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र - राजकोट, एक प्रमुख औद्योगिकीकृत जिलों में से एक है। राजकोट और इसके उपनगरों में लगभग 85000 से अधिक एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित हैं, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आभूषण, सिरामिक, घड़ी निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के माध्यम से निर्यात-आयात सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राजकोट में एक पूर्ण समर्पित एमएसएमई भवन की स्थापना के लिए सरकार से लंबे समय से मांग चल रही है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा देने और इन व्यवसायियों की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करेगा। एक पूर्णांकित एमएसएमई भवन की स्थापना से न केवल रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों की सुविधा भी मिलेगी। इससे उद्योग क्षेत्र में स्थानीय विकास होगा और स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक ताकत मिलेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय एमएसएमई मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि राजकोट में एक पूर्ण समर्पित एमएसएमई भवन की स्थापना की शीघ्र आदेश करें।

(इति)

Re: Need to accelerate the implementation of Jal Jeevan Mission in Jharkhand

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): मैं सदन का ध्यान झारखंड के एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। झारखंड राज्य सरकार जल जीवन मिशन-हर घर जल योजना के तहत अपनी ग्रामीण आबादी को नल का पानी उपलब्ध कराने में बेहद खराब प्रदर्शन कर रही है। जल, राज्य का विषय है और इसलिए घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल-सम्बन्धी योजनाओं को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की है। जुलाई 2023 तक, झारखंड में केवल 39.02% ग्रामीण परिवारों ने नल कनेक्शन की सूचना दी है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें, तो झारखंड में 37 लाख से ज़्यादा ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन नहीं है। इसकी तुलना में, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में जेजेएम के तहत 100% नल कनेक्शन है। ऐसे समय में जब हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है व विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है, झारखंड राज्य अपनी ग्रामीण आबादी को घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में भी असमर्थ है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि जल जीवन मिशन- हर घर जल योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी करें।

(इति)

Re: Need to set up Counselling Centre and Mental Wellness Centre in Guwahati Parliamentary Constituency

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): आज दुनिया में बढ़ती प्रतियोगिता और भारतीयों की व्यस्त जीवन शैली, चिन्ता का विषय है। यह बच्चे, बुर्जग और जवानों को मानसिक रोगी बना देती है। जीवन जीने की शैली और हर क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिता भी मानसिक रोगी होने का एक कारण है। नेशनल मेंटल हैल्थ सर्वे आफॅ. इंण्डिया के अनुसार इसमें 45 साल के उपर के व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होते है । आँकडों के अनुसार प्रत्येक छठा भारतीय व्यक्ति इससे प्रभावित है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 दर्शाता है कि हमारे देश में ऐसे करीब 22 करोड़ नागरिक हैंए जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए देखभाल और सहायता की आवश्यकता है। इनके अतिरिक्त 70 से 90 फीसद लोग सही समय पर उचित चिकित्सीय सहायता न मिलने कारण डिप्रैशन का शिकार हो गये हैं। अत: मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि ऐसी परिस्थिति से निबटने के लिए हर जिले में काउंसलिंग सेंटर, मेंटल वेलनेस सेंटर बनाये जाऐ व जगह जगह सेमिनारो के माध्यम से जनता को जागरूक बनाये जाऐ व वृहत पैमाने पर अभियान चलाया जाऐ, जिससे मानसिक संतुलन खो रहे नागरिक पुन सामान्य जीवन जी सकें।

(इति)

Re: Need to set up a Vegetable Procurement Centre and provide railway facility for transportation of vegetables in Deoria Parliamentary Constituency

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मेरा संसदीय क्षेत्र देवरिया पूर्ण रूप से ग्रामीण आबादी का क्षेत्र है और कृषि पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और नदी के पानी के कारण फसलो पर भी प्रभाव पड़ता है जिससे वह नष्ट हो जाती है। किसानों में सब्जी बोने की रूचि बड़ी है। किसान बड़ी संख्या में सब्जी बो रहे हैं और फल पैदा कर रहे हैं। लेकिन उनको उचित कीमत भी नहीं मिल पा रही है और कोई संग्रह स्थल ना होने के कारण उसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। इसलिए उनको अपने उत्पादन को औने-पौने भाव मे बेचना पड़ता है या नुकसान सहना पड़ता है। उनका जीवनयापन कठिन हो जाता है। अतः आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि वहाँ के उत्पादन के खरीद का कोई केन्द्र विकसित किया जाये। रेलवे के कई ए.सी. कोच जोड़ कर उनको रेल की सुविधा दी जाए जिससे वह अपने उत्पादन को बड़े शहरो एवं विदेशों में भी भेज सके और उनके जीवन में भी समृद्ध और खुशहाली आ सके।

(इति)

Re: Removal of QCO BIS Certification on Cotton bales

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): भारत सरकार ने कपास गुणवत्ता नियन्त्रण आदेश 2023 लागू किया है। इसके द्वारा कपास की गांठो को बीआईएस में डाल दिया है। महोदय मै सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कपास एक प्राकृतिक रेशा है और विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समय में इसकी कई प्रकार की किस्मे बोई जाती है। हर वर्ष जलवायु और बीज के कारण विशेषताएं बदल जाती है। कपास ईकाईयां केवल किसान की उपज का प्रसंस्करण करती है। जिनिंग ईकाई मानक जिनिंग पद्वतियों को अपना सकती है। कपास की गांठो में निर्दिष्ट बीआइएस मापदंडों को पूरा नहीं होने पर भी इसकी आर्थिक मूल्यों में कोई कमी नहीं आती है। बीआईएस अधिनियम में कहा गया है कि मापदण्ड के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर भारी जुर्माना, गिरफ्तारी जैसी बाते शामिल है। मेरा आपसे आग्रह है कि कपास की गांठो पर क्यूसीओ- बीआईएस के नियम को हटाया जाए।

(इति)

Re: Need to provide stoppage of trains running on Palanpur - Gandhidham Railway Section at Bhabhar Railway Station

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): गुजरात में मेरे निर्वाचन क्षेत्र बनासकांठा से होकर कुछ ट्रेनें चल रही हैं, और पालनपुर-भुज रेलवे ट्रैक पर चलने वाली इन निम्नलिखित ट्रेनों को भाभर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाना चाहिए

1. 12959- बांद्रा - भुज सुपरफास्ट
2. 12960- भुज- बांद्रा सुपरफास्ट
3. 12965- बांद्रा- गांधीधाम सुपरफास्ट
4. 12966- गांधीधाम- बांद्रा सुपरफास्ट
5. 20935 गांधीधाम - इंदौर सुपरफास्ट
6. 20936 इंदौर- गांधीधाम सुपरफास्ट
7. 19575 नाथवाडा अप
8. 19576 नाथवाडा डाउन
9. 20928 भुज - पालनपुर सुपरफास्ट
10. 20927 पालनपुर - भुज सुपरफास्ट
11. 20949 अहमदाबाद - एकतानगर सुपरफास्ट
12. 20948 एकतानगर अहमदाबाद सुपरफास्ट

ये ट्रेनें पालनपुर-गांधीधाम रेलवे लाइन पर भाभर रेलवे स्टेशन से होकर चल रही हैं। भाभर एक बड़ा शहर है जिसकी अपनी नगर पालिका है और यह पूरे भारत से जुड़े महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक है। भाभर के कई लोग अहमदाबाद, पालनपुर, सूरत, मुंबई और कच्छ जिलों में रहते हैं और अक्सर भाभर आते-जाते रहते हैं। भाभर रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन (ऊपर उल्लिखित) को स्टॉपेज नहीं दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से मा. रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि पालनपुर-गांधीधाम रेलवे लाइन से गुजरने वाली उपरोक्त सभी ट्रेनों को भाभर स्टेशन पर रुकने की अनुमति देने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to increase the honorarium of ASHA workers in Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं सदन का ध्यान बिहार राज्य में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटर की समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। हम सभी जानते है कि समाज के गरीब एवं पिछड़े इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा योजना की शुरुआत की गई थी। जैसे कि लोगों को स्वास्थ्य सेवा संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी देना, महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में प्रसव एवं उन्हें परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को टीकाकरण क्लीनिक में लाना तथा स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने जैसे कार्य है। आज राष्ट्रिय स्तर पर मातृ-शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आयी है इसमें आशा कार्यकर्ताओं का योगदान भी सराहनीय रहा है। कोरोना महामारी के दौरान भी आशा कार्यकर्ताओं ने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है। परन्तु इसके एवज में बिहार राज्य में उन्हें सिर्फ 1 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है, जो आज के महंगाई को देखते हुये उचित नहीं है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि महंगाई को देखते हुये आशा कार्यकर्ताओं और फैसलिटेटरों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ उन्हें स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाये।

(इति)

Re: Need to implement Uniform Civil Code in the country

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): एक राष्ट्र एक कानून और एक लोक के आधार पर हर राष्ट्र में एक ही कानून संचालित है। देश में संविधान अलग एवं धार्मिक कानून अलग अलग एक साथ काम करते है। अब बढ़ती आबादी एवं समान अधिकार के आधार पर एक देश एक कानून की आवश्यकता है। इसलिए समान नागरिक संहिता लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निर्देशित है कि राज्य, भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इस संहिता के जरिये समान नागरिक संहिता पर्सनल लॉ बोर्ड के संबंध में धार्मिक भेद-भावों का अंत किया जायेगा तथा सभी नागरिको के लिए एक कानून की वकालत की जाएगी। अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत में समान नागरिक संहिता लागू किया जाना सरकार का दायित्व है जिसका लाभ देश के नागरिकों विशेषकर महिलाओं को मिलेगा एवं भेदभाव समाप्त होगा। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मान. न्यायाधीश, सांसदगण, विधायकगण, भारत के संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। इनका दायित्व है कि वे सभी संविधान का पालन करें एवं समान नागरिक संहिता को लागू करायें। माननीय मंत्री महोदय से देश में समान नागरिक संहिता लागू कराये जाने का अनुरोध है।

(इति)

Re: Problem faced by people due to frequent leakage of poisonous gas from chemical factories set up in Bharuch Parliamentary Constituency

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): गुजरात में मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत अंकलेश्वर पनौती जीआईडीसी के संजौली गांव में इंजीनियरिंग जोन घोषित हुआ था लेकिन वहां इंजीनियरिंग जोन की जगह केमिकल इंडस्ट्री डाल रहे हैं और इस केमिकल इंडस्ट्री से बार-बार खतरनाक गैस लीक होने की घटनाएं घटती रहती है दो-तीन महीने पहले काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था तथा खतरनाक गैस पूरी तरह फैल गई थी। अब ठीक उसी के बगल में इसी तरह की केमिकल फैक्ट्री लगाई गई है। इस फैक्ट्री से भी 13-14 जून को गैस लीकेज हुआ। इस फैक्ट्री से 200-300 मीटर की दूरी पर संजौली गांव स्थित है। इस गांव में एससी/एसटी/ओबीसी और मुसलिम समुदाय के गरीब लोगों के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग 25-30 हजार लोग रहते हैं। इस गैस लीकेज की वजह से सभी लोग प्रभावित हुए हैं एवं उनको सांस लेने में दिक्कत, शरीर में जलन, घबराहट तथा उल्टी होने के कारण भगदड़ मच गई। जब यह हादसा हुआ था, उस समय कंपनी का सारा स्टाफ भाग गया था। अच्छा हुआ कि गांव के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए तथा कंपनी के भागते हुए कर्मचारियों को मौके पर लाकर गैस लीकेज बंद करवाया। मैंने 18 जून को घटनास्थल का दौरा किया तथा वहां के स्थानीय लोगों ने मुझे यह बताया कि यह घटना घटती रहती हैं तथा बचाव के लिए वहां पर कोई भी यंत्र नहीं है। जहरीली गैस के रिसाव से वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है और अधिकांश लोग किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। इसी प्रकार अंकलेश्वर, झगड़िया तथा दहेज जीआईडीसी में आए हुए कारखानों में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं और इन घटनाओं की वजह से श्रमिक, किसान तथा कारखानों के कर्मचारियों को कई तरह का नुकसान पहुंचता है। इंडस्ट्री के विकास से मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु जनता के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इन कारखानों से स्थानीय किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल उचित कदम उठाने की कृपा करें। (इति)

Re: Need to take stringent action against stone-pelters

श्री संजय सेठ (राँची): पहले कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना सुनने और देखने को मिलती थी। अब पत्थरबाजी की घटना पूरे देश में सामान्य हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे देश विरोधी ताकत, राष्ट्रीय स्तर पर पत्थरबाजी का प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। राष्ट्र विरोधी तत्वों के संरक्षण में असामाजिक तत्व प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी कर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। हत्या करते हैं। पत्थरबाजी से प्रशासन और पुलिसकर्मियों को घायल करते हैं। शोभायात्रा के ऊपर पत्थरबाजी करके भी जान-माल का भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यह बड़ी राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। विगत वर्ष की बात करूं तो झारखंड की राजधानी रांची सहित पूरे देश में ऐसी लगभग 100 घटनाएं हुई, जहां सामूहिक रूप से पत्थरबाजी कर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। कई लोगों की जान ली गई, कई लोग गंभीर अवस्था में घायल हो गए। अभी हरियाणा में भी पत्थरबाजी की ऐसी ही घटना हुई। इस मामले की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाए। एक कठोर कानून बनाया जाए, जिसमें पत्थरबाजों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा देने का प्रावधान हो। उनकी संपत्तियां जब्त की जाए और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई उसे नीलाम करके की जाए। (इति)

Re: Need to open Kendriya Vidyalaya in Amreli

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मेरा विषय मेरे संसदीय क्षेत्र में नया केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के सन्दर्भ में है। जिसका प्रस्ताव के०वी०एस० संगठन की ओर से अनुमोदित (Approved), है, परन्तु Challenging Method Committee एवं Public Investment board की मीटिंग न होने के कारण अब तक विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु मंत्रालय की ओर से अंतिम आदेश लंबित है, जिसके कारण विद्यालय के निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है। महोदय, विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अमरेली में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करना अति आवश्यक हो चूका है। उक्त विलम्ब के कारण विद्यार्थियों का पठन-पाठन कार्य प्रभावित ना हो इसके लिए K.V.S रीजनल कार्यालय द्वारा अमरेली में स्थित एक भवन में अस्थाई रूप से केंद्रीय विद्यालय का शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव भी K.V.S. मुख्यालय के समक्ष स्वीकृति हेतु भेजा गया है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है की जल्द से जल्द आपके मंत्रालय की ओर से Challenging Method Committee एवं Public Investment board की मीटिंग बुलाई जाए, जिससे उक्त दोनों प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी प्राप्त हो सके।

(इति)

Re: Need to open a Sainik School in Farrukhabad Parliamentary Constituency

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): सरकार ने देश भर में 100 नये सैनिक स्कूल खोलने का संकल्प लिया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा निति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उन्हें सैन्य वलों में शामिल होनें हेतु बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना हेतु मंजूरी भी दे दी गयी है। मैं देश के रक्षा मंत्री जी निवेदन करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में भी एक सैनिक स्कूल खुलवानें का कष्ट करें। महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र में दो बड़े रेजीमेंट्स सेंटर भी हैं। एक राजपूत रेजीमेंट सेंटर और सिखलाई रेजीमेंट सेंटर जहाँ से निकले कई वीरों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान तक न्योछावर कर दी है। मेरे संसदीय क्षेत्र के एक युवा सिपाही श्री अलोक दुबे जी को उनके पराक्रम और साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया है। यदि मेरे संसदीय क्षेत्र में सैनिक स्कूल खुल जाता है, तो क्षेत्र के होन-हार युवाओं को सैन्य अध्ययन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा एवं दलित, शोषित, गरीब युवाओं को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा।

(इति)

Re: Need to ensure transfer of funds to bank accounts of beneficiaries under PM Awas Yojana in Bargarh Parliamentary Constituency

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): In the District Level Consultative Committee meetings of Bargarh district in Odisha, it is learnt that in some cases of every Nationalized Banks, funds disbursed by direct benefit transfer under PM AWAS YOJANA into the SB Accounts of the beneficiaries are being automatically transferred to their NPA Loan Accounts as both are inter linked. The local Bank officials are showing their inability to allow the withdrawal by the beneficiaries as there is no credit in favour of the beneficiary in the Saving Account due to central reversal of funds into the Loan Account of the beneficiary concerned. In such cases, the beneficiaries are unable to start the construction of PM AWAS allotted to them and are not eligible to get further disbursement of the sanctioned fund for the next phase. Thus, the most ambitious scheme of Hon'ble PM to provide every eligible household a pucca house is not being realised. Therefore, I request the Hon'ble Finance Minister to instruct the Banks to develop a system to ensure that the funds allotted for PM AWAS Yojana are not adjusted with the loan default of the beneficiaries and facilitate them for construction of their houses under the PM AWAS Yojana.

(ends)

Re: Need to resume the operation of train Nos. 14213/14214 running between Bahraich and Banaras

श्री अक्षयवर लाल (बहराइच): मेरे संसदीय क्षेत्र बहराइच, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा ट्रेन सं0-14213 बनारस- बहराइच इंटरसिटी एक्स० एवं ट्रेन सं०-14214 बहराइच-बनारस इंटरसिटी एक्स० का संचालन दिनाँक 23 अगस्त, 2022 को मेरे साथ हजारों लोगों की संख्या में हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया था। उपरोक्त ट्रेन चलने से जनपद-बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, बनारस की लाखों जनता को इसका लाभ मिल रहा था। उपरोक्त ट्रेन को बन्द कर दिया गया था, जिसका संचालन पुनः दिनाँक 16 नवंबर, 2022 को प्रारम्भ किया गया था। पुनः उपरोक्त ट्रेन को दिनाँक 01 दिसम्बर, 2022 से 28 फरवरी, 2023 और पुनः 28 अप्रैल, 2023 तक और फिर 29 मई, 2023 तक ट्रेन का संचालन रेलवे विभाग द्वारा बन्द करने की सूचना दी गई है, जो जनहित में नहीं है। इससे वहाँ की आम जनता को आवागमन हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त ट्रेन के संचालन बन्द हो जाने से जन मानस में भारी आक्रोष है। अतः मा० रेल मंत्री, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जनहित में ट्रेन सं0-14213 बनारस- बहराइच इंटरसिटी एक्स० एवं ट्रेन सं०14214 बहराइच-बनारस इंटरसिटी एक्स० की सेवा अतिशीघ्र पुनः बहाल कराए जाने की कृपा करें।

(इति)

Re: Construction of Sidhi - Singrauli Section of NH-39

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): NH-39 हमारे संसदीय क्षेत्र के सीधी व सिंगरौली के बीच के भाग को फोर लेन बनाने का टेण्डर वर्ष 2011-12 में हुआ था, किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगभग 11 वर्ष से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं होती है, जिससे कई जाने भी जा चुकी हैं और निरतंर यह सिलसिला जारी है। मैं माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि NH-39 के सिंगरौली से सीधी के बीच के मार्ग को बनने में अभी और कितना समय लगेगा। नये संविदाकार ने अभी तक कितना कार्य किया है और अभी कितना कार्य किया जाना शेष है? साथ ही माननीय सड़क परिवहन मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस NH1-39 मार्ग के शीघ्र निर्माण हेतु विशेष मानीटरिंग टीम बनाकर कार्य कराये, जो प्रतिमाह निर्माण कार्य का लक्ष्य बनाये और निगरानी करते हुये इस मार्ग का निर्माण समय पर पूर्ण कराये।

(इति)

Re: Grant of permission for immediate functioning of Kendriya Vidyalaya, Kottarakkara

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The development and operation of new Kendriya Vidyalaya in Kottarakkara, Kollam district, Kerala is neglected even after transfer to five acres of land to the Kendriya Vidyalaya Sangathan by the State Government and temporary accommodation has been handed over, and Regional Commission of Kendriya Vidyalaya have inspected the site alongwith Central PWD officials as per rules. It has been about a decade since the people of Kottarakkara taluk, which is a part of Mavelikkara Lok Sabha Constituency, are waiting for the functioning of this institution, that will provide an impetus to the educational requirements of Kottarakkara taluk and nearby areas in need of affordable and quality education. I would urge the Union Ministry of Education to accord all necessary permissions for immediate functioning of the Kendriya Vidyalaya, Kottarakkara, on priority so that students from the region can avail the services and gain from quality tutelage at the earliest. Any delay in this matter is an injustice to the students desirous of availing affordable education as Kendriya Vidyalayas offer quality learning and open up a world of opportunities for students from varied backgrounds and address opportunity gaps.

(ends)

Re: Problems faced by the weaving industry in Tamil Nadu

SHRI S. JAGATHRAKSHAKAN (ARAKKONAM): Though India is the World's largest Producer of cotton, due to loss of jobs of more than 80000 power loom and handloom workers in the constituency of Arokkonam, the weaving industry is facing long drawn Recession. In order to save the handloom industry in Tamil Nadu, levy of GST should be banned, Rebate should be given for yarn fabrics, welfare measures for handloom weavers such as, pension, free power supply, technology up gradation in weaving industry, establishment of Textile Park at Tirutani etc. are to be initiated. Rise in prices of cotton hank yarn seriously affects the production of handloom industry. Handloom weavers are unable to generate demand in domestic and global markets. To save the handloom Industry, exemption from GST, reduction of yarn prices, strengthening of Weaver's Cooperative Societies, timely payment to handloom weavers, export promotion activities etc. are to be taken up on war footing. I would like to know about the remedial actions being planned to sustain the handloom and power loom workers and to save the weaving industry in Tamil Nadu.

(ends)

Re: Need to strengthen extradition treaties with other countries to bring to book fugitive economic offenders

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): India recently called upon G20 countries to adopt multilateral action for faster extradition of fugitive economic offenders and recovery of assets both on the domestic front as well as from abroad. Fugitive economic offenders are individuals who have fled their home country to avoid facing prosecution for financial crimes such as money laundering, fraud, and embezzlement. These individuals typically engage in illegal activities that involve large sums of money and often cause significant damage to the economy of the country they have fled. As per the Central Bureau of Investigation (CBI), 08 absconders/proclaimed offenders in 08 cases registered by CBI reportedly left India during 2018-19 itself and such numbers have grown since then - as revealed through the reply provided to Unstarred Question Number 3604 of 2020. Therefore, there is a need develop and strengthen extradition treaties with other countries to ensure that Fugitive Economic Offenders (FEO) are not able to evade justice by fleeing to other countries, while enhancing cooperation with International Organizations to facilitate the sharing of information and intelligence about FEOS. (ends)

Re: Need to investigate the issue of bogus GST notices in Ratnagiri - Sindhudurg Parliamentary Constituency

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): मेरे संसदीय क्षेत्र रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में कर प्रणाली में भ्रम को कम करने की सरकार के प्रयासों को कथित रूप से कमजोर करने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार के वस्तु एवं सेवा कर कार्यालय के अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों की नकल करके नकली जीएसटी नोटिस कथित रूप से लोगों को भेजे जा रहे हैं। यह गंभीर अपराध है एवं सरकार के लिए खुली चुनौती है। इसमें कुछ बिल्डर, बैंकर और सीए भी शामिल हो सकते हैं, यह जांच का विषय है। इसमें जांच और कार्रवाई में देरी हो रही है। घोटालेबाजों को मदद पहुंचाने के लिए ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। ऐसे नोटिसों के माध्यम से सैकड़ों लोगों को धोखा दिया जा रहा है, इनकी आवाज उठाने और सरकारी विभागों में संदिग्ध आचरण के कारण शिकायतकर्ता की जान को भी खतरा है। पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह इस पर ध्यान दे और शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करे। अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। (इति)

Re: Grant of incentives to the energy sector in Odisha

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Odisha's huge Renewable Energy potential is about 1.5 lakh MW Solar Power which is six times more than the assessment of Ministry of New and Renewable Energy. A survey conducted by international forum for Environment, Sustainability and Technology, revealed that Odisha has huge renewable energy potential. By utilizing only 2% of wasteland, Odisha can install over 170 Gigawatts of solar capacity. The forum in its report 'Odisha Renewable Energy Potential Re-assessment: Focus on Solar, Wind and Biomass' stated that if the Odisha Renewable Energy Policy (OREP) 2022, is implemented fully, it will be a win-win situation for the state as it will also help reducing carbon emission from the utility power in the state by 29 to 30% by 2029-30, putting the state on the path of net-zero target. Report has clear indication of enough potential in the state to achieve sustainability in energy sector and to achieve goals of OREP 2022 and also SDG commitments of Government. Therefore, I would urge upon the Hon'ble Minister to take concrete steps in terms of providing incentives to enable energy sector in Odisha particularly coastal areas like Berhampur to further untap its potential and help it emerge as a leading player in Renewable Energy Sector.

(ends)

Re: Need to complete the Storm Water Drainage Project in Vijayawada

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): The Union Government has sanctioned Rs. 461 crores in 2016 for the Storm Water Drainage project in Vijayawada, only about 60% of the project has been completed, and in many places, the works have been abandoned in midway. As monsoons come and go, the people of Vijayawada face the fury of floods at this time every year. With heavy rains lashing the city in the last few days, residential colonies and main roads were waterlogged creating inconvenience for motorists and pedestrians. A stormwater management system is necessary for collecting and draining excess rainwater in public places that would otherwise remain stagnant, putting the health and well-being of citizens at risk. Part of the project is also to cover all the open drains in the city. As this problem persists, we can expect more fatalities due to accidental drowning which could have been avoided with concerted action on the project. I urge upon the Ministry of Housing and Urban Affairs to conduct a comprehensive review of the utilization of allocated funds and take the necessary steps to support the Vijayawada Municipal Corporation in resolving any administrative, technical, or contractual issues hindering the project.

(ends)

Re: Plight of daily wage workers in Jammu & Kashmir

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): I rise to bring to your notice the plight of more than 60 thousand Contractual workers, Contingent Paid Workers (CPW), HDF (Hospital Development Fund) workers, ad-hoc workers, CIC operators, Home Guards, Teachers of Tribal Seasons Schools, zonal coordinators under Samagra Shiksha and Contractual Lecturers Health Workers & Asha workers. They have been sweating hard for decades in various departments of Jammu & Kashmir. These workers are hired on need basis by Departments like; Jal Shakti, Power development, Health and Education, Rural Development & Panchayati Raj etc and are paid meagre wages. Their constant protests over the last several months have remained unheard. They are demanding regularization and an increase in their salaries in accordance with the Minimum Wages Act. The local response has been highly ineffective, where demands and well-being of our workers have not been heard. Therefore, I strongly urge upon the Government to address the grievances of the daily wage workers by fast-tracking their regularization by fixing a reasonable time frame for their regularization, absorbing them as permanent employees in the department and issuing orders for their wages as per Minimum Wages Act.

(ends)

Re: Need to take strong action for crime against women and children

KUMARI AGATHA K. SANGMA (TURA): I am scared by the data provided by National Crime Record Bureau (NCRB) which shows that 13.13 lakh girls and women went missing in the country in the three years between 2019 and 2021. Total 10,61,648 women above 18 years and 2,51,430 girls below 18 years went missing between 2019 and 2021 across the country. As per data compiled by NCRB and tabled in Parliament last week, 1,60,180 women and 38,234 girls went missing between 2019 and 2021 in Madhya Pradesh; 1,56,905 women and 36,606 girls from West Bengal; Maharashtra, 1,78,400 women and 13,033 girls; in Odisha, 70,222 women and 16,649 girls and in the National Capital, 61,054 women and 22,919 girls went missing during the period. Crime against women and children are. rapidly increasing in the country and undoubtedly, we are dealing with something which is of unprecedented magnitude, namely crimes and perpetuation of violence against women in a situation of communal or sectarian strife of a nature which has taken place in Manipur. It is time for the Government to take strong actions against the culprits.

(ends)

Re: Need to regulate sale and purchase of Jan Aushadi medicines through online platform

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): I thank the Government in helping citizens of Bengaluru South save over Rs 5 crore through the 110 PMBJK stores set up in the city - the highest for any Parliamentary constituency or city in the country. The PMBJP is also helping citizens across the country save Rs 20,000 crore in their medicinal purchases. However, it is noted that certain online platforms and several PMBJK owners are selling the generic medicines available only in Jan Aushadhi Kendras through online platforms. Websites like janaushadhistore.in, janaushadhistore.online and several other such websites are openly selling Jan Aushadhi medicines online, without any license or permit. The current guidelines do not permit the sale of Jan Aushadhi medicines through websites, WhatsApp or any digital platform. For this reason, I request the Government to crack down on such illegal platforms. I also request that the Government work on releasing guidelines or policy changes in the future which can regulate the sale and purchase of Jan Aushadhi medicines through online platforms - this will increase the availability and consumption of low-cost, reliable medicines.

(ends)

Re: A policy for recycling of waste tyres

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Pollution and climate change is killing more life than we acknowledge. Among the unending source of pollution, one of the most neglected yet disastrous is tyre-burning. As per data provided for NGT case, India discards roughly 275000 tyres each year, but doesn't have comprehensive plan for them. Over and above it, about 3 million waste tyres are imported for recycling. The NGT had on September 19, 2019 in a case related to the absence of proper management of End-of-Life Tyres/Waste Tyres (ELTS) directed the Central Pollution Control Board to come up with a comprehensive waste management plan for the waste tyres and their recycling. In the name of pyrolysis, the industry in India produces inferior quality products that are to be banned with immediate effect to prevent environmental damage and highly carcinogenic pollutants. The producers and the recyclers of waste tyres must be made responsible for proper recycling instead of mere burning. The draft Extended Producer Responsibility notifies the manufactures to take responsibility of recycling the waste matter. But this is not enough. Need of the hour is to take stern steps which will yield faster result. Every minute delay is costing thousands of lives. Thus, the Government must look into the matter and come up with a policy to solve the problem at the earliest.

(ends)

Re: Need to declare Azamgah district in Uttar Pradesh as drought-hit and redress the grievances of farmers of Lalganj Parliamentary Constituency

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): मेरे जनपद आज़मगढ़ में इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण आज़मगढ़ को सूखा ग्रस्त घोषित किया जाए और नहरों में पानी औसतन कम छोड़ा गया है, उसे मांग अनुसार छोड़ा जाए ताकि धान की बोआई में कमी को पूरा किया जा सके। बिजली की कटौती भी अधिक हो रही है। १८-२० घंटे आपूर्ति बहाल की जाए और ट्रांसफार्मर भी काफ़ी संख्या में भी जल रहे है, जो १०-१५ दिन बाद बदले जाते हैं, उसे २४ घंटे के अंदर तत्काल लगा दिया जाए और आवश्यकता अनुसार क्षमता वृद्धि भी कर दी जाए। इसके अलावा किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर ४००० रूपए कर दिया जाए। इसके साथ ही जनपद आज़मगढ़ में मंदूरी हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में किसान भूमि अधिग्रहण के विरोध में कई महीनों से आन्दोलत्रत्न है। मेरी आपसे माँग है कि शासन-प्रशासन तथा किसानों से वार्ता कर उनकी यथा उचित मांगो को स्वीकार किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज के विधानसभा फूलपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। किसान उससे आंदोलित है क्योंकि उनको किसानों की ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। मेरी सरकार से माँग है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करके किसानों से वार्ता कर किसानों की माँग के अनुसार उचित मुआवज़ा दिया जाए।

(इति)

Re: Need to declare Eastern Rajasthan Canal Project as a national Project

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): मैं प्रधानमंत्री जी और जलशक्ति मंत्री का ध्यान राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल तथा सिंचाई से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की तरफ आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि ईआरसीपी के माध्यम से राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर जिले में राहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा वर्तमान विधमान सिंचित क्षेत्र का कायाकल्प करने व 2 लाख हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय जल आयोग ने दिल्ली द्वारा इस परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 6 अक्टूबर 2016 को दी है क्योंकि यह पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए जीवन दायिनी परियोजना है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए यदि किसी निर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार से प्रस्ताव लेने की आवश्यकता है तो स्वयं केंद्र इसमें पहल करके जनहित में यह प्रस्ताव मंगवाए क्योंकि किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। राजस्थान की जनता लंबे समय से यह मांग भी कर रही है तथा इस विषय पर मेरा यह भी आग्रह है कि राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य पानी को लेकर कोई विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसका समाधान भी जनहित में केंद्र सरकार को आगे जाकर करने की जरूरत है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें मानसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, काली, सिंध तथा मेज नदी के अधिशेष पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती व काली सिंध नदियों में पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि बिना किसी भेदभाव के केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ईआरसीपी को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करना चाहिए।

(इति)

(1210/IND/AK)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर-24, श्री राहुल गांधी जी।

मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव – जारी

1210 बजे

श्री राहुल गांधी (वायनाड) : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोक सभा में रिइनस्टेट किया। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने बहुत जोरों से अदानी जी पर फोकस किया। शायद ... (*Expunged as ordered by the Chair*) जो सीनियर नेता हैं, उन्हें थोड़ा कष्ट हुआ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप विषय पर बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड) : अध्यक्ष जी, उन्हें जो कष्ट हुआ, उसका असर शायद थोड़ा ... (*Expunged as ordered by the Chair*) पर भी हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। आज मेरे जो बीजेपी के मित्र हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा भाषण... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आज मैं अपना भाषण अदानी जी पर नहीं बोलने जा रहा हूं। आप रिलेक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था – जो शब्द दिल से आते हैं, वे शब्द दिल में जाते हैं। आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, आज मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं।... (व्यवधान) मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब एक-दो गोले जरूर मारूंगा, लेकिन इतना नहीं मारूंगा, इसलिए आप रिलेक्स कर सकते हैं।... (व्यवधान) महोदय, पिछले साल 130 दिनों के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ गया।... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): महोदय, ये हमारा टाइम खराब करने की साजिश है।... (व्यवधान)

(1215/RV/UB)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़, ऐसे धमकाने वाले वाक्य यहां न बोलें।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड) : महोदय, मैं समुद्र के तट से लेकर कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों तक चला।... (व्यवधान) मैंने लद्दाख को नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और हम जरूर लद्दाख आएंगे। आप मत घबराइए। यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि राहुल, तुम क्यों चल रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो? जब वे मुझसे पूछते थे तो शुरुआत में मेरे मुँह से कोई जवाब नहीं निकलता था, शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने यह यात्रा क्यों शुरू की। जब मैंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू किया तो मैं सोच रहा था कि मैं हिन्दुस्तान को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लोगों के बीच जाना चाहता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी ही देर में मुझे बात समझ में आने लगी। जिस चीज़ से मुझे प्यार था, जिस चीज़ के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज़ के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, जिस

चीज़ के लिए मैंने दस साल हर रोज गाली खायी, उस चीज़ को मैं समझना चाहता था कि यह क्या है जिसने मेरे दिल को इतनी मजबूती के साथ पकड़ रखा था।

शुरुआत में, जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज आठ-दस किलोमीटर दौड़ता हूं तो मेरे दिमाग में यह था कि अगर मैं दस किलोमीटर रोज दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने में क्या है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को अगर देखूं तो वह अहंकार था कि मैं यह कर सकता हूं, यह कुछ नहीं है। मेरे दिल में उस समय अहंकार था। मगर, भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, एक सेकेन्ड में मिटा देता है। उसके बाद यह हुआ कि दो-तीन दिनों में ही मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया। पुरानी इन्जुरी थी। जबर्दस्त दर्द था। हर रोज जब मैं उठूं तो मेरे घुटने में दर्द था, हर कदम में दर्द था। पहले दो-तीन दिनों में जो अहंकार था, मतलब भेड़िया, जो निकला था, वह एकदम चींटी बन गया।

(1220/GG/SRG)

जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वह पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया और रोज़ मैं डर-डर कर चलूं कि क्या मैं कल चल पाऊंगा? मेरे दिल में यह डर था और जब भी यह डर बढ़ता था, कहीं न कहीं से कोई न कोई शक्ति मेरी मदद करती थी। एक दिन मैं सह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिट्ठी देती है। वह आठ साल की लड़की थी। मैंने चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था कि “I am walking with you. Do not worry.” उसने मेरे पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ति मुझे दे दी। … (व्यवधान) सिर्फ उसने ही नहीं, लाखों लोगों ने दी। … (व्यवधान) शुरूआत में जब मैं चल रहा था, तब कोई किसान आता था, मैं एकदम पहले उसको अपनी बात बताता था कि आपको यह करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। मगर इतने लोग आए, हज़ारों लोग आए कि थोड़ी देर मैं बोल नहीं पाया। जो मेरे दिल में बोलने का डिज़ायर था, वह बंद हो गया। बोल ही नहीं पाया क्योंकि इतने लोगों से बोलना था और एक सन्नाटा सा छा गया। भीड़ की आवाज़ थी – भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जो मुझसे बात करता था, उसकी आवाज़ मैं सुनता गया। हर रोज़ सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक, आम आदमी, गरीब, अमीर, बिज़नमैन, किसान, मज़दूर सबकी आवाज़ थी। … (व्यवधान)

आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आप कल से रुके हुए हो अब थोड़ा और रुक लो, 5-10 मिनट रुक जाओ। … (व्यवधान) तो यह चलता गया, मैं बात सुनता गया फिर मेरे पास एक किसान आया और उस किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मेरी आँख में देख कर मुझे रुई का बंडल दिया और कहा कि राहुल जी, मेरे खेत का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। … (व्यवधान) मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, मैंने उससे पूछा कि भईया! आपको बीमा का पैसा मिला? तब किसान ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वह मुझसे छीन लिया। मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज़ हुई कि जब मैंने किसान को देखा और वह मुझसे बोल रहा था, तब उसके दिल में जो दर्द था, वह मेरे दिल में आया।

(1225/MY/RCP)

जब वह अपनी बीबी से बात करता था, उसकी आँखों में जो शर्म थी, वह शर्म मेरे आँखों में आई। … (व्यवधान) उसकी जो भूख थी, वह मुझे समझ आई और उसके बाद यात्रा बिल्कुल बदल गई। … (व्यवधान) मुझे भीड़ की आवाज सुनाई नहीं देती थी। मुझे सिर्फ उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती थी, जो मेरे साथ बात कर रहा था। उसका दर्द, उसकी चोट, उसका दुख, मेरा दुख, मेरी चोट, मेरा दर्द बन गया। … (व्यवधान) भाइयो और बहनों, लोग कहते हैं कि यह देश है। … (व्यवधान) कोई कहता है कि यहां अलग-अलग भाषाएं हैं। कोई कहता है कि यह जमीन है, मिट्टी है। … (व्यवधान) कोई कहता है कि यह धर्म है, यह सोना है, यह चाँदी है। … (व्यवधान)

मगर, भाइयो और बहनों, यह सच्चाई है कि यह देश एक आवाज है। यह देश सिर्फ एक आवाज है। यह देश यहाँ के लोगों की आवाज है। … (व्यवधान) इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयाँ हैं। अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपनें हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपने को परे करते हैं, तब हमें हिन्दुस्तान की आवाज सुनाई देती है। … (व्यवधान) तब तक हिन्दुस्तान की आवाज हमें सुनाई नहीं देती है। अब आप कहेंगे कि यह बात मैंने नॉन कंफिडेंस मोशन में क्यों रखी? … (व्यवधान) इसका क्या मतलब हैं कि भारत एक आवाज है, भारत के लोगों का दुख है, भारत के लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं। … (व्यवधान)

स्पीकर सर, भारत एक आवाज है। भारत, इस देश के सब लोगों की आवाज है। अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं तो हमें अहंकार, नफरत को मिटाना पड़ेगा।

स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आजतक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिन्दुस्तान नहीं है। … (व्यवधान) मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भागों में कर दिया है। मणिपुर को आपने बाँट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर के रिलीफ कैम्प्स में गया। … (व्यवधान) आज जा रहा हूं। … (व्यवधान)

(1230/CP/PS)

मैंने मणिपुर में रिलीफ कैंप में महिलाओं से बात की। …(व्यवधान) मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधान मंत्री जी ने आज तक नहीं की। एक महिला से मैंने पूछा कि बहन, आपके साथ क्या हुआ?…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): एक-एक मंत्री बोल रहे हैं। … (व्यवधान) एक-एक मंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं।…(व्यवधान) एक-एक मंत्री खड़े होंगे, तो हमारे सांसद यहां पर खड़े होंगे?…(व्यवधान) कल केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा होगा।…(व्यवधान) पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा।…(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड): मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? …(व्यवधान) वह कहती है कि मेरा छोटा सा बेटा था। मेरा एक ही बच्चा था। मेरी आंखों के सामने उसको गोली मारी।…(व्यवधान) आप अपने बेटों के बारे में सोचिए। उसने कहा, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही।…(व्यवधान) झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हैं, झूठ मैं नहीं बोलता हूं।…(व्यवधान) मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही।…(व्यवधान) फिर मुझे डर

लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया।…(व्यवधान) जो भी मेरे पास था, वह मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कि कुछ तो लाई होगी? वह कहती है कि नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं, ये मेरे पास हैं। फिर वह इधर-उधर ढूंढती है, एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है कि यही अब मेरे पास बची है।…(व्यवधान) एक और उदाहरण दूसरे कैंप का है। एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? …(व्यवधान) जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): आप महिलाओं का दर्द नहीं सुन सकते।…(व्यवधान) महिलाओं का दर्द सुनने का आपके पास धैर्य नहीं है।…(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड): जैसे ही मैंने उससे यह सवाल पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही एक सेकेंड में वह कांपने लगी।…(व्यवधान) उसने अपने दिमाग में वह दृश्य देखा और बेहोश हो गई। वह मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई।…(व्यवधान) मैंने आपको ये सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं।

(1235/NK/SMN)

स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) की है।…(व्यवधान) सिर्फ मणिपुर की ही नहीं, हिन्दुस्तान की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिन्दुस्तान को मणिपुर में मारा है।… (व्यवधान) हिन्दुस्तान का ... (*Expunged as ordered by the Chair*) किया है, हिन्दुस्तान का ... (*Expunged as ordered by the Chair*) मणिपुर में किया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि शांति रखें। प्लीज शांत हो जाइए।

… (व्यवधान)

1236 बजे

(इस समय श्री सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री टी. एन. प्रथापन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी ने आज जो बातें इस सदन में कही हैं। … (व्यवधान)। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। … (व्यवधान) सात दशक तक लोगों को नार्थ ईस्ट में … (व्यवधान) इसका जिम्मेदार कौन है? … (व्यवधान) इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। … (व्यवधान) राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों से ज्यादा समय तक इस देश पर शासन किया है। … (व्यवधान) इन्होंने नार्थ ईस्ट का ... (*Expunged as ordered by the Chair*) किया है। … (व्यवधान) आज नार्थ ईस्ट में जो मिलिटेंसी है उसे कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। … (व्यवधान)। आज नार्थ ईस्ट की सारी जनता मिलिटेंट हो गई, कांग्रेस पार्टी की वजह से मिलिटेंसी का जन्म हुआ है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप भाषण नहीं सुनना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप भाषण नहीं सुनना चाहते हैं, प्लीज बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज बालू जी, बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। यह तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को बोलने के लिए कहा है तो कहा है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसे सदन नहीं चलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो यह अलग बात है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने अपनी बात कही है, यह गलत तरीका है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसे सदन चलने वाला नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य टेबल पर आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं, यह तरीका उचित नहीं है कि आप टेबल पर आएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह गलत तरीका है।

… (व्यवधान)

(1240/SK/RU)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड): जैसे मैंने भाषण की शुरूआत में बोला, भारत एक आवाज़ है, भारत हमारी जनता की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है, उस आवाज़ की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) आपने मणिपुर में की। … (व्यवधान) आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) की है। … (व्यवधान) आप ... (*Expunged as ordered by the Chair*) हो … (व्यवधान) आप देशभक्त नहीं हो … (व्यवधान) आप देशप्रेमी नहीं हो … (व्यवधान) आप ... (*Expunged as ordered by the Chair*) हो, आपने देश की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) मणिपुर में की। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठना चाहते हैं या नहीं?

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड): अब सवाल उठता है … (व्यवधान) इसीलिए आपके ... (*Expunged as ordered by the Chair*) मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मणिपुर में देश की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) की है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड): मणिपुर में हिंदुस्तान की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) की है। … (व्यवधान) मणिपुर में भारत माता की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) की है, मणिपुर के लोगों के दिल में … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, आप बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, आप भी विराजें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए तो सही।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: फिर आप ही बोल लें।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड): आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, … (व्यवधान) आप भारत माता के ... (*Expunged as ordered by the Chair*) हो।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, भारत मां हमारी मां हैं, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड): मैं अपनी मां की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) की बात कर रहा हूं। … (व्यवधान) मैं मणिपुर में अपनी मां की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) की बात कर रहा हूं। … (व्यवधान) मैं आदर से बोल रहा हूं, आपने मेरी मां की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) मणिपुर में की है। … (व्यवधान) एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। … (व्यवधान) जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) हर रोज़ कर रहे हो। … (व्यवधान) हिंदुस्तान

की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। … (व्यवधान) अगर नरेन्द्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज़ नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज़ नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज़ सुनते हैं? दो लोगों की। … (व्यवधान) दो लोगों की आवाज़ सुनते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड) : इसकी आवाज़ सुनते हैं, … (व्यवधान) इसकी आवाज़ सुनते हैं, … (व्यवधान) और इसलिए सुनते हैं … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह गलत तरीका है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका यह गलत तरीका है।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड): देख लीजिए, अडाणी जी के लिए मोदी जी ने क्या प्लान किया है… (व्यवधान) देख लीजिए, यह पहले और यह बाद में। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पोस्टर लेकर आए हैं, आपका यह गलत तरीका है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं। आप इस तरह का व्यवहार सदन में मत कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बात कीजिए लेकिन पोस्टर लाना किसी तरीके से उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड): … (*Expunged as ordered by the Chair*) भाइयो और बहनो, लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। … (व्यवधान)

(1245/KDS/SM)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आप संयमित बोलें। यह सदन है, इसलिए आप तरीके से बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (वायनाड) : राम ने रावण को नहीं मारा था, बल्कि रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। … (व्यवधान) आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हैं। … (व्यवधान) आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। … (व्यवधान) अब आप हरियाणा में कर रहे हैं। … (व्यवधान) पूरे देश को आप जलाने में लगे हुए हैं। … (व्यवधान) पूरे देश में आप भारत माता की **…** (*Expunged as ordered by the Chair*) कर रहे हैं। … (व्यवधान) धन्यवाद। (इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन में किस तरह से बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह सदन है। आप लोग प्लीज बैठिए।

… (व्यवधान)

1246 hours

महिला और बाल विकास मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है। … (व्यवधान) अगर सदन, विशेषत: विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखें, तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। You are not India; for, India is not corrupt… (*Interruptions*) India believes in merit and not in dynasty… (*Interruptions*) Today, of all the day, people like you need to remember what was called to the British, "Quit India"… (*Interruptions*) Corruption, quit India… (*Interruptions*) Dynasty, quit India… (*Interruptions*) Merit now finds place in India… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर, जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। … (व्यवधान) राष्ट्र के इतिहास में पहली बार भारत मां की हत्या की बात की गई और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। … (व्यवधान) भारत मां की हत्या की बात पर जब कांग्रेस पार्टी ने आज इस सदन में तालियां पीटीं, तो इस बात का संकेत पूरे देश को दे दिया कि मन में गद्दारी किसके है। … (व्यवधान) मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं कि मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। … (व्यवधान) मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं की अलायंस के एक सदस्य बैठे हुए हैं, जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत है। … (व्यवधान) अगर राहुल गांधी में हिम्मत हो, तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। … (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर गांधी खानदान में हिम्मत है, तो इस सदन में, इस देश को बताएं कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है? You are not India because you define corruption in India… (*Interruptions*) You are not India because you define incompetence… (*Interruptions*) You are not India… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह तरीका ठीक नहीं है। सदन में नारेबाजी करने का तरीका ठीक नहीं है। आप लोग प्लीज बैठिए और उनको अपनी बात कहने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी है। यह तरीका ठीक नहीं है। नो, यह आपका गलत तरीका है। स्मृति जी।

… (व्यवधान)

(1250/MK/RP)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: कहती हूं। शायद ये अपने ही कोलाहल में सुन न पाएं। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है। … (व्यवधान) वह न खंडित था, न है और न कभी होगा। यूपीए के एलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। मैं पुन: कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत नहीं है। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि

क्या भारत केवल उत्तर भारत है। … (व्यवधान) अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंहतोड़ जवाब दें, अगर आप हिन्दुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की संभावना तलाशनी चाहिए। … (व्यवधान) मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या उनके आदेशानुसार यह वक्तव्य दिया गया कि कश्मीर का खंडन हो और भारत विभाजित हो? क्या यह कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: कहती हूं कि हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत माँ की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। … (व्यवधान) कांग्रेसियों ने बैठकर माँ की हत्या के लिए मेज थपथपाई है और यह बात करते हैं इंसाफ की।… (व्यवधान) यह चेहरा धूमिल है, मैं बताऊं यह चेहरा किसका है? यह चेहरा गिरिजा टिक्कू का है। … (व्यवधान) आप भी पंडितों की दास्तान सुन लीजिए। यह चित्र गिरिजा टिक्कू का है। 1990 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पे चेक लेने जाती है। … (व्यवधान) मैं सारी बातें करूंगी। वह अपना पे चेक लेने जाती है और बस से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको पाँच मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं, फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं।… (व्यवधान) जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्तओं ने उसको प्रोपेगंडा कहा। सरला भट्ट … (व्यवधान) आप नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए। आप नहीं चाहते हैं कि वह विक्टिम आज आइडेंटिफाई हो। … (व्यवधान) सरला भट्ट एक मेडिकल स्टॉफ थी। 1990 के दशक में उसको उसके इंस्टिट्यूट से अगवा करके गैंगरेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। … (व्यवधान) आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी एलायंस के लोग हिन्दुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि गिरिजा टिक्कू और सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? … (व्यवधान) हर गली, हर मोहल्ले में पंडितों के बीच एक स्लोगन गूंजता था - Ralib Galib Chalib. मैं पुन: कहती हूं- Ralib Galib Chalib, आप चिल्लाना बंद कीजिए। … (व्यवधान) आप पहले समझिए। Ralib Galib Chalib, इसका मतलब या तो अपना धर्म बदलो, या कश्मीर छोड़ो, या यहीं मरो। क्या उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है? आपने उनकी आवाज को कभी नहीं सुना। … (व्यवधान) मैं आज कहती हूं, इन्होंने 1984 के दौरान आसूं बहाए, भ्रमण किया, मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप किसी और का वक्तव्य मत सुनिए। एक पत्रकार प्रणय गुप्ता हैं, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रैट करके उनके अंगों को उनकी माँ के मुंह में ठूंसा गया।… (व्यवधान)
(1255/SJN/NKL)

मैं आज बताती हूं। त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चिल्ला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया गया। सुल्तानपुरी की एक महिला ने एफिडेविट दी है कि मेरे पति को मार दिया, बेटी को शादी की एक रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया।…(व्यवधान) सिख दंगों के दौरान एक 45 साल की मां ने कहा कि न सिर्फ मेरे पति को मारा, न सिर्फ मेरा गैंगरेप किया, बल्कि

मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसीन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई और आज ये भारत की बात करते हैं।…(व्यवधान) वे कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिन्दुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में हर दिन गोलियों की आवाजें सुनाई देती थीं, जब ये उन वादियों में गए, तो जैसे कश्मीरी कहते हैं कि शीन जंग कर रहे थे।…(व्यवधान) बर्फ के गोलों के साथ अपने किसी परिजन के साथ खेल रहे थे, ये तब संभव हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 हटाई।…(व्यवधान) आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं। I have been to Manipur. You might have not been there. … (*Interruptions*)

महोदय, आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया। अगर इनका बस चले, तो ये पुनः धारा 370 स्थापित कर देंगे। धारा 370 की वजह से अगर कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई।…(व्यवधान) अगर कश्मीर की बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थीं, तो उनकी पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। अगर कश्मीर में 14 या 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था, तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई।…(व्यवधान) आज जो इस सदन से भाग गए हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में न तो धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को 'Ralib Galib Chalib' की धमकी देने वाला कोई नहीं बचेगा।…(व्यवधान) आज यहां पर कई बहनें उपस्थित हैं, जो अपने आक्रोश को और राहुल जी के प्रति समर्थन को व्यक्त कर रही हैं। सन् 1984 के दंगों का विवरण सुनकर, गिरिजा टिक्कू का विवरण सुनकर।…(व्यवधान) मैंने स्वयं मणिपुर के मुख्यमंत्री जी से बात की, त्वरित रूप से वहां पर लोग पकड़े जाएं, न सिर्फ इसका निवेदन किया, बल्कि वे लोग पकड़े गए और सीबीआई की इंक्वॉयरी जारी है।…(व्यवधान)

आज जो यहां बैठे हैं और जो चले गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, उन्होंने कहा कि वह राजस्थान गए थे। राजस्थान में क्या हुआ? गिरिजा टिक्कू को तो 90 के दशक में आरी से काट दिया गया था। भीलवाड़ा में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है।…(व्यवधान) इस सदन की दो महिला एमपीज़ उस परिवार से मिलती हैं। जब बच्ची जिंदा थी, तो गैंगरेप के बाद उसे काटा जाता है। फिर उसे भट्टी में डाल दिया जाता है। ये इन महिला सांसदों का वक्तव्य है। जब 14 साल की बच्ची जीवित थी, तो राजस्थान के भीलवाड़ा में गैंगरेप के बाद उसको काटा गया, जलाने के लिए फेंका गया। उसका एकमात्र हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था।…(व्यवधान)

(1300/YSH/SPR)

अध्यक्ष महोदय, मैं आज पूछना चाहती हूँ कि आज जो जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं, इन्होंने न्याय की गुहार तब नहीं लगाई, जब 60 साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंगरेप हुआ।… (व्यवधान) कोर्ट में केस लंबित था। इनका दिल नहीं दहला और बोल रहे थे कि मणिपुर के बारे में, नार्थ ईस्ट के बारे में आप नहीं जानते।… (व्यवधान) जिन्होंने प्रस्तावना की,

मैं उनसे कहती हूँ। नेल्ली का नरसंहार हुआ। पांच मिनट के लिए कांग्रेस की एक मंत्री गई, लेकिन इनका तब क्या रुख था?... (व्यवधान) वर्ष 2012 में तरुण गोगोई जी ने स्वयं वक्तव्य दिया था कि दंगे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की केन्द्र की सरकार न ट्रूप्स दे रही है, न इंटेलिजेंस दे रही है।... (व्यवधान) ये कोकराझार की बात करते हैं। यह मेरा वक्तव्य नहीं है।... (व्यवधान) यह उस समय के कांग्रेस के मुख्य मंत्री तरुण गोगोई जी का वक्तव्य है। कोकराझार में हिंसा होती है। धुबरी में तीन-तीन महीने तक कर्फ्यू रहता है।... (व्यवधान)

महोदय, आज जो लोकतंत्र की दुहाई दे चुके हैं, हम बार-बार इस सदन में इमरजेंसी की गाथा को याद करते हैं।... (व्यवधान) इस सदन में हम बार-बार उन नेताओं को, उन सामाजिक संस्थाओं को, उन मीडिया के बंधुओं को याद करते हैं, जिनकी प्रिंटिंग प्रेस कैसे जबरन बंद कराई गई, उस पर विस्तृत चर्चा होती है। इमरजेंसी के कालखंड में साधारण महिला का कांग्रेस पार्टी ने क्या हश्र किया? स्नेहलता रेड्डी की आज बात करना जरूरी है।... (व्यवधान) उन्हें बैंगलोर की जेल में बंद किया गया और इसलिए बंद किया गया, क्योंकि वे सोशलिस्ट थीं, भाजपाई नहीं थीं। जब उन्हें 2 मई, 1976 को बंद किया, तब उन्होंने अपनी प्रिजनर्स डायरी में जो लिखा, उसे मैं कोट कर रही हूँ, जो पब्लिकली अवेलेबल है।... (व्यवधान) As a woman comes in, she is stripped naked in front of everyone else. When a human being is sentenced, is the punishment not enough? Must the human body be degraded and humiliated? ... (*Interruptions*)

यह स्नेहलता रेड्डी के शब्द हैं, जो उन्होंने इमरजेंसी के कालखंड में जेल में लिखे। अपनी अचीवमेंट्स को बताते हुए 6 जून, 1974 में स्नेहलता रेड्डी लिखती हैं, "At least I have achieved something here. I have stopped the horrible beatings the women prisoners used to get."

यह कांग्रेस का इतिहास है और ये भारत की बात करते हैं। ये महिला अस्थमा की पेशेंट थी। जेपीजी को डायलसिस नहीं करने दिया, अस्थमा की इस पेशेंट को दवा नहीं लेने दी। वह दो बार अस्थमेटिक कोमा में गईं और अस्थमेटिक कोमा में जाते-जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो उनको पैरोल पर 15 जनवरी, 1977 में छोड़ा गया। चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था और पांच दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है।... (व्यवधान) जिनकी हत्या हुई, आज वे इनको कठघरे में नहीं ला सकते हैं इसलिए आज इस सदन में मैं उनका नाम ले रही हूँ, उनके बारे में बोल रही हूँ। ये चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो।... (व्यवधान) मणिपुर पर चर्चा करने के लिए बार-बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार-बार देश के गृह मंत्री जी ने कहा। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पर सदन में चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं।

(1305/RAJ/MMN)

ये भागे, हम नहीं भागे।…(व्यवधान) भागने के पीछे कारण क्या है? …(व्यवधान) क्योंकि जब गृह मंत्री जी बोलने लगेंगे, परतें खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे।…(व्यवधान) मौन मुद्रा का उल्लेख हुआ था।…(व्यवधान) ये लोग कई चीजों पर मौन थे और आज भी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में केपीएमजी की एक रिपोर्ट है, जो इनके कार्यकाल से संबंधित है।…(व्यवधान) जो कहता है कि करप्शन की वजह से यूपीए के कार्यकाल में हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ को नौ प्रतिशत का निगेटिव इम्पैक्ट होगा।…(व्यवधान) यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज बोल रही थी।…(व्यवधान) लेकिन ये चुप थे और आज भी चुप हैं? …(व्यवधान) जो लोग जीरो लॉस थ्योरी सिखाते थे, आज उसी काँग्रेस के एक नेता को कोयला घोटाले के लिए सजा हुई है और वे चुप हैं।…(व्यवधान) वे चुप और बहुत सारी चीजों में रहे हैं।…(व्यवधान) वर्ष 2005-2006 में यूपीए की सरकार को यह ज्ञात हो गया था कि खुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। वर्ष 2005-2006 में इनको पता था। यह सरकारी सर्वे में ज्ञात हुआ है। लेकिन ये चुप थे।…(व्यवधान) जब वर्ष 2010 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा, तब इनकी सरकार थी कि स्वच्छता नहीं होने की वजह से देश की जीडीपी पर 6.4 प्रतिशत का निगेटिव इम्पैक्ट है। यह चुप रहे। महिला का बलात्कार खुले में शौच करने के कारण हो रहा था, यह इनको पता था, लेकिन ये चुप रहे।…(व्यवधान) इन्होंने वर्ष 2014 तक देश में केवल 39 प्रतिशत आबादी को टॉयलेट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी। वर्ष 2019 तक 100 प्रतिशत कवरेज हुआ।…(व्यवधान) 110 मिलियन टॉयलेट्स, …(व्यवधान) अध्यक्ष जी, ये इस पर हंसते हैं।…(व्यवधान) शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना या सूर्यास्त का इंतजार करना और फिर शौच के लिए बाहर जाना एवं वहां उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, यह कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है, इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं है। ये इसे उपहास का विषय बनाते हैं।…(व्यवधान)

आज मुझे यह कहते हुए शर्मिंदगी है कि मैं यहां पर कह रही हूं कि खुले में शौच करते समय औरत का बलात्कार होता है। ये उपहास उड़ा रहे हैं और महिला उपहास उड़ा रही है।…(व्यवधान) शायद कांग्रेस नीत एलायंस के यही लक्षण हैं कि औरत का बलात्कार हो तो ये हंसे।…(व्यवधान) भारत मां की हत्या की बात हो, तो ये यहां पर तालियां पीटें।…(व्यवधान) यह कांग्रेस का लक्षण है।

इनकी प्रस्तावना के वक्त यह कहा गया कि हम मात्र एक व्यक्ति से बात करेंगे। हम किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे। क्योंकि मंत्रियों की कार्यशैली पर इनको चर्चा नहीं करनी है और शायद सच भी है। इनका अपना अनुभव है कि इनके यहां पावर का केन्द्र बिन्दु एक था, लेकिन यहां पर फर्क यह है कि हम सब कलेक्टिव रिस्पाँसिबिलिटी के भागीदार हैं।…(व्यवधान) इसलिए आज जब गजेन्द्र शेखावत जी की मंत्रालय की ओर से टॉयलेट्स की व्यवस्था होती है, तो मैं एक महिला सांसद और नागरिक होने के नाते इनका उतना ही अभिनंदन करती हूं जितना कि प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जल जीवन मिशन के बारे में कहना चाहती हूं। हमारे देश में जब इनकी सरकार थी, तो मात्र तीन करोड़ परिवारों तक नल से पानी पहुंचता था। वर्ष 2019 का आंकड़ा कहता है कि आपने तब तक साढ़े नौ करोड़ लोगों तक पानी पहुंचाया और अब तक लगभग 12 करोड़, 40 लाख लोगों तक नल से पानी पहुंच चुका है।... (व्यवधान)

(1310/KN/VR)

लेकिन इनको इससे भी सरोकार नहीं कि अगर टॉयलेट बना, महिलाओं का शोषण कम हुआ, देश की साधारण महिला का सम्मान बढ़ा तो इनको इससे कोई सरोकार नहीं है, यह स्पष्ट है। गरीब के घर में नल से जल पहुंचा, तो कांग्रेस का उससे कोई सरोकार नहीं, यह स्प्ष्ट है और सही है।... (व्यवधान) हमारा सरोकार है, देश हमारा है और सेवा हमारी है। आज ये उत्तेजित हैं कि मैं इस सदन में मंत्रिमंडल के अपने कई सहयोगी साथियों का वर्णन करती हूं। एक ऐसी महिला मंत्री का वर्णन कर रही हूं, जो वर्तमान में नहीं हैं। जनधन योजना के माध्यम से 23 करोड़ महिलाओं का बैंक में खाता खुला। यह इनके लिए कोई मान्यता नहीं रखता, यह मुझे स्वीकार है। यह हमारे लिए अहम है।... (व्यवधान)

मुद्रा योजना के माध्यम से 40 करोड़ लोगों को, जो जीवन में कभी व्यवसाय नहीं कर पाते थे, जिनके पास कांग्रेस की पर्सनल डायलिंग मशीन नहीं थी, उनको मुद्रा योजना का लोन मिला और 27 करोड़ रुपये के लोन महिलाओं को दिए गए।... (व्यवधान) मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 23 लाख करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए। इनका उससे कोई सरोकार नहीं है।... (व्यवधान) हमारे राष्ट्र के इतिहास में 8 करोड़ नौजवान फर्स्ट टाइम एन्टरप्रेन्योर बने, इनका उससे कोई सरोकार नहीं है। एक लाख 80 हजार एकाउंट्स में स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत 40 हजार करोड़ रुपये दिए गए। 80 प्रतिशत महिलाएं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट रुकिये। यह क्या तरीका है? वे अपनी बात कह रही हैं, तथ्यों के आधार पर कह रही हैं। अगर आपको इसका खंडन करना है तो आप बोलना और तथ्यों के आधार पर करना। यह गलत बात है। नहीं, यह गलत बात है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलिये।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : सर, मैं आपकी अनुमति से पुन: बोलूं।... (व्यवधान) जैसा कि मैंने कहा कि अगर महिला का आर्थिक-सामाजिक उत्थान होता है तो इससे इनको कोई सरोकार नहीं है।

अब सेल्फ-हेल्प ग्रुप की बात करते हैं। जब इनकी सरकार थी, तब मात्र 19 लाख सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को इन्होंने 80 हजार करोड़ रुपये का लोन दिया। हमने 9 करोड़ महिलाओं को देश के सेल्फ-हेल्प ग्रुप में 5 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक व्यवस्था करके दी। यह हमारा अभिमान है। आज ये महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब इन्होंने महिलाओं से संबंधित बजट की व्यवस्था की, तब इनके कार्यकाल से 130 प्रतिशत ज्यादा बजट हमारे प्रधान मंत्री जी ने देश की महिलाओं को समर्पित किया। यह हमारा अभिमान है।

आयुष्मान भारत के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों में महिलाओं को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला। आज तक 2 करोड़ 60 लाख महिलाओं ने हॉस्पिटल में, वेलनेस सेंटर में सुविधाएं लीं। ब्रेस्ट कैंसर में 12 करोड़, सर्वाइकल कैंसर में 8 करोड़ महिलाओं ने स्क्रीनिंग करवाई। इनका उससे कोई सरोकार नहीं, बल्कि इनका दिल्ली में उनसे सरोकार हैं, जिन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू ही नहीं की। इनका उनसे सरोकार हैं।... (व्यवधान) देश में मोदी जी की सरकार में 3 करोड़ 84 लाख घर बने, जिनमें से 2 करोड़ 86 लाख महिलाओं को मिले, इनका उनसे कोई सरोकार नहीं हैं क्योंकि गरीब महिलाएं लखपति दीदी बन गईं, वे हमारा अभिमान हैं, इनका नहीं।

हमारे देश में 8 करोड़ 50 लाख बेटियों ने समग्र शिक्षा के माध्यम से स्कूल में सेवा ली, मुफ्त टेक्स्ट बुक की सेवा ली। बेटियों की यह उपलब्धि हमारा अभिमान है, इनका नहीं। 5 लाख से ज्यादा स्कूलों में बेटियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था हुई, यह इनका अभिमान नहीं, हमारा अभिमान है। हमें अपनी बेटियों पर गर्व हैं। 5 लाख दिव्यांग बेटियों को मंथली स्टाइपेंड मिलता है।

(1315/VB/SAN)

यह सेवा हम देश की बेटियों को दे सकते हैं। यह हमारे लिए प्रभु का एक बहुत बड़ा उपकार है। 1,28,000 बेटियों को हर साल 12,000 रुपए मेरिटोरिअस स्कॉलरशिप दी जाती है।... (व्यवधान) यह सेवा का मौका परिवारों ने हमको दिया। 2 लाख से ज्यादा बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है।... (व्यवधान) आज देश में एलिमेंट्री एजुकेशन में बेटियों की एनरोलमेंट शत-प्रतिशत है। यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आज पहली बार, उच्च शिक्षा में फीमेल एनरोलमेंट 2 करोड़ से ज्यादा हुआ है।... (व्यवधान) यह देश के लिए गौरव की बात है। आज दलित बेटियों का एनरोलमेंट 38 परसेंट बढ़ा है। मैं दलित बेटियों का उल्लेख करती हूँ, ये चिल्लाते हैं।... (व्यवधान) इनको दलित बेटियों से सरोकार नहीं है, लेकिन हमको है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आदिवासी बच्चों में, लड़कियों का एनरोलमेंट 63 परसेंट बढ़ा है।... (व्यवधान) आदिवासी बच्चियों के साथ इनका कोई सरोकार नहीं, आदिवासी बेटियों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को सेवा का मौका दिया, यह हमारे लिए प्रभु की असीम कृपा है।... (व्यवधान)

यदि हम नॉर्थ-ईस्ट की बात करें, तो नॉर्थ-ईस्ट में महिलाओं के एनरोलमेंट में 34 परसेंट की वृद्धि हुई है।... (व्यवधान) नॉर्थ-ईस्ट के मेरे सभी साथी, चाहे वे सदन में कहीं भी बैठे हों, मैं महिलाओं की दृष्टि से उनका अभिनन्दन करती हूँ।... (व्यवधान)

आज हमारे देश में, जो महिलाएं पीएचडी करती हैं, उनके एनरोलमेंट में 99.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह हमारे लिए हिन्दुस्तानी होने के नाते गौरव की बात है।... (व्यवधान) आज जो महिलाएं शैक्षिक संस्थानों, यूनिवर्सिटीज, इंस्टिट्यूशंस, कॉलेजेज़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं, उनकी संख्या में 66 परसेंट की वृद्धि हुई है।... (व्यवधान) आप हो-हो करते जाएं, लेकिन हम तो उनके लिए बल्ले-बल्ले ही करेंगे।... (व्यवधान)

आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारी लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि ईपीएफ में 28,70,000 महिलाओं ने अपने आप को सब्सक्राइबर बनाया है।... (व्यवधान) वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 1400 महिला साइंटिस्ट्स को भारत सरकार की विविध स्कीम्स के अंतर्गत

सहयोग मिला है।... (व्यवधान) आज महिलाओं को मैटरनिटी लीव में 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव मोदी सरकार ने सुनिश्चित की है। आज तीन करोड़ बेटियों ने, महिलाओं ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 13,700 करोड़ रुपए अपने बैंक के खाते में पाया है।... (व्यवधान) इस सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी को आभार और बेटियों का अभिनन्दन।... (व्यवधान)

आज हमारे देश की बेटियाँ सैनिक स्कूलों में पढ़ सकती हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए रक्षा मंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी को आभार।... (व्यवधान) आज हमारे देश की बेटियाँ आर्म्ड फोर्सेज में परमानेंट कमीशन पा चुकी हैं।... (व्यवधान) हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसी बेटियों का आभार। आज जो यहाँ महिलाओं के हक़ के लिए बोल रहे थे... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये विषय पर बोल रही हैं। सभी अविश्वास प्रस्ताव के विषय पर बोल सकते हैं। इस प्रकार से करना, क्या यह अच्छा तरीका है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीया मंत्री जी, आप बोलें।

... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : महोदय, शायद वे भी मजबूर हैं। उनको भी रिमोट से डायरेक्शन आया है।... (व्यवधान)

1319 बजे (श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

महोदय, आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज एक तरफ हमारी बेटियों ने सैनिक स्कूल्स में, आर्म्ड फोर्सेज में अपनी प्रतिभा के आधार पर देश का गौरव बढ़ाया है।... (व्यवधान) दूसरी ओर, बिना किसी पुरुष सहयोगी के हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार 4,313 मुस्लिम बहनें अकेली हज़ के लिए गईं और सुरक्षित हिन्दुस्तान लौटीं।... (व्यवधान)

महोदय, जो महिलाओं के हक़ की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के हक़ को संरक्षित करने के लिए जब हमारी सरकार ट्रिपल तलाक के कलंक को मिटाना चाहती थी, ... (व्यवधान) तब महिलाओं के हक में नहीं बल्कि वोट बैंक के लालच में इन्होंने सदन की कार्यवाही को त्याग दिया था। ... (व्यवधान)

(1320/PC/SNT)

सभापति महोदय, जब आज ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो यह कहना उचित होगा कि एक तरफ ये वर्ष 2013 में निर्भया फंड की रचना की घोषणा करते हैं, लेकिन एक काम निर्भया फंड में नहीं करते, लेकिन जो निर्भया के बलात्कारी हैं, कांग्रेस नीत एलाएंस के लोग बलात्कारी के हाथ में 10,000 रुपए और एक सिलाई की मशीन देते हैं। ... (व्यवधान)

आज हमें इस बात का गौरव है कि देश में 42 प्रोजेक्ट्स, लगभग 5,000 करोड़ की लागत से भारत सरकार के सौजन्य से बन रहे हैं। ... (व्यवधान) जो महिला सुरक्षा के लिए ये न कर पाए, वह आज प्रधान मंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ... (व्यवधान) आज इंटिग्रेटेड इमर्जेंसी रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत देश के 983 रेलवे स्टेशंस पर महिला पैसेंजर्स के लिए चौबीसों घंटे सुरक्षा का

प्रावधान किया गया है। ... (व्यवधान) आज कोंकण में वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम की विशेष व्यवस्था महिला संरक्षण और महिला सुरक्षा के लिए की गई है। ... (व्यवधान)

आज, चूंकि रेल मंत्री जी यहां बैठे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर फेशियल रिकगनिशन सिस्टम, इंटिग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम, यह सब भारत सरकार के सौजन्य से महिला सुरक्षा के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं एक बात पर आपत्ति दर्ज करती हूं। जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते-जाते यहां एक अभद्र लक्षण के दर्शन दिए। ... (व्यवधान) It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a Parliament which seats female Members of Parliament. ऐसे गरिमाविहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ... (व्यवधान) ये उस खानदान के लक्षण हैं, यह आज सदन में देश को पता चला। ... (व्यवधान) लेकिन कहां गए हैं? वहां क्या हालात हैं? राजस्थान में भास्कर ने लिखा है कि गोद भराई के नाम पर राजस्थान की सरकार जेब भराई कर रही है। ... (व्यवधान) राजस्थान में 13 से 20 महीने का गर्भाशय दिखाया जा रहा है और भारत की तिजोरी से पैसा लूटा जा रहा है। ... (व्यवधान)

इनका सरोकार महिला उत्थान से नहीं, ये महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, इनके नेता ने जाते-जाते यहां उसको प्रसारित कर दिया है। ... (व्यवधान) लेकिन इनके नेता को सरोकार किससे है? ... (व्यवधान) चीन से है, चूंकि कांग्रेस पार्टी के सब नेता चीन में इतनी रुचि लेते हैं, इसलिए आज एक सुखद समाचार भी सुनाती हूं। ... (व्यवधान)

चीन में 31वें यूनिवर्सिटी गेम्स हुए। ... (व्यवधान) वर्ष 1959 से लेकर आज तक भारत को मात्र 18 पदक मिले थे। ... (व्यवधान) इस बार 26 मेडल का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के बच्चों ने स्थापित किया। ... (व्यवधान) भारत मां के टुकड़े के लिए तालियां बजाते थे, भारत मां के बच्चों के लिए तो बजा दो। ... (व्यवधान) 11 गोल्ड, पांच सिल्वर, दस ब्रॉन्ज़ आज देश के यूनिवर्सिटी के छात्र देखें कि 31वें यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का नाम रौशन करने वाले छात्रों के लिए मैं गुहार लगा रही हूं कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए यहां अभिनंदन कर दे, लेकिन ये अभिनंदन से भारत के बच्चों को वंचित रखते हैं। ... (व्यवधान)

(1325/CS/KKD)

बात अभिनन्दन की निकली, तो एक वह भी थे, जिन्होंने आसमान चीरा और दुश्मन को मुँहतोड़ जवाब दिया।... (व्यवधान) आज जो व्यक्ति यहाँ पर भारत की आवाज का उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने भारत की आवाज में आवाज मिलाकर तब नहीं बोला, जब आतंकी हमला करते हैं।... (व्यवधान) उन्होंने भारत की आवाज से अपनी आवाज को भिन्न करते हुए इस सदन में भारत के रक्षा बलों से प्रमाण माँगा।... (व्यवधान) प्रमाण क्यूँ माँगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा होगा और प्रमाण माँगने का क्या सलीका है, यह मीडिया के मित्रों के माध्यम से देश के ध्यान में आया है।... (व्यवधान) आज मैं न्यूजक्लिक की बात करना थोड़ा जरूरी समझती हूँ।... (व्यवधान) न्यूजक्लिक, नेविल रॉय सिंघम कुछ पत्रकारों को हिन्दुस्तान में लिखते हैं कि किस प्रकार से हिन्दुस्तान के खिलाफ न्यूज

सर्कुलेट होनी चाहिए।... (व्यवधान) कैसे चाइना के समर्थन में अलग-अलग आर्टिकल लिखने चाहिए और इसे एक बार छपवा दो तो ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन इसको इकट्ठा करके फिर काम आगे बढ़ायेगा।... (व्यवधान) मेरे एक पार्लियामेन्टरी सहयोगी निशिकांत जी ने जब इस पर विषय उठाया तो मैं स्तब्ध हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने डिमांड नहीं की कि अगर कोई बाहरी ताकत का पैसा लेकर हिन्दुस्तान में व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है, हिन्दुस्तान को कलंकित करना चाहता है तो उस पर कार्रवाई करो। ऐसा कांग्रेस का पक्ष नहीं था। कांग्रेस ने पक्ष यह लिया कि जो निशिकांत दुबे के मुँह से शब्द निकले हैं, उनको एक्सपंज कर दीजिए।

महोदय, यह जो ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन है, जिसके बारे में ना आप ईडी को मानें, न्यूयॉर्क टाइम्स को मानें, उस ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन के जो मुख्य रिसर्चर हैं, ... (व्यवधान) उनके वक्तव्य को कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल फेसबुक पर क्यों डालती है, यह मैं पूछना चाहती हूँ... (व्यवधान) जो जानबूझकर भारत के किसानों के हितों के खिलाफ बोलते हैं।... (व्यवधान) उनका वक्तव्य, ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन वालों का जो सीनियर फेलो या रिसर्चर है, उसका वक्तव्य नेशनल कांग्रेस के फेसबुक पर 19 अप्रैल, 2019 को क्यों पब्लिश होता है।... (व्यवधान) यह थोड़ा-बहुत शोध का विषय है।... (व्यवधान) यह थोड़ा-बहुत चर्चा का विषय है। आज मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब प्रस्तावना हुई, मैं तो प्रस्तावना के विरूद्ध खड़ी हूँ, मैं नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व पर राष्ट्र के सभी नागरिकों के साथ पुन: विश्वास दर्शाते हुए अपना वक्तव्य देती हूँ, लेकिन राहुल जी ने किस पर विश्वास जताया। राहुल जी ने विश्वास जताया मुस्लिम लीग पर। उन्होंने कहा कि यह सेक्युलर पार्टी है। शायद राहुल जी ने न पढ़ा हो कि 80 के दशक में मुरादाबाद में 83 लोगों को मारने वाली मुस्लिम लीग, ... (व्यवधान) राहुल जी को बताना पड़ेगा कि सेक्युलर कैसे हुई। राहुल जी को आज जवाब देना होगा। वे राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, तो क्या जेएनयू में जाकर जब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दे रहे थे, वह राहुल गांधी जी की देशभक्ति थी। राहुल गांधी जी को आज जवाब देना होगा, हैं तो नहीं, ... (व्यवधान) उनको आज जवाब देना होगा। जिस अफजल गुरु ने इस संसद पर हमला किया, उस अफजल गुरु के संरक्षक, समर्थक को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी का नेता बना दिया।... (व्यवधान) यह राहुल गांधी जी की देशभक्ति है।... (व्यवधान) राहुल गांधी जी की देशभक्ति... (व्यवधान) आज बताती हूँ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह क्या हो रहा है? ... (व्यवधान) We Strongly oppose this. ... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : घबराइये मत, आप ही के नेता बोलकर गए हैं।... (व्यवधान) आप घबरा क्यों रहे हैं? ... (व्यवधान) बैठिए, मैं आराम से बोल रही हूँ।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): मंत्री जी, आप जरा संक्षेप में कीजिए।

(1330/IND/AK)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : सभापति जी, मैं पुन: बोलना चाहती हूं। बहुत सारे व्यवधान आए। अब राहुल जी की बात चली है तो थोड़ी कृपा कर दीजिए।... (व्यवधान) मैं दोबारा कहती हूं कि यहां क्या बोले हैं और क्या देश के बाहर बोले हैं? देश के बाहर गए, तो आइडियाज ऑफ इंडिया कांक्लेव में कहा कि "There is going to be a mass upsurge. India has massive amount of polarization". ये राहुल गांधी के शब्द हैं। इसका मतलब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा हिंदुस्तानी सौहार्द की भूमिका में नहीं रहते। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी भाईचारे में इतना विश्वास नहीं करते because there is a massive amount of polarization. राहुल गांधी ने कहा कि "There is going to be a mass upsurge. Now, the question is how can the Opposition effectively use the upsurge to change politics". मतलब उन्होंने कहा कि देश में उथल-पुथल होगी। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष इस उथल-पुथल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, यह मैं सोच रहा हूं।... (व्यवधान) फिर उनका शब्द है कि देश में केरोसीन फैला है, हमें एक चिंगारी की जरूरत है। मैं पूछना चाहती हूं कि आज माचिस ढूंढते-ढूंढते राहुल गांधी कहां खो गए? अमरीका गए, तंजीम अनसारी के साथ, जो पाकिस्तानी इमाम जावद अहमद के साथ ताल्लुक रखते हैं, अपने कार्यक्रमों को अमरीका में उनके साथ करवाया। राहुल गांधी, मिनाज खान जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। आज जो लोग इस देश में एसपियोनेज के लिए पकड़े जाते हैं, उनका राहुल गांधी ने विदेश में जाकर समर्थन किया। ये तब से अडानी-अडानी कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं भी बोल दूं।... (व्यवधान) वह तो मेरे पास भी है। वह इतना ही खराब है, तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं?... (व्यवधान)

1332 hours

(*At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury came and stood near the Table.*)

निशिकांत जी ने सही कहा कि किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। मैं पूछना चाहती हूं कि वर्ष 1993 में मुंदरा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब प्रधान मंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे।... (व्यवधान)

1332 hours

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury went back to his seat.)

उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72 हजार करोड़ रुपये का लोन दे दिया। राजस्थान में साठ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का समझौता गहलोत जी के साथ कर लिया। बीस हजार एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीए सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी, तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया?... (व्यवधान) बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी

को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के मना करने के बावजूद अडानी को क्यों दिया?… (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, this is not right. … (*Interruptions*)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जानें? … (व्यवधान) दामाद आपका नहीं है, जिनका है, वे नहीं चिल्ला रहे हैं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं। आप बैठ जाइए। जिसका दामाद है, वह नहीं चिल्ला रहा है तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप बैठ जाइए।… (व्यवधान) आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोयला घोटाले में पकड़े गए, 2-जी में भी ... (*Expunged as ordered by the Chair*) बैठ जाएं।… (व्यवधान)

1334 hours

(*At this stage, Shri A. Raja came and stood near the Table.*)

पूरी बला की जड़ परिवादवाद में है और परिवारवाद की राजनीति की जड़ कांग्रेस पार्टी में है। इनके एलायंस के लोग चारा खाते हैं और ये उनके घर मटन खाने चले जाते हैं।… (व्यवधान)

1334 बजे

(इस समय श्री ए. राजा अपने स्थान पर वापस चले गए।)

इनके एलायंस के लोग रेल की नौकरी के लिए गरीब की जमीन खाते हैं, जाकर वे उन्हीं लोगों को गले लगाते हैं और इस सबके पीछे एक ही मजबूरी है जो बड़ी विनम्रता से अधीर दा ने भी स्वीकारी कि मजबूरी हमारी है कि जनता तीसरी बार कह रही है कि फिर एक बार मोदी जी की बारी है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप कंक्लूड कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप भी बैठिए।

… (व्यवधान)

(1335/RV/UB)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : सभापति महोदय, आज ये यहां पर किसानों का उल्लेख कर रहे थे, आज ये किसान की बात कर रहे थे, तो किसान का क्या हश्र करते हैं, वह मैं बताना चाहती हूं। मुझे थोड़ी-सी मोहलत दे दें।… (व्यवधान)

महोदय, मैं उस क्षेत्र की बात कहना चाहती हूं, जिसकी मैं प्रतिनिधि हूं, जहां पर गरीब, किसान, दलित विद्यालय की मांग कर रहे थे।… (व्यवधान) वर्ष 1982 में किसानों ने 4 बीघा 2 बिस्वा जमीन इन्टर कॉलेज के लिए दी और अमेठी में किसानों की यह जमीन धोखे से हड़पने वाले फाउण्डेशन का नाम गांधी खानदान है।… (व्यवधान) वर्ष 2016 में राहुल जी दौरे पर तिलोई गए।… (व्यवधान) वहां लोगों ने कहा, 200 छात्रों ने कहा कि जमीन वापस कर दो, हमारे लिए कॉलेज की व्यवस्था करो, उन्होंने अपने अलाएंस पार्टनर के साथ उन छात्रों को जेल में डाल दिया।… (व्यवधान) वर्ष 2017 में जेल में डाल दिया।… (व्यवधान) सेठा, गौरीगंज में इसका प्रमाण है।… (व्यवधान) आ

जाओ गौरीगंज, 'दूध का दूध, पानी का पानी' यहीं कर दूंगी।... (व्यवधान) गौरीगंज, सेठा रोड पर जमीन हथिया ली, भूसियावा मार्ग पर नरसिंह भानपुर में मुंसीगंज में जमीन हथिया ली, यह उनका संस्कार है।... (व्यवधान) जमीन कौन-कौन हड़पता है, कांग्रेस की यह गाथा स्पष्ट है।... (व्यवधान)
1336 बजे

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री रवनीत सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

महोदय, मैं रेल मंत्री जी का अभिनन्दन करती हूं कि रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली में भी दस हजार कोचेज तब बने, जब नरेन्द्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बने।... (व्यवधान) क्या आपको पीड़ा हो रही है?... (व्यवधान)

मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आज जो किसानों का दम भरते हैं, बालियान साहब यहां हैं, अमेठी के किसानों की ओर से बालियान साहब को नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करती हूं कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार अमेठी में खाद की रैक तब उतरी, जब मोदी जी प्रधान मंत्री बनकर आए।... (व्यवधान) इन्होंने खाद नहीं दी। ये गौरीगंज में किसानों पर लाठी चार्ज करते थे। राजनाथ जी इसके साक्षी हैं।... (व्यवधान) अमेठी में, जहां पाँच दशक इन्होंने राज किया, वहां के 80 प्रतिशत लोगों को इन्होंने शौचालय की सुविधा नहीं दी, 60 प्रतिशत लोगों के घर में बिजली नहीं दी और आज ये लोकतंत्र की बात करते हैं, अपनी प्रतिभा की बात करते हैं।... (व्यवधान)
1337 बजे

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री रवनीत सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

मैं आभार व्यक्त करती हूं कि अमेठी का पहला सैनिक स्कूल मोदी जी ने दिया। साढ़े सात लाख लोगों को मुफ्त अनाज मोदी जी दे रहे हैं। अमेठी का पहला मेडिकल कॉलेज, जिसके नाम पर इस खानदान ने जमीन हड़प ली थी, उसे नरेन्द्र मोदी जी ने दिया।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहती हूं कि जो अभी यहां नहीं हैं, जो पचास साल की उम्र के बाद देश देखने निकले थे, वर्तमान में वे देश के किस कोने में हैं, यह मैं नहीं जानती।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): माननीय सदस्यगण, आप मंत्रिमंडल में अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आए हैं तो मंत्रिमंडल उस सम्बन्ध में बोलेगा, उन्हें बोलने का अधिकार है।

आपने मणिपुर के ऊपर चर्चा की मांग नहीं की है। जो एक विषय है, उस पर चर्चा हो रही है। उसका उत्तर भी आएगा।

प्लीज़, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : सभापति महोदय, रोम के एक फिलॉसोफर का यह वक्तव्य है - "A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gate is less formidable, for he is known and carries his banner openly". But the enemy who speaks slyly, what is that enemy?

महोदय, जिनके पास न नीति थी, न नीयत थी, न देश के प्रति निष्ठा थी, जो न कभी हिन्दू के हुए, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, जिन्होंने न ही सिखों के साथ इन्साफ किया, जो न कभी महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित थे, जो न नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे, जो न किसानों के बलिदान को स्वीकार कर किसान की समृद्धि के लिए समर्पित थे, आज उनसे कहना चाहती हूं कि जो समर्पित है, जो सबके विश्वास के साथ सबका विकास कर रहा है, उस पर देश पुन: विश्वास दिखाएगा, वर्ष 2024 में पुन: मोदी सरकार बनाएंगे।… (व्यवधान) महोदय, इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं निषेध करती हूं और भारत माँ का जयकारा लगाते हुए जो भारत माँ की हत्या की बात कर रहे थे, उनसे कहना चाहती हूं कि अंग्रेज आए, चले गए, मुगलिया सल्तनत आई, खत्म हो गयी, पर हिन्दुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा, और हिन्दुस्तान इस देश की तिजोरी की चाभी वापस उनकी माता जी के हाथों में नहीं देगा।… (व्यवधान) (इति)

(1340/SRG/GG)

… (*Interruptions*)…

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Shri Midhun Reddy Ji.

… (*Interruptions*)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, we have a tradition of respecting … (*Interruptions*)… Sir, the House is not in order … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, please listen.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप प्लीज़ बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please cooperate.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, she made a personal comment. … (*Interruptions*)… She is threatening me. … (*Interruptions*)..

HON. CHAIRPERSON: No.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : कोई आवश्यकता नहीं है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You are a very senior Member.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप प्लीज़ बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, there is too much of noise. … (*Interruptions*).. The House is not in order. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्लीज़ बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I want to say something. … (*Interruptions*)

… (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): She is threatening that I am going to be arrested. … (*Interruptions*)..

माननीय सभापति : मैं कार्यवाही में देख लूंगा।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): She said that. … (*Interruptions*)… Does it mean to say that the Supreme Court Bench is under their control? … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : यदि ऐसी कोई बात है तो उसको देख लेंगे।

… (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Whether this Government is controlling the judiciary…. (*Interruptions*)

माननीय सभापति : अब आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी जी, बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़, अब आप बैठ जाइए। इधर के सदस्य भी बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

1342 hrs

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, thank you for giving me the opportunity. … (*Interruptions*).. Our country has a tradition of respecting women. … (*Interruptions*) Even the Vedas says, “Where the women are worshipped, the Gods dwell there.” … (*Interruptions*).. We fondly call our country ‘Mother India’. Such is the respect that we have given for women in our country. … (*Interruptions*).. But the spate of events which have happened in Manipur, the heinous crimes which have happened against women in Manipur, are really painful. … (*Interruptions*).. The Government needs to act swiftly and very tough. … (*Interruptions*).. All this ethnic violence has to be curbed and the women need to be protected … (*Interruptions*).. Both the ethnic groups have to be made to sit together and an amicable solution needs to be brought out. … (*Interruptions*)…

Sir, a combination violence of ethnic violence and gender violence have dented our image globally … (*Interruptions*)… Many people from abroad have called me … (*Interruptions*).. They are asking me what is happening in your country? … (*Interruptions*).. What are these horrific incidents happening in your country? … (*Interruptions*).. Sir, it is very shameful that these incidents are happening in our country … (*Interruptions*). In a country where we preach unity in diversity, we should not let such incidents happen … (*Interruptions*).. Manipur might be a small State … (*Interruptions*).. There might be just two MPs from Manipur, but it does not mean that Manipur is not a part of the country … (*Interruptions*)… We need to act very tough. … (*Interruptions*).. It is the responsibility of our Government that peace be restored in Manipur … (*Interruptions*)

Sir, all of us should put politics aside and make sure that peace is restored in Manipur. Not only Manipur, any communal clashes, any issues, any ethnic fights between minority and majority groups, all these have to be sorted out … (*Interruptions*)… Otherwise there is no meaning of democracy … (*Interruptions*).. I think we should preach what we believe that unity is of foremost importance for the progress of our country. … (*Interruptions*)

Sir, there should be a two-stage approach to sort out this problem. One, enough forces need to be deployed and peace has to be restored there. Secondly, we should address the source of the problem … (*Interruptions*).. If Meiteis have to be given reservation, it has to be done through meaningful dialogues … (*Interruptions*).. All the stakeholders need to be brought together and a logical conclusion has to be reached.

Manipur, as such is called the jewel of India. Manipur is surrounded by nine mountains with an oval shaped valley. We need to protect this jewel. Manipur is like a gateway to the country. It shares its border with Myanmar. If we have a weak Manipur, if we have a weak border, it is not good for the safety of our country. We have seen what happened in the North East. We have seen the Chinese intrusion. We cannot let one more incident like that happening. A strong Manipur means a strong India. Peace has to be there in Manipur.

Sir, I would like to be very brief. I would like to confine myself to the issue of Manipur. YSR Congress Party believes that this No-Confidence Motion does not carry much value because the Ruling NDA has an absolute majority.

(1345/SMN/MY)

Sir, we believe that this No Confidence Motion should not be used for settling our political differences. We do not want to be a part of a tussle between two alliances. I would like to reiterate and we urge the Government to sort out this Manipur issue as soon as possible. Peace has to be restored there. A strong Manipur means a strong India. In the interest of the country, peace has to be restored there and we urge the Government to act with all their might and make sure peace is restored at the earliest.

With these words, we oppose this No-Confidence Motion.

Thank you very much.

(ends)

1346 बजे

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): सभापति महोदय, श्री गौरव गोगोई जी द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव सदन में लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। गौरव गोगोई जी ने मणिपुर की हिंसा के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। हम लोगों को तब आश्चर्य होता है, जब मणिपुर इस देश का पूर्वोत्तर राज्य है। यह महत्वपूर्ण राज्य है। वहां डबल इंजन की सरकार है। जब वहां की हालात पर चर्चा होती है, तो सत्ता पक्ष के जो लोग है, वे विभिन्न राज्यों की छिट-पुट घटनाओं की चर्चा करके इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मणिपुर को आप इतने हल्के में न लें। आज मणिपुर में जो घटना हुई है, कल मिजोरम में होगी, परसों नागालैंड में होगी, पूर्वोत्तर की आपकी पूरी सीमा उससे प्रभावित होगी। आप इसकी गंभीरता ही नहीं समझ रहे हैं। आज मणिपुर की हालत बहुत खराब है। उसकी गंभीरता के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। यहां लंबे-लंबे भाषण हो रहे हैं, लेकिन मणिपुर की गंभीरता और उसकी स्थिति के बारे में किसी ने एक शब्द भी बोलने का कष्ट नहीं किया। उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मैं भी मणिपुर गया था। वहां दो समुदायों के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है, एक-दूसरे के प्रति इतनी घृणा फैल गई है कि उसको पाटना बहुत मुश्किल है। इसे जितने हल्के में आप कह रहे हैं, उसको आप पाट नहीं सकते हैं। आज दोनों समुदायों के लोगों में विश्वास की कमी है। हम लोग दोनों समुदाय के राहत शिविरों में गए थे।

महोदय, दोनों समुदाय के लोगों का विश्वास राज्य की सरकार के प्रति समाप्त हो गई है। दोनों समुदाय के लोग आज राज्य सरकार को पूरे मणिपुर की घटना के लिए दोष दे रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? विपक्ष ने क्या माँग की थी? आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तैयार थे, रक्षा मंत्री जी बयान देने के लिए तैयार थे, सभी बयान देने के लिए तैयार थे, लेकिन यह सरकार किसकी है? यह सरकार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। हम विपक्ष के लोग यही चाह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन में बयान दें। तीन मई से आज तक लगातार मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। वहां के जो 150 से ज्यादा लोग मर गए, उनके प्रति संवेदना का एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। इस देश के पूर्वोत्तर के किसी राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों की यही मांग थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएं और मणिपुर के बारे में बताएं। वह मणिपुर के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें, लेकिन उन्होंने कहा-नहीं।

जब राहुल गांधी जी ने कहा कि यह अहंकार का प्रतीक है तो बहुत लोगों को तिलमिलाहट लग गई। आज मणिपुर में बहुत कुछ करने की जरुरत है। मणिपुर के लोगों में विश्वास पैदा करने की जरुरत है। वहां के दोनों समुदायों में विश्वास पैदा करने की जरुरत है।

(1350/CP/RU)

मणिपुर के लोगों को पुनर्वासित करने की जरूरत है। लोग बेघर होकर मई से आज तक राहत शिविरों में रह रहे हैं। राहत शिविरों में गर्भवती महिलाएं रह रही हैं। वहां गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा हो रही है, वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। आप अलग-अलग राज्यों की छिटपुट घटनाओं को जोड़कर कह रहे हैं कि बहुत कुछ है। प्रधान मंत्री जी ने मौन व्रत धारण किया, जरूर किया। प्रधान मंत्री जी इस देश के प्रधान मंत्री हैं। क्या उनका यह दायित्व नहीं बनता है कि किसी राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बारे में हम एक शब्द बोलें? यह क्या है? यह तो वही पुरानी कहावत है, "रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था।"

सभापति जी, हम आपको दिनकर जी की एक कविता सुनाना चाहते हैं-

क्या कहा कि मैं घनघोर निराशावादी हूं?
तब तुम्हीं टटोलो हृदय देश का, और कहो,
लोगों के दिल में कहीं अश्रु क्या बाकी है?
बोलो, बोलो, विस्मय में यों मत मौन रहो ।

यही दिक्कत है। आपको इस देश की जनता ने देश चलाने की जिम्मेदारी दी है। इसीलिए, आज अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा।... (व्यवधान) अभी उस पर आएंगे। आप चिंता मत करिए।...(व्यवधान) चुप रहिए, बैठिए।... (व्यवधान) आपको वह भी बता देंगे।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप बैठिए, सुनिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका जब नंबर आए, तब बोलिएगा। अभी इनको बोलने दीजिए। आप अभी बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : जब आपके पक्ष का नम्बर आएगा, तब आप बोलिएगा। अभी इनको बोलने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिए। आप उधर ध्यान मत दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : किसी और सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। केवल राजीव रंजन जी की ही बात रिकार्ड में जा रही है।

… (Interruptions) … (Not recorded)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): आदरणीय प्रधान मंत्री जी 9 वर्षों से इस देश में शासन कर रहे हैं। 9 साल से इस देश में शासन कर रहे हैं।… (व्यवधान) इस देश की जनता आज अपने आपको छला हुआ महसूस कर रही है। वर्ष 2014 में इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे। वे किसके बल पर जीत रहे थे? इस देश के नौजवानों के बल पर, इस देश के बेरोजगारों के बल पर जीत रहे थे। उन्होंने इस देश से क्या वादा किया था? उन्होंने इस देश से वादा किया था कि दो करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे।… (व्यवधान) नौ साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार का हिसाब दीजिए। 18 लाख रोजगार का भी हिसाब नहीं दे रहे हैं।… (व्यवधान) एक आदमी को रोजगार दिया। एक आदमी को रोजगार जरूर मिला, वह सबसे बेरोजगार था। हम नाम नहीं बोलेंगे कि किसको उन्होंने रोजगार दिया। ये खुद बतायें कि इन्होंने किसको रोजगार दिया। जो सबसे बड़ा बेरोजगार था, उसको भारी रोजगार देकर इस देश का नंबर वन और दुनिया के नंबर तीन पर पहुंचा देने का काम किया। आप ही नाम बताइए कि कौन इतना बेरोजगार था, जिसको आपने रोजगार दिया? इस देश के नौजवानों को तो रोजगार नहीं मिला। हम लोग भी वर्ष 2014 में चुनाव लड़े थे। बेंगलुरु में, महाराष्ट्र में और अलग-अलग शहरों में जो लड़के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, सब अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव आ गए थे। सब अपने घर में बैठ गए थे और अपने अभिभावकों से कह रहे थे कि मम्मी-पापा, मोदी जी को वोट दे दो, हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। क्या रोजगार मिल गया? आज वही लड़के 4-5 हजार रुपये की नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनियों में दर-दर भटक रहे हैं। 18 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ? …(व्यवधान) आप 18 करोड़ लोगों के रोजगार का हिसाब दीजिए।… (व्यवधान)

अभी सदन में रक्षा मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। रक्षा मंत्री जी को मालूम है कि इस देश में जो सेना में नियमित बहाली होती है, उस नियमित बहाली के लिए लाखों नौजवानों ने दौड़ को पास किया।

(1355/NK/SM)

उनका मेडिकल हो गया, उनको नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ कर फेंक दिया गया और चार साल के लिए अग्निवीर बना दिया गया। यही आपका रोजगार के प्रति नजरिया है। रोजगार के प्रति आपका नजरिया कैसा है? यही है आपका रोजगार के प्रति नजरिया।

देश के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में घूम घूम कर भाषण दिए। आप बोलिए कि नहीं बोले थे कि दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर साहस और हिम्मत है तो कहिए कि हमने नहीं कहा था कि दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। काला धन लाएंगे, पूरी दुनिया में जितना काला धन है, उसको लाएंगे और हर गरीब के खाते में दस से पन्द्रह लाख रुपये पहुंचाएंगे। एक आदमी को भी पैसा नहीं मिला। काला धन लाने की बात छोड़ दीजिए, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहूल चौकसी आपकी आंख के नीचे से काला धन लेकर विदेश चले गये। आप बैठे रह गए।

आप देश की जनता को ... (*Expunged as ordered by the Chair*) रहे हैं। देश की जनता को ... (*Expunged as ordered by the Chair*) का काम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी वर्ष 2014 के आम चुनाव के बाद, हमने उनका एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देखा, टीवी चैनल वाले ने देश के गृह मंत्री जी से पूछा कि माननीय गृह मंत्री जी आपने देश में नौजवानों को, दो करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, आपने हर गरीब के खाते में दस से पन्द्रह लाख रुपये भेजने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। उन्होंने क्या कहा, उनका जवाब था कि चुनाव के टाइम में इस तरह के ... (*Expunged as ordered by the Chair*) कहे जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे मोबाइल में इंटरव्यू है अगर आप कहिएगा तो दिखा देंगे। आपके गृह मंत्री जी का इंटरव्यू है, आपको दिखा देंगे। … (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): सभापति महोदय, यह सब धंधा नहीं चलेगा। बीच में कोई पाइंट ऑफ आर्डर के नाम पर खड़ा होकर अनर्गल बात करेंगे। यह सब

नहीं चलेगा। ये सब ... (*Expunged as ordered by the Chair*) हैं। इनके एक नम्बर के मंत्री ने इस देश में कहा कि हम चुनाव में जो वादा करते हैं, वह ... (*Expunged as ordered by the Chair*) होता है।

आज देश में सबसे बड़ी समस्या महंगाई की है। अब आप उज्ज्वला योजना की चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि उज्ज्वला योजना में आपने जितना सिलेंडर बांटें, उसमें से पांच प्रतिशत घरों में वह सिलेंडर नहीं जल रहा है क्योंकि तेरह सौ रुपये और चौदह सौ रुपये सिलेंडर का दाम हो गया है। पहले आप अपनी पीठ बहुत थपथपाते थे। हर भाषण में कहते थे, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना। अब शांति कायम हो गयी है।

आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आजकल आप देश भर में घूम घूम कर भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में महाराष्ट्र में 70 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की चर्चा की। महाराष्ट्र में 70 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, तीन दिन के अंदर सबको वाशिंग मशीन में डालकर एक सेंकड में बाहर निकाल दिया और सभी को सरकार में शामिल कर लिया।

अभी कर्नाटक का चुनाव लड़े थे न? कर्नाटक के चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। प्रह्लाद जोशी जी यहां बैठे हैं। उनको पता होगा। … (व्यवधान) कर्नाटक में चालीस लाख की चर्चा हर घर में थी। हर सड़क पर थी, हर चौक पर थी, हर चौराहे पर थी। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का क्या हक है?

(1400/SK/RP)

वह भी बताएंगे। ... (व्यवधान) चिंता मत करिए, राकेश जी।... (व्यवधान)। वह भी अभी आपको बताते हैं। ... (व्यवधान) अभी हम उसी पर आ रहे हैं। ... (व्यवधान) बैठिए, उसी पर आ रहे हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Hon. Member, please address the Chair.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : कृपया, अध्यक्ष पीठ की तरफ देखकर बात करें।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सिर्फ अपनी बात कहें।

... (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): निशिकांत जी यहां बैठे हैं, कल भाषण दे रहे थे, फंडिंग करते थे, ... (व्यवधान) अरे भाई, किस कंपनी के बिहॉफ पर फंडिंग करते थे, उसका भी तो ज़रा नाम बताइए। ... (व्यवधान) फंडिंग करते थे। ... (व्यवधान) गृह मंत्री जी ने दिल्ली विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा। ... (व्यवधान) बैठिए, आप भी गए थे, कहां गए थे, क्या हम बोल दें यहां? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: ललन बाबू, आप इधर देखकर बात करें।

... (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): नीतिश कुमार जी के यहां गए थे कि भाजपा वाला बहुत तंग कर रहा है, ज्वाइन करा लीजिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बात कीजिए और इधर ध्यान दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): जब हम लोगों का गठबंधन बना, 9 अगस्त, 2022 को, तब से इनको तितली लग गई, तब से इनको भारी तितली लग गई। ... (व्यवधान) पूरा देह खुजला रहा है। ... (व्यवधान) सबकी देह खुजला रही है। ... (व्यवधान)

हम अभी भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे, इनके गृह मंत्री जी कितने बड़े भविष्यवक्ता हैं।... (व्यवधान) वर्ष 2022 में जब गठबंधन हुआ तो तितली लग गई। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह बात ठीक नहीं है। जब आपको अवसर मिलेगा तब आप अपनी बात रखिए। अभी आप सुनिए।

... (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): वर्ष 2015 में जब तीन पार्टियों का गठबंधन हुआ, ये साफ हो गए बिहार से। ... (व्यवधान) वर्ष 2015 में जब बिहार में गठबंधन हुआ, आरजेडी, जनता दल यू और कांग्रेस पार्टी का ... (व्यवधान) तब गृह मंत्री जी ने तीन महीने बिहार में कैम्प किया। ... (व्यवधान) बैठिए, आप दिल्ली के हैं, बिहार के बारे में क्या जानते हैं? ... (व्यवधान) क्या एबीसीडी भी जानते हैं? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बार-बार उधर क्यों देखते हैं? आप इधर देखकर बात करें।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): जब गठबंधन हुआ, तीन महीने गृह मंत्री जी ने कैम्प किया। इस देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 43 आम सभाएं कीं। यह रिकॉर्ड है कि किसी राज्य की विधान सभा चुनाव में 43 आम सभाएं कीं। … (व्यवधान) और सीट आई, 52 … (व्यवधान) जब इनका बस नहीं चला तो इन्होंने लालू जी के परिवार के यहां छापा मरवाने का काम किया।… (व्यवधान) जब छापा मरवाने के कारण वर्ष 2017 में हमारा गठबंधन टूटा तो वर्ष 2017 से 2022 तक कुछ नहीं हुआ। वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक शांति में रहे और इनके तीनों पालतू … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) शांत बैठ गए। … (व्यवधान) जैसे ही 9 अगस्त, 2022 को फिर से गठबंधन हुआ, तीनों … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) चालू हो गए, तीनों … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) दौरा कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार छापा मार रहे हैं। … (व्यवधान) मारते रहो, बिहार की 40 की 40 सीट हमारी हैं।… (व्यवधान)

सभापति महोदय, हम आपको एक बात बता देते हैं कि देश के गृह मंत्री जी बहुत भारी भविष्यवक्ता भी हैं। उनको ज्योतिष ज्ञान है। अभी दिल्ली विधेयक पर कह रहे थे कि वर्ष 2024 में फिर से नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री बनेंगे। अब हम आपको इनके ज्योतिष ज्ञान के बारे में बताते हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

(1405/KDS/NKL)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : आप कृपया बैठ जाइए। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। जब आप बोलिएगा, तब रिकॉर्ड में जाएगा।

…(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): महोदय, वर्ष 2015 में गृह मंत्री जी ने भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन बिहार के चुनाव की गिनती होगी, उस दिन 11 बजे नीतीश कुमार जी त्याग-पत्र देंगे और 12 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। इनकी भविष्यवाणी फेल कर गई। … (व्यवधान) इनकी मात्र 52 सीटें आईं। वर्ष 2021 में जब बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, तो कह रहे थे कि दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे, हार गए। वर्ष 2022 में हिमाचल गए, वहां कहे कि सरकार बना रहे हैं। भविष्यवाणी फेल हो गई। कर्नाटक गए, वहां बोले कि दो तिहाई बहुमत से सरकार बना रहे हैं, हार गए। वर्ष 2024 भी आप जरूर हारेंगे। आपका भविष्य यही बता रहा है। … (व्यवधान)

महोदय, मैं दो-तीन मिनट में कनक्लूड कर दूंगा। गृह मंत्री जी की यही आदत है। बिहार में भी ये तीन दौरे कर चुके हैं। … (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

माननीय सभापति : क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, बताएं।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, इन्होंने कई डिफेमेटरी बातें माननीय गृह मंत्री जी के लिए कही हैं। नियम 352(2) यह कहता है कि वह सदन के सदस्य हैं। बिना नोटिस के इस तरह की बातें, जो बाहर बोली गई हैं, वे यह नहीं बोल सकते हैं। रंजन जी मुझसे ज्यादा वरिष्ठ सदस्य हैं। यहां के नियम-कानून के बारे में इनको ज्यादा जानकारी है, इसलिए जो भी बातें इन्होंने कहीं, वे एक्सपंज कर देनी चाहिए। इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।

माननीय सभापति : ठीक है, उसको देख लेंगे।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): सभापति जी, गृह मंत्री जी तीन बार बिहार गए। पहली बार पूर्णिया में गए। वहां भाषण दिया और कहा कि पूर्णिया का हवाई अड्डा मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया। जनता हंस रही थी कि जिसका काम भी शुरू नहीं हुआ, उसको इन्होंने बनवा दिया। … (व्यवधान) इतना बड़ा ... (*Expunged as ordered by the Chair*) तो हमने देखा ही नहीं। जिस हवाई अड्डे का काम भी शुरू नहीं हुआ, उस हवाई अड्डे को इन्होंने बनवा दिया। ये अध्यक्ष जो बैठे हुए हैं, इन्होंने ही फीडबैक दिया होगा। उसके बाद ये लखीसराय गए। वहां जाकर इन्होंने कहा कि मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया? … (व्यवधान) मेडिकल कॉलेज बनवाया कि नहीं बनवाया? … (व्यवधान) हर घर नल से जल मोदी जी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तीनों सफेद झूठ हैं। मुंगेर के मेडिकल कॉलेज निर्माण में एक रुपया केंद्र का नहीं है। मुंगेर के इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में एक रुपया केंद्र का नहीं है। बिहार में हर घर नल से जल के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से रुपया नहीं लिया। … (व्यवधान) इन्होंने ऑफर किया, लेकिन राज्य सरकार ने ठुकरा दिया और बोला कि नहीं लेंगे। केंद्र सरकार की फितरत है कि राज्य की जब कोई योजना चलती है, तो उसमें कुछ पैसा दे देते हैं और पैसा देकर कहते हैं कि यह तो हमारी योजना है। नीतीश जी ने कहा कि एक रुपया नहीं लेंगे। हम अपनी ताकत पर काम करेंगे। यह काम उन्होंने किया। इनको ... (*Expunged as ordered by the Chair*) ही नहीं आती है। … (व्यवधान) ये लखीसराय में गए थे ,वहां यही बताए होंगे कि मेडिकल कॉलेज बनवा दिया , इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिया, हर घर नल से जल पहुंचा दिया। … (व्यवधान) इस देश के गृह मंत्री जी इसी तरह के बयान करने के आदी हैं। जम्मू-कश्मीर में पीडीपी से कौन-सा समझौता किए थे? आपका नेचुरल अलायंस था क्या?

(1410/MK/SPR)

क्या वह आपका स्वाभाविक गठबंधन था? … (व्यवधान) केवल बात बना रहे हैं और यहां जम्मू एंड कश्मीर का भाषण देते हैं। आपने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया कि नहीं किया? क्यों किया? … (व्यवधान) लालू जी, हमारे साथ रहे हैं और एक पार्टी में रहे हैं। इस पार्टी का निर्माण हम लोगों ने किया था, इसलिए हम लोग रहेंगे।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): आपका खाता बिहार में नहीं खुलने वाला है।… (व्यवधान)

सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। इसी के साथ मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इनकी वर्ष 2024 में विदाई का ऐलान करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। … (व्यवधान)

(इति)

1411 बजे

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे भाग लेने का सौभाग्य देने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के विरोध के लिए खड़ा हूं। आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने देश को अंग्रेजों के लिए आह्वान किया था। उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। वे कम्पेल कर दिए गए और चले गए। भारत से अंग्रेज तो चले गए, मगर भारत में शोषित, पीड़ित, गरीब, दलित और पसमांदा समाज को छोड़ गए।

सभापति महोदय, आजादी के अमृतकाल में एक नया इंडिया गिरोह पैदा हुआ है। वे इसके माननीय सदस्य हैं, जो अभी ... (*Expunged as ordered by the Chair*) रहे थे। इस नये इंडिया गिरोह में कौन लोग हैं?

1413 बजे (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी पीठासीन हुए):

इसमें भ्रष्टाचारी, दूराचारी, वंशवादी और तुष्टिकरण वाली पार्टियां शामिल हैं। … (व्यवधान) रावण का दस सिर था। वही दस नेता प्रमुख रूप से हैं। … (व्यवधान) आप क्यों भागे जा रहे हैं? है हिम्मत तो सुनिए, है ताकत तो सुनिए। … (व्यवधान) ये रावण के दस सिर वाले नेता लोग हैं, जो बैठे हैं। ये 'इंडिया' एलायंस के लोग हैं। … (व्यवधान) ये इंडिया वाले नहीं हैं। ये घमंडिया हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सब बैठ जाइए। आप सब अपने स्थान पर जाइए।

… (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): ललन जी को डांट कर भगा दिया, जाओ नहीं तो नौकरी खत्म हो जाएगी। ये सब नौकरी करने वाले लोग हैं। क्या इनका अपना कोई अस्तित्व है? ये इशारों पर चलने वाले लोग हैं। ये डांट खाने वाले लोग हैं, ये गुलाम लोग हैं। … (व्यवधान) ये क्या बात करेंगे।… (व्यवधान) बैठ जाइए।

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

(1415/SJN/MMN)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : माननीय सदस्यगण, आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। सिर्फ राम कृपाल जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

… (*Interruptions*) … *(Not recorded)*

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र) : महोदय, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले करोड़ों गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और पसमांदा भारतीयों का प्रतीक 'एनडीए' गठबंधन है। जिसके एकमात्र सम्माननीय नेता, देश के गरीब और देश के पिछड़ों का बेटा नरेन्द्र मोदी है। यह फर्क है। यह 'भारत' और 'इंडिया' गिरोह में फर्क है। जो घमंडिया गिरोह है, इसमें कौन लोग हैं? भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। यह फर्क है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बार-बार खड़े मत होइए। आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं? आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र) : महोदय, वैसी परिस्थिति में 'इंडिया' गिरोह के खिलाफ आज के दिन यानी 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। इनको हटाना है, भ्रष्टाचारियों को हटाना है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बार-बार खड़े मत होइए। बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर बैठिए।

… (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र) : महोदय, तुष्टीकरण करने वालों को हटाना है और वंशवादियों को हटाना है। हम लोगों ने वह कार्य आज से प्रारंभ कर दिया है।…(व्यवधान) मैंने हमेशा 'भारत' वाली राजनीति की है। मैंने अपने जीवन के 40-45 सालों में 'इंडिया' गिरोह वाली राजनीति कभी नहीं की है।…(व्यवधान) आपका टिकट निश्चित है। आप चिंता मत करिए।…(व्यवधान)

महोदय, मैं देश की सबसे बड़ी महापंचायत से देश के करोड़ों गरीबों, पिछड़ो, अति पिछड़ों, दलितों और पसमांदा समाज के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं - भारत के नौजवनों देखो, परिवारवादी, भ्रष्टाचारीवादी, तुष्टीकरणवादी वाला घमंडी गिरोह ने आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया है।…(व्यवधान) देख रहा है, विनोद, अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाया गया है? पता है, क्योंकि आपके समाज के बेटे नरेन्द्र मोदी ने पिछले नौ वर्षों में आपके लिए 50 करोड़ जन-धन खाते खोलने का काम किया है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया है। 42 करोड़ लोगों को गरीब मुद्रा योजना से लोन देने का काम किया है। 13 करोड़ घरों में पानी की व्यवस्था दी है।…(व्यवधान)

भारत को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। 13 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। आदिवासी समाज की महिला को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। अगर हिन्दुस्तान की आजादी के बाद किसी ने यह काम किया है, तो वह कोई और नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी ने ऐसा काम किया है। आज देश देख रहा है।…(व्यवधान)

महोदय, यही नहीं, ओबीसी समाज के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाने का भी काम किया है। इसके पहले दलित समाज का राष्ट्रपति बनाने का भी काम किया है। ये सब काम किया है।…(व्यवधान) यही नहीं, केन्द्रीय मंत्रिमंडल में 27 प्रतिशत मंत्री ओबीसी समाज के बनाए हैं। यही नहीं, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा भी देने का काम किया है, जिसके लिए ओबीसी समाज न जाने कितने दिनों से परेशान था।

(1420/YSH/VR)

सर, मैं लंबे काल से सांसद हूँ। यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भारत की संसद में राज्य सभा और लोक सभा के सदस्य प्रतिनिधिमंडल जाया करते थे कि ओबीसी समाज के लोगों को

संवैधानिक दर्जा दीजिए, लेकिन कांग्रेस में ओबीसी के प्रति नफरत थी। उनके दिल में ओबीसी के लोगों के लिए कहां पर जगह थी? ... (व्यवधान) मैं समझता हूँ कि यह तो इतिहास साक्षी है कि ओबीसी के बेटे नरेन्द्र मोदी जी बनते हैं और ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देकर उनके लिए न्याय करने का काम करते हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : माननीय सदस्य, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): यही नहीं उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सभी धरोहरों को पंच तीर्थ का दर्जा देने का काम किया है। केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में नीट में आरक्षण देने का काम किया है। यह पहली बार हुआ है। केन्द्रीय बल में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। कोरोना से मुक्ति के लिए टीका मुफ्त में देने का काम किया है।... (व्यवधान) 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है। वर्ल्ड क्लास सुविधा से लैस रेलवे स्टेशन्स देने का काम किया है। एयरपोर्ट देने का काम किया है। हाईवेज़ देने का काम किया है और वाटरवेज भी देने का काम किया है। यह है मोदी जी की सरकार।... (व्यवधान)

अरे, आप मोदी जी को कहां से निकाल देंगे? मोदी जी तो हिन्दुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिल में बैठे हुए हैं। हिन्दुस्तान का गरीब आदमी आज एक स्वर से कह रहा है और क्या कह रहा है – मोदी, मोदी, मोदी। चारों तरफ, हिन्दुस्तान के कोने-कोने से मोदी, मोदी, मोदी आवाज आ रही है। अरे, क्या करेंगे आप? घमंडिया लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके चाहने से भी मोदी जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप क्या बात करेंगे?... (व्यवधान) मैं अभी अपनी बात पर आ रहा हूँ। मैं इनको एक-एक पाई का हिसाब दे दूंगा। मैं जदयू के लोगों को जानता हूँ। इनके नेताओं को जानता हूँ। ये क्या बताएंगे? ये सब हमसे जूनियर हैं। ये सब जूनियर लोग हैं। ये क्या बताएंगे? कई लोगों ने हमारे नेतृत्व में काम किया है। ये क्या बोलेंगे? इनके नेता ललन सिंह क्या बोलेंगे? मैं आज उनका पर्दा-पर्दा उखाड़कर फेंक दूंगा।... (व्यवधान) ये क्या बात करते हैं? मोदी जी ने वाटरवेज़ दिया, वर्ल्ड क्लास सुविधा दी। रेलवे स्टेशन्स, एयरपोर्ट्स, हाइवेज़ दिए। इतना सब कुछ किया, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं किया। गरीब लोगों के लिए इतना सारा कुछ काम किया, जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं किया, तुष्टीकरण नहीं किया, भाई-भतीजावाद नहीं किया। मोदी जी का कोई है तो हिन्दुतान के 140 करोड़ लोग हैं। मोदी जी अपने लिए क्या करेंगे? मोदी जी तो फकीर हैं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे।... (व्यवधान) मोदी जी का ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही नहीं, मोदी जी तो फकीर हैं और देश की तकदीर हैं। इस तकदीर का आप लोग क्या बिगाड़ सकते हैं? मोदी जी ने नारा दिया 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास'। इस सिद्धांत पर सब चल रहे हैं।... (व्यवधान) हाँ, यह और बात है कि 9 वर्षों के दरम्यान मोदी जी ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो काम किया, उसके लिए वे गाली सुनते रहे।

(1425/RAJ/SAN)

उनको लोगों ने नीच कहा।...(व्यवधान) फिर वे भी सुनते रहे। मौत का सौदागर कहा, फिर भी वे सुनते रहे, मगर देश के गरीब बच्चों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों और पीड़ितों के लिए लड़ते

रहे, काम करते रहे और जब तक ये रहेंगे, तब तक उनके लिए लड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। जितना भी गाली देना है, दे दो, मगर जब तक हम गरीबों के आंसू को पोंछ नहीं देते, उनको आगे नहीं बढ़ा देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। मोदी जी ने यह कहा।...(व्यवधान) गाली देना है, दे दो, दर्द है।...(व्यवधान) मैं इनकी पीड़ा जान सकता हूं।...(व्यवधान) मैं पिछड़ा समाज का बेटा हूं। मैं छोटे किसान का बेटा हूं।...(व्यवधान) मैं जान सकता हूं कि इन नए घमंडियों को क्यों दर्द है? ...(व्यवधान) मोदी जी ने इनके भ्रष्टाचार को बंद किया है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी): आप सभी बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी, तब बोलिएगा।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद मोदी जी को भारत की जनता ने चुना है। जिनकी मां बरतन साफ करती थीं। पिताजी प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते थे।...(व्यवधान) उनका बेटा हिन्दुस्तान की जनता की तकदीर बदलता है। उनके आंसू को पोछता है, तो इन लोगों को दर्द है। कांग्रेस पार्टी को खास तौर पर इसलिए भी दर्द है कि मोदी जी पिछड़ा का बेटा है।...(व्यवधान) मोदी जी गरीबों को अनाज देते हैं। यह और बात है कि बिहार के लोग खा जाते हैं।...(व्यवधान) हम पांच किलोग्राम अनाज देते हैं, तो ये चार किलोग्राम अनाज देते हैं।...(व्यवधान) यही नहीं बिना आइडिया के 'इंडिया' वालों, आपको चीन और पाकिस्तान एवं विदेशी गैंग ने पीएम बनाने की गारंटी दी है, मुझे कुछ नहीं कहना है।...(व्यवधान) मोदी जी को 140 करोड़ लोगों ने पीएम बनाने की गारंटी दी है। यह राष्ट्र धर्म युद्ध है।...(व्यवधान) भारत यानी कि इंडिया और जीतेगा इंडिया और हारेगा घमंडिया।...(व्यवधान)

महोदय, विपक्ष का चरित्र यह है कि उनके खून में राजनीति है।...(व्यवधान) बंगाल में क्या हो रहा है? वे मणिपुर की चर्चा कर रहे थे। हम सभी लोग आहत हैं। मणिपुर की घटना के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी, देश के लोगों ने संवेदना व्यक्त की है। उसे कोई अप्रूव नहीं कर रहा है, उसे करने वाला भी नहीं है। मगर ये मणिपुर को लेकर राजनीति कर रहे हैं।...(व्यवधान) मणिपुर के घाव को भरने का मन नहीं है, ये घाव को उधेड़ने का काम कर रहे हैं। मणिपुर में जो आग लगी है, उस आग में राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता था कि बंगाल में टीएमसी क्या कर रही है? ...(व्यवधान) हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है।...(व्यवधान) ये कांग्रेस पार्टी ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) लोग इनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है।...(व्यवधान) ये लेफ्ट वाले सीपीआई, सीपीएम के लोग, इनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है। अभी हाल में जो चुनाव आया है, उसमें 58 लोगों की जान चली गई है। शहादत लेने का काम किया है।...(व्यवधान) ये जो घमंडिया वाले लोग हैं, उन पर कोई ऐक्शन नहीं। राहुल जी बोल रहे थे।...(व्यवधान) वे पीड़ा में थे।...(व्यवधान) वे दर्द में थे, नाटक कर रहे थे।...(व्यवधान) आप मणिपुर पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। क्या आपको बंगाल की चिंता नहीं है? आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। आपको राजस्थान की चिंता नहीं

है। आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। आपको छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है। आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। आपको बिहार की चिंता नहीं है। आप एक शब्द नहीं बोलेंगे।... (व्यवधान)

(1430/KN/SNT)

महोदय, बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। मां और बहन की इज्जत तथा आबरू जा रही है। बिहार में भय का वातावरण पैदा हो गया है।... (व्यवधान) बिहार में रोज हत्याएं, लूट, अपहरण की घटनाएं घट रही हैं। हमारे कटिहार में बिहार की बेटी को नग्न अवस्था में घुमाने का काम किया।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : श्री राम कृपाल जी, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): इन्हें बिहार की चिन्ता नहीं है।... (व्यवधान) ललन बाबू चले गए। वह दलित समाज की बेटी थी, उसके लिए चिंता नहीं है।... (व्यवधान) ये बहुत परेशान हो रहे हैं। इन्हें बिहार की चिन्ता नहीं है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इन्हें बिहार की चिन्ता नहीं है।... (व्यवधान) ये नौकरी की बात कर रहे हैं। 10 लाख नौकरियां देने की बात कही गई थीं।... (व्यवधान) इनके एक नेता ने कहा, जिसके अलायंस में हैं, कि हम आने के साथ अपनी कलम से पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे।... (व्यवधान) वे नौकरियां कहां गईं? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राम कृपाल जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): ये जुमले की बात कर रहे हैं।... (व्यवधान) हमारे नेता के बारे में जुमले की बात बोल रहे हैं। वे नौकरियां कहां गईं? क्या इनका पेन भूल गया है, जिससे आपने कहा था कि नौकरी देंगे। एक झटके में पेन भूल गया।

महोदय, यहीं नहीं, दरभंगा में जब दलित का शव जाता है तो उस पर अभद्र व्यवहार किया जाता है। मुझे कहने में शर्म आ रही है कि दलित का शव जा रहा है तो कुछ लोगों ने उस पर पेशाब करने का भी काम किया है। इन लोगों को शर्म नहीं आएगी।... (व्यवधान) राजीव रंजन जी को शर्म नहीं आएगी, ये शर्मसार नहीं होंगे। पटना जैसी राजधानी में 30 दिन में 30 हत्याएं हुई हैं, इनको शर्म नहीं आएगी। जब हम शिक्षक के इश्यु को या बेरोजगारी के इश्यु को लेकर जाते हैं, जो इनका अनाउंसमेंट है, तो ये गोली की बौछार करते हैं, लाठियों की बौछार करते हैं। हमारे कार्यकर्ता को जान गंवानी पड़ी है। विजय सिंह, जो जहानाबाद से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे। इन्होंने मारकर उसकी जान ले ली। महिलाओं को भी नहीं बख्शा, एमएलए, एमपी को भी नहीं बख्शा। यह लाठी और गोली की सरकार है।... (व्यवधान) सर, सांसद जी यहां बैठे हैं। आप खड़े हो जाइये। आप उसका यह नजारा देखिये कि किस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है?... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राम कृपाल जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सर, समाप्त कैसे करेंगे, अभी तो बहुत सारा बाकी है। सर, यह गोली की सरकार है।

सर, यही नहीं, भारत सरकार तो बहुत बिजली दे रही है और बहुत उपलब्धता है। जब किसान बिजली के लिए जाता है तो उसको गोलियों से मारकर लाश बिछाने का काम करते हैं। यह हत्यारी सरकार है। नीतीश कुमार जी की सरकार ... (*Expunged as ordered by the Chair*) सरकार है।... (व्यवधान) बिहार के कटिहार में यह घटना घटी है। हमारा एक कार्यकर्ता निलेश जीवन और मौत से गुजर रहा है। उसकी दिनदहाड़े हत्या करने की कोशिश की है। उसका एम्स में इलाज चल रहा है। सर, अनेकों कहानियां हैं। हर दिन हत्या, हर दिन लूट, हर दिन अपहरण, हर दिन चोरी, हर दिन डकैती और इन्होंने क्या किया है, इनकी गोली कार्यकर्ताओं पर चलेगी।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राम कृपाल जी, आप अपनी महत्वपूर्ण बात रखकर समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सर, इनकी गोली आम लोगों पर चलेगी, शिक्षकों पर चलेगी, इनकी लाठी चलेगी। ये क्या कर रहे है?... (व्यवधान) ये सब तो शराबबंदी के पक्ष में हैं। इनका पुलिस पदाधिकारी केवल कलैक्शन कर रहा है। भ्रष्टाचारी पदाधिकारी बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है। आप ऊपर से नीचे तक चले जाइये, पैसा दो काम लो।

महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि नौकरी मांगेंगे तो ये ठेंगा दिखायेंगे। मैं अभी बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण सुन रहा था।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राम कृपाल जी, आपका समय समाप्त हो गया है। आप कन्क्लूड कीजिए। मैं दूसरा नाम अनाउंस कर रहा हूं।

... (व्यवधान)

(1435/VB/KKD)

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Kindly conclude your speech in two minutes.

... (*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): एक क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को लोक-लज्जा का ज्ञान दे रहे थे। यह कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष? ... (व्यवधान) ये कौन लोग हैं? ... (व्यवधान) ये लालू जी की बात कर रहे थे।... (व्यवधान) सर, मैं लालू जी के साथ था और लम्बे काल तक था।... (व्यवधान) मैं उस लालू जी के साथ था, जो गरीबों की बात करते थे, मैं उस लालू जी के साथ था जो लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी के उसूलों पर चलते थे। मैं उस लालू जी के साथ था, जो सामाजिक न्याय की बात करते थे। मैं उस लालू जी के साथ था, जो कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं जनम लेता है, मैं उस लालू जी के साथ था।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका समय समाप्त हो चुका है।

... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सर, प्लीज थोड़ा समय दे दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं-नहीं, आपका समय पूरा हो गया है। अभी अन्य बहुत-से वक्ता शेष हैं। अब आप कंक्लूड कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): मगर मैं देख रहा हूँ कि सामाजिक न्याय के बारे में बोलने वाले लोग पारिवारिक न्याय में बदल गये। जो गरीब की झोपड़ी में थे, वे महल में चले गये। उनकी आवाज़ बदल गयी, उनके विचार बदल गये।... (व्यवधान) परिवारवाद के चक्कर में सारा काम खत्म हो गया, परिवारवाद के चक्कर में देश को बर्बाद करने का काम किया।... (व्यवधान) अब वही लालू यादव जी कहते हैं, वे मेरे आदरणीय नेता थे, इसलिए सम्मान है और सम्मान रहेगा, अब वे कह रहे हैं कि रानी के पेट से राजा जनम लेता है और वोट के राज का मतलब वोट का राज होता है। वे पहले कहते थे- छोट का राज, वोट का राज। यह है परिवर्तन।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : धन्यवाद। अब मैं दूसरा नाम एनाउंस कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सुनिए सर, ये जो राजीव रंजन जी हैं, लालू जी को अगर किसी ने जेल भिजवाने का काम किया है, इस उम्र में, इस परेशानी में, अगर किसी ने उनको जेल में डालने का काम किया है, तो वह ललन सिंह हैं, जो आज लालू जी की दुहाई देने का काम करते हैं।... (व्यवधान) वे क्या बात बोलेंगे? ... (व्यवधान) नीतीश कुमार और ये, इन दोनों ने मिलकर लालू जी को बर्बाद करने का काम किया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती काकोली घोष दस्तीदार जी।

... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सर, मैं कृषि पर बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूँगा। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा।

माननीय सभापति : आप कंक्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): महोदय, किसानों के लिए मोदी जी ने अभूतपूर्व काम किया।... (व्यवधान) पहली बार किसानों के लिए उनकी फसलों की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य तय हुआ। पहली बार किसानों के बैंक खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सुनिश्चित हुआ, पहली बार किसानों को ई-नेम के रूप में राष्ट्रीय मंडी मिली है, पहली बार किसानों को फसल बीमा योजना से सवा लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवज़ा मिला है। पहली बार अभियान चलाकर किसानों को फसलों के बीजों की नयी वेरायटी दी गई है। पहली बार पशु-पालकों और मछली-पालकों को... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : अब आपकी बात समाप्त हो गई।

श्रीमती काकोली घोष दस्तीदार जी।

1438 hours

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Jai Hind. Jai Bangla. My respect goes to all the Adivasi people today on the occasion of All India Adivasi Divas. My respect goes for the martyrs of the Quit India Movement today.

'Khurumjari!' (Namaskar!) How are you Manipur? How are you Bharat? Not well. Not well, at all. There is darkness everywhere.

The first speaker and all the other speakers of the Treasury Benches have proven that they are not bothered about what is happening in Manipur. They have not spoken about Manipur. वे केवल अपनी सत्ता का ढिंढोरा पीट रहे थे। मणिपुर में जो हत्या हो रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं, एक ने भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया।

Hon. Chairman, Sir, I stand here on behalf of All India Trinamool Congress with gratitude towards my Chairperson and leader, Ms. Mamata Banerjee, who sent the first team to Manipur. I was included in that team, and we visited Manipur on 19th July. But my leader was denied permission to visit Manipur on 3rd June when she wanted to visit there and be with the people of Manipur who were suffering so much. She was denied permission.

(1440/AK/PC)

She was not allowed to stand by the strife-torn people of Manipur and help bring back the normal state of affairs. She wanted us to go on 19th July. For INDIA alliance, the glorious alliance striving to bring back democracy to our beloved motherland, hon. Member, Gaurav Gogoi ji has brought this No-Confidence Motion here against the present dispensation. I support it.

The 'Double Engine Government' as they call it has failed completely to save the people from the manslaughter, the mayhem, the lawlessness that has seen nearly complete destruction of our country, our States. Our Delegation had met the hon. Governor in Manipur, and she said that till that day, that is 19th of July, 57,000 to 58,000 people had lost their homes. They were living in relief camps. Babies were being born in relief camps; mothers were undergoing labour pain in relief camps; there was no doctor; there was no medication; there was no sanitary napkin; there was no food; there was no drinking water; and there was no baby food. So, that was Manipur in the relief camps. And the Treasury Benches did not have the guts to talk about it here since the No-Confidence Motion started.

Nearly, 5,000 to 6,000 houses have been burnt there, and women have been tortured, molested and gang raped. One unfortunate gang rape had seen the entire nation come out as one. I do not want to mention it, but this beheading, we have seen videos in which girls were caught by their hair and their throats were slit. All girls

should know about these gang rapes. There were two girls hiding in a car wash. They were hiding without food and water for two to three days to avoid these terrorists. They were dragged out from there and gang raped. All this has been covered up by this Government here. The net was blocked, and the media was so manipulated that the nation hardly got the information till we went there. … (*Interruptions*)

Do not disrespect me. I am talking. … (*Interruptions*) The 'Sage Bard' whose Death Anniversary we celebrated yesterday … (*Interruptions*) You do not even know who our 'Sage Bard' is. The 'Sage Bard' of Bengal whose Death Anniversary we just celebrated yesterday had said:

"*Durbolerey rokkha karo, durjonerey harao"*

It means, "Protect the weak and hit out at the enemy/evil". This Government has failed to do that.

Whose agenda is it? Whose design is it? India wants to know. The nation is seeing an unforeseen betrayal of democracy, indifference to respect for individual liberty, deafness and blindness to the cries of the tormented not only here, but all over the 10 States of the 'Double Engine Sarkar'. I would say, like too many cooks spoil the broth, too many engines spoiling the States.

डबल-इंजन सरकार काम नहीं कर रही है। … (व्यवधान) We need one engine and one driver. Like West Bengal is surging forward under the leadership of our Chief Minister. … (*Interruptions*) The Centre-State equation is being devastated. … (*Interruptions*) States having Government run by Opposition Parties are being denied their rightful dues as we are experiencing in West Bengal where Rs. 7,000 crore of labour's money in the MNREGA -- who have worked in the fields -- has been denied. The roof on top of the head through Awaas Yojana for the poor people has been denied. So, this is the Government that has denied it to the States being ruled by the Opposition Governments. … (*Interruptions*)

Just a few days back we saw vehicles and houses burning in Haryana. The whole country is burning. Another 'Double Engine' failure in Haryana. … (*Interruptions*) In Manipur, about 70,000 to 80,000 Central Armed Forces/Police have been deployed, but every second day there is more killing, more arson, more deaths, and more rapes. This is war.

(1445/UB/CS)

It is a civil war. A Government which cannot control a civil war has no business to remain in power. Is this a civil war or a war designed and manipulated from outside wherein our Arunachal Pradesh is at stake, Manipur is at stake, where it is also spreading to Mizoram which is close to Andaman & Nicobar Islands and the Coco

Islands? … (*Interruptions*) Try to understand and do not disturb. What is happening in Coco Islands? … (*Interruptions*)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप भी बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Sir, Galwan Valley saw it. My question is whether the dispensation is ready to answer what is happening in the Coco Islands near the Andaman & Nicobar Islands, who is doing it? … (*Interruptions*) Why is the Government not taking any action? Is it because the Government came to power in 2017 in Manipur with their help? We know who it is. So, the Government has to be careful. The Government has to answer. We would request the hon. Prime Minister to come and answer this instead of giving us a report card of their performance.

Mizoram is following suit. One class of people is being thrown out of Mizoram. What force are we fighting against? How are the sophisticated M-16, AK-47, grenades and self-loaded rifles coming into the hands of the common man? … (*Interruptions*) Freely available weapons are going to move throughout the North-East and I fear they might find a way into the West Bengal State also. So, we have to be careful about this. Six lakhs of ammunition have been stolen from the police and the State armouries. Was it in connivance with the State Government? Is this an ethnic cleansing operation? What is the master plan to counter it? The Kaladan Project must be given a serious thought. Do you remember the Kaladan Project? More than 4000 arms have been reportedly looted from the armoury. Was that in connivance? Brother is killing brother. Sisters are being bloodied. I will just quote:

यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है,
अश्रु, स्वेद, रक्त से,
लथपथ लथपथ लथपथ,
अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।

INDIA Alliance promises to be with democracy, with federalism, and with respecting the Indian Constitution.

तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी,
तू न मुड़ेगा कभी,
कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ,
अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।

I quoted Harivansh Rai Bachchan ji. Just remember those words. We in India make a promise to stand by the tortured, for peace. I appeal to all the mothers and sisters, and quote Mulayam ji, an hon. Member who used to sit right here but he is no more with us. He said, " माँ-बहनों हमला बोल"। I appeal to all the mothers and sisters of this country, बलात्कारी पर हमला बोल, बेअदबी पर हमला बोल, हत्यारे पर हमला बोल। … (व्यवधान) बेरहमी पर हमला बोल।… (व्यवधान) बोल मेरी माँ हमला बोल,… (व्यवधान) चल आँसू पोंछ,… (व्यवधान) हमला बोल।… (व्यवधान) बलात्कारी पर हमला बोल।… (व्यवधान)

My mothers and sisters of this country, let your curse burn the tormentor! Mothers, be angry, be very, very angry! Let your eyes be fire and vanquish the tormentors, and the rapists that this Government has failed to punish! Why does the Government not open its mouth? Why does the Government not speak about Manipur? Why is the Government giving a report card? This is not election time.

(1450/SRG/RV)

Forget about the elections, talk about Manipur. … (*Interruptions*)..This No-Confidence Motion is against this Government for the poor Human Development Index. This No-Confidence Motion against this Government is for the poor media freedom. This No-Confidence Motion is moved because of rising unemployment. This No-Confidence Motion here is due to the increasing price rise. It is due to increasing farmers' suicides. It is due to the selling of the public sector undertakings. This No-Confidence Motion here is for the divisive forces that are trying to destroy our country. The Government is trying to bring the nation towards complete failure to protect the ethos of India. Is it narcoterrorism that is happening in Manipur? According to Archaeological Survey of India, some very precious metals have been found in the hills of Manipur. Is it to take the corporates right up to Manipur and hand over those precious metals to the corporates? Is the war because of that? … (*Interruptions*) I am quoting the hon. Chief Minister who says that in 2017, the poppy was grown on 1,853 acres of land. As of 2022, the poppy is being grown on 6,743 acres. With whose connivance was it done? Who is supporting them? The hon. Chief Minister himself has said that the problem is due to illegal immigrants. Who are these illegal immigrants? Where are they coming from? Which country is abetting them? Which is the porous border through which they are coming? … (*Interruptions*) Why is the Central Government not closing that border? … (*Interruptions*) And we have to be careful that not only Manipur, as rightly said by hon. Member Gaurav Gogoi Ji yesterday, the total North-East India is lying absolutely vulnerable to the forces that might walk right through that porous border. … (*Interruptions*) That is why, the Kaladan project! … (*Interruptions*) All the seven sisters, all the seven States there

are at danger. Why is the Government not taking care of places? Arunachal Pradesh, half of it is gone. Leh, half of it is gone. Galwan Valley, half of it is gone. Why is it happening? Is it because you have taken help of terrorist groups during the elections that you are keeping quiet and you are praying for further elections to take the help of the terrorist groups? The people of India want to know this. … (*Interruptions*)..कि हमें महफूज़ रखने के लिए जो निगरानी होनी चाहिए थी, देश में वह निगरानी क्यों नहीं है, इस प्रश्न का जवाब सरकार को, सत्ता पक्ष को देना चाहिए। What happened to their attack on the Assam Rifles convoy? Who did it? Who engineered it? … (*Interruptions*).. Such animosity and hatred are brewed among brothers that have lived together. … (*Interruptions*).. This cannot be spontaneous and the Government has failed to control it. So, we have no confidence in this Government. … (*Interruptions*).. Houses have been burnt, *mandirs* have been burnt, temples have been burnt, 350 churches have been burnt. So, in the amber glow of the burning hurts, let us seek light, let us pass the No-Confidence against this Government now. … (*Interruptions*).

Jai Hind! Jai Bharat!

(ends)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): माननीय सभापति महोदय, चूंकि सरकार के खिलाफ, मंत्रिपरिषद् के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव आया है, मैं देश के सामने कुछ स्पष्ट करना चाहती हूं। यहां मनरेगा से संबंधित प्रश्न उठाए गए हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि पूरे देश के लिए एक नियम है, चाहे कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य के साथ हम पक्षपात नहीं करते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को अवगत कराना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ। मेरे मंत्रालय ने नहीं, बल्कि इनके अधिकारियों ने इसे स्वीकार किया। हमने कहा कि उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मनरेगा को इसलिए रोका गया है कि हम मनरेगा को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे। वहां प्रधान मंत्री आवास योजना को 'बांग्ला आवास योजना' के नाम से दिया गया। हम उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। देश के कोने में कहीं भी यदि मनरेगा में लूट होगी तो हम उस पर रोक लगाएंगे। पारदर्शिता से काम करें, हम देने के लिए तैयार हैं। (इति)

(1455/SMN/GG)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Thank you, Sir.

I would like to start with a quote of Babasaheb Ambedkar: "Let us not forget that this Independence has thrown on us great responsibilities. By Independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong" . In this case, I think it is often the Congress. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves.

Sir, On behalf of the INDIA team and my Party DMK, I rise to support this No-Confidence Motion brought by INDIA. and by Shri Gaurav Gogoi.

Sir, for the first time in India, the Judiciary had to intervene to protect a State. Is it not a shame?

Sir, the Government proudly says that in Manipur, it has a double engine Government because it is the BJP Government at the Centre and it is the BJP Government in the State. But this double engine has become a double-edged weapon against the people of Manipur, a double disaster and a double break-down. The PM after returning from his trips abroad chooses to speak to the media in a very rare occurrence outside the Parliament but he refuses to cross the threshold and come to Parliament and speak with fellow Parliamentarians. A senior leader Yashwant Sinha day before yesterday in his article had mentioned, democracy is not defined by the beauty of its Parliament building, it is dignified by the quality of its debates and the voice with which it speaks in unison on national issues. Today, INDIA team is speaking in unison on national issues and you refused and you failed to come here and respond to it.

Sir, 170 people have been killed, thousands injured, 60,000 displaced, 3,500 homes have been burnt. People have been killed. As dear Kakoli mentioned, people have been beheaded but when the Chief Minister of Manipur was asked, why he has not been able to control the situation for three months, the Chief Minister said that two brothers are fighting and the Government is like a father mediating between them. Is this not a shame?

The State of Manipur is with a heavy security blanket. The State of Manipur has the highest ratio of police personnel to civilians in India. Now, 161 companies of Central forces including Assam Rifles are present in Manipur and yet, the Government has failed to protect the people.

There is silence of the Union Government and the Prime Minister and inaction of the State Government which watched as houses burned, police armoury was looted and people killed each other, women were being humiliated, stripped, paraded, raped, violated and killed, this double engine stood hand in hand watching there. It said brothers are fighting. The videos of these two women who were paraded naked and raped shook the conscience of the nation and the world. The 21-year old girl's father and brother were killed when they were trying to protect her.

Sir, when the mob caught this family, they ran to police gypsy which was there. They begged them to take them in the gypsy to somewhere safe but the policemen refused. When they got into the gypsy, they allowed the mob, the violent mob to pull these two women out and the father and brother out of the gypsy and the policemen were watching in silence. The father and brother were killed and these two women were stripped.

The National Commission for Women and the State Women's Commission were all silently watching, maybe they were wishing that this will miraculously vanish till unfortunately, the videos went viral.

(1500/RU/MY)

And after many weeks and months, five or six people out of the mob were arrested. But time and again, these women were asking as to why no action was taken against the policemen who handed them over to the violent mob. But till yesterday, the Government chose to keep silent and it did not respond.

People have mentioned Draupadi in this House..… (*Interruptions*)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी): माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी बात कहिए।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): जब वे लोग बोलते हैं तो कैमरा वाले लगातार उनका चेहरा दिखाते हैं। … (व्यवधान) जब 'इंडिया' अलाएन्स वाले बोलते हैं तो कैमरा यहाँ पर नहीं, बल्कि कैमरा आपकी तरफ होता है।… (व्यवधान)

सर, ऐसा क्यों हो रहा है? … (व्यवधान)

माननीय सभापति: ऐसा नहीं है।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, ऐसा ही हो रहा है।… (व्यवधान)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: कनिमोझी जी, आप अपनी बात रखिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Interruptions will not go on record. Only the speech of Shrimati Kanimozhi will go on record.

… (Interruptions) … (Not recorded)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, Members have been mentioning about Draupadi from Mahabharata in this House and how she was humiliated and stripped. These women must have prayed some God to come and help them. Neither God nor the Government came to help these two women. Anybody who has read Mahabharata properly knows that it is not the perpetrators of the crime alone who were punished but the silent spectators who stood there like trees, watching her being humiliated, were also punished. They will be punished as they were silent in the case of Hathras, Unnao, Katra, Bilkis Bano and when the wrestlers were protesting. The country, the nation and the mothers of India will punish them.

Sir, there are hundreds of relief camps but there is no food, no water and they are over-crowded with no proper sanitation. Roofs are leaking and children have to live there. They cry out of fear and hunger. Is this what you call relief camps in this country? You do not want to even reach out to the people who have lost everything, who had to walk for days to save their lives. You cannot give them food, you cannot give them protection, you cannot ensure that their roofs do not leak.

At Bishnupur, a woman said that people are saying that his son has been killed but she has not seen his body. She refused to believe that he has been killed. His best friend has told her that her son was killed. But she refuses to believe that he was killed because she lives in hope. She said that she hopes that, some day, he will come back alive to her. This is not just one mother who is saying this. There are brothers, fathers and families who are waiting with hope that their loved ones are alive somewhere, and even if they are injured, they are there somewhere.

A Meitei girl, in one of the camps, asked me, "You have come to see us. But why has the Chief Minister or the Prime Minister not bothered to visit us? We have lost our homes, families and livelihood. I will never go back to my house. I will never feel safe there. The Government has let me down. Why has anybody not come here to wipe my tears?" But instead of listening to her pain and comforting her, the BJP fake news team manufactures a narrative saying that she told the INDIA Team that she has faith in the Prime Minister and why they have come here.… (*Interruptions*)'

Sir, whether it is the Kukis or the Nagas or the Meiteis, we only saw despair and despondency in their eyes. That is the truth. I request the Prime Minister and the Government to reach out to these people and say that they care for them and justice will be done. Can you not do that much for the people who have been hurt and bleeding?

Sir, we went there to say that INDIA stands with you, and we would like to know whether the Government stands with them or not. The Chief Minister of Manipur has been blaming the Kukis and the Nagas for the drug cultivation there.
(1505/SM/CP)

But a former ASP, Ms. Brinda, blames the Chief Minister, the Chief Miniter's office and the Manipur Government for it. There have been many

stories in the newspapers earlier saying that the pesticides and fertilizers which are being sent to the State are diverted for poppy cultivation and not for food production. Should we not find out the truth? Should not there be a proper inquiry into what has been really happening?

You brought the Sengol to the new Parliament with big pomp and show. You said it is Chola's tradition. You do not know the history of Tamil Nadu properly. Have you heard about the Pandian Sengol, the Pandian Sengol which burnt, which shattered when the King failed the common people? Do you know the story of Kannagi? Please stop imposing Hindi on us and go read the Silappadikaram. It has a lot of lessons to teach you all… (*Interruptions*)

It is okay, they are very scared of us. They do not want to see our faces also. We are happy with it as long as they can hear us. They cannot hear Manipur people. At least, let them hear us.

This Government is very lucky. It knows how to manufacture one issue after another, one disaster after another. So, we have to forget what happened a month ago and discuss something else, a new issue in the Parliament.

We had no opportunity to discuss as to what happened in Balasore in Odisha. Three trains collided, 288 passengers died and over 1,000 passengers were injured. There are bodies still lying in AIIMS Bhubaneswar which are unclaimed and not identified. But the report on the accident says that lapses at various levels in signal and telecommunication department are responsible for the accident. They had been warned, the Government had been warned two months before the accident that there should be an inquiry, and the methods of shortcut being used for signal and telecommunication system in the country has to be looked into.

Today, there are vacancies in operational and safety categories. Over 50,000 people have not been employed. Is it not the fault of the Government? What is your response to the accident? What is your response to the number of people who have lost their lives?

This Government fears and deplores accountability. It hides data and refuses to collect data. When data does not favour them, they sack the person in charge. The Chairperson of NFHS was suspended when he exposed the false claims of the Union Government.

The Minister, Shrimati Smriti Irani, said that India is hundred per cent open-defecation free. There is not one single State which is hundred per cent open-defecation free. It is a total lie and when the concerned person made sure that the truth should come to light, he was suspended.

Sir, the employment data was withheld till the election results were out and the two people in the Commission resigned because of that. The unemployment rate is 8.5 per cent in this country. Investments have dropped to half. Earlier, it was 10.5 per cent. Now, it is 5 per cent. People are going back to agriculture. More than 50 per cent people are there in the agriculture. This does not happen in any developing nation. People are going back to agriculture because they have no hope, there is no space for them in formal employment.

National policy for rationalisation of schools has closed down thousands and thousands of schools, and millions of children have lost their opportunities to go back to the schools… (*Interruptions*)

(1510/RP/NK)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी): आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: कनिमोझी जी, आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: दानिश अली जी, आप अपनी जगह पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्रीमती कनिमोझी जी, आप अपनी बात रखिए।

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, whenever somebody from the Opposition speaks, the camera is not on us, it is somewhere else. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: कनिमोझी जी, आप बोलना चाहती हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: कनिमोझी जी, आप आगे बोलिए, आप शुरू कीजिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We have taken note of it.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, you have to give me extra time.

I want to know from the Government whether they want to close down the schools because only the students of SC, ST and OBCs go to these Government schools. In a reply to Rajya Sabha, the Union Minister of State has stated that 25,593 students belonging to the SC, ST and OBC communities have dropped out of Central Universities. Is this the India you are talking about? Is this the Bharat you proudly talk about where students from suppressed communities cannot go to the Central Government institutions and study there? Is this not discrimination?

We have been, time and again, threatened in this House with ED. It is not only the Opposition parties but the Media also which has been threatened by this Government. The Government creates a framework that exposes its own people to conditions of unfreedom and subject them to state brutality. Between 2014 to 2020, 7000 people have been charged with sedition and most of them are below the ages of 30 years. Is this not a matter of shame?

The Prime Minister calls the differently-abled people ‘Divyang’, but the pension which this Government gives them per month is Rs. 300 which is equal to one kilo of tomato in your Government. It is not only the prices which are rising in this Government, it is the crime against women which has risen to 26.3 per cent in the past few years in the BJP Government. This is a Government which is indifferent and its administration is indifferent to people. They do not value people. Do they care about the well-being of the Indian citizens? The irony is that the Government calls itself nationalist and calls us anti-national. Are they nationalist? Do they care about this country? Do they care about the people of Manipur, the women, and the children there who suffer every day? Till today, they have not been able to bring peace to that State.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now. Your time is over.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, they are hurting Mother India and making her bleed every day. India will teach them a lesson very soon.

Thank you. (ends)

माननीय सभापति: श्री नामा नागेश्वर राव जी।

… (व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, there is a point of order. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Under which rule are you raising the point of order?

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, it is regarding the Lok Sabha Television. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: ऐसा कोई रूल में नहीं है। श्री नामा नागेश्वर राव जी।

… (व्यवधान)

(1515/NKL/SK)

1515 hours

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Hon. Chairperson Sir, on behalf of BRS Party and my leader, KCR *Garu,* I thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of No-Confidence in the Council of Ministers. … (*Interruptions*) हमें स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए हैं। 75 सालों से सब मैम्बर्स अपनी कांस्टीटुएंसी की दिक्कतें बताते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, कांस्टीट्युशन के आर्टिकल 1 में लिखा है – “India, that is Bharat shall be a Union of States.” यह स्पिपिट ऑफ द कांस्टीट्यूशन है। 75 साल बाद भी इंडिया में अलग-अलग राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, कुछ राज्य आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ आपको अपोज़ करते हैं, आप सैंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं इसलिए आपको सबको इक्वली देखना चाहिए, सही ढंग से देखना चाहिए, चाहे छोटी स्टेट हो या बड़ी स्टेट हो, चाहे वह राज्य आपकी मदद कर रहा हो या आपको अपोज़ कर रहा हो, लेकिन सैंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान पूरे देश की तरफ होना चाहिए। सैंट्रल गवर्नमेंट को सब राज्यों की सेफ्टी और सिक्योरिटी देखनी चाहिए।

महोदय, अब देश में क्या हो रहा है? हम जरूर मणिपुर की भी बात करेंगे। तेलंगाना में पिछले नौ साल से केसीआर साहब मुख्यमंत्री हैं। हमारी पार्टी राज्य में सरकार चला रही है, आपको भी सैंटर में नौ साल हो गए हैं। आप नौ साल से सैंट्रल गवर्नमेंट में हैं और हमारी स्टेट के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। एपीआर एक्ट, 2014 हाउस से पास हुआ था, उसके अनुसार हमें कांस्टीटुएंसी खम्माम में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाना था, काजीपेट में कोच फैक्ट्री लगानी थी, लेकिन आप यह कोच फैक्ट्री महाराष्ट्र लेकर चले गए, कोच फैक्ट्री गुजरात लेकर चले गए, हमें कोच फैक्ट्री नहीं दी, हमारे यहां वैगन रिपेयर वर्कशॉप बना दी। इसी तरह से आईआईएम देना था, लेकिन हमें नहीं दिया। एक्ट में ट्राइबल यूनिवर्सिटी देने का वादा था, वह भी कम्पलीट नहीं हुआ। पूरे देश में सबको मेडिकल कॉलेज दे दिए लेकिन तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। … (व्यवधान) हमारे दोस्त निशिकांत जी, उनकी कांस्टीटुएंसी में एम्स और मेडिकल कॉलेज की बात बोल रहे थे, लेकिन आप तेलंगाना के साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? तेलंगाना और तेलंगाना के लोग इसी देश में हैं,

तेलंगाना भी इंडिया का पार्ट है, फिर क्यों आप तेलंगाना के साथ इस तरह से कर रहे हैं? यहां के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Why are you disturbing him?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Why are you standing up frequently?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Take your seat.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Why are you disturbing him?

DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA (PEDDAPALLE): When any Member is expressing his pain and addressing the grievances of his State, why is the TV focussing somewhere else? … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : फिर आप इनकी जगह बोलिए।

… (व्यवधान)

DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA (PEDDAPALLE): Is it justice? They are disrespecting the Chair, Sir. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप यह गलत कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): एक्ट के अनुसार एक-एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय देना है, लेकिन पिछले नौ साल से हमारे यहां एक भी विद्यालय नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है, हम लोगों ने भी चिट्ठी लिखी है और हाउस में भी कई बार बात की है, लेकिन तब भी एक स्कूल तक नहीं दिया, एक भी नवोदय विद्यालय नहीं दिया।

हम लोगों के लिए पहले कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे। आईटीआईआर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो तेलंगाना को सैंक्शन हुआ था।

(1520/KDS/SPR)

आप लोगों ने सैंक्शन हुए प्रोजेक्ट को निकाल दिया है, उसको कैंसल कर दिया है। आप क्यों हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, यह आपको बताना पड़ेगा। आपको जरूर इसका रिप्लाई देना पड़ेगा। हमारे तेलंगाना की कुछ स्कीम्स को आप कॉपी कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। 'इंडिया' में सबसे पहले तेलंगाना ने हर किसान को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष देने का काम किया है। आप लोगों ने उसको कॉपी किया है, जो अच्छी बात है। 'किसान सम्मान निधि योजना' के नाम पर आपने 6 हजार रुपये किसान को दिए हैं, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। कम से कम आप लोगों ने तेलंगाना को फॉलो तो किया। उसी तरह से हम लोग हरेक घर में फिल्टर्ड वाटर देते हैं। मैं तेलंगाना के किसान का बेटा हूं, मैं गांव में पैदा हुआ आदमी हूं। मैंने बचपन में देखा था कि तेलंगाना में पहले

पीने का पानी नहीं था, सिंचाई के लिए पानी नहीं था। जब गर्मी आती थी, तो मार्च से लेकर जुलाई तक पीने का पानी नहीं था। पीने के पानी के लिए दूर के कुछ गांवों में जाना पड़ता था। उस समय यह कंडीशन तेलंगाना की थी, लेकिन हमारे नेता केसीआर सर ने आने के बाद पूरे तेलंगाना में हर घर को फिल्टर पानी दे दिया है। हमारे इस मिशन को भी आप लोगों ने कॉपी किया है। यह अच्छा है कि आप लोग भी हर घर जल के नाम से हर घर को पानी दे रहे हैं।

महोदय, इसी पार्लियामेंट में हम लोगों का एक प्रश्न था। वह प्रश्न यह था कि देश का कौन सा बड़ा स्टेट हर घर में जल दे रहा है? इसका उत्तर मंत्री जी ने दिया कि बड़े स्टेट्स में केवल एक ही स्टेट तेलंगाना है, जो हर घर में जल दे रहा है। हर घर जल की तरह हमने 'मिशन काकतीय' बनाया। … (व्यवधान)

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): There was no `Point of Order' allowed yesterday also. `Point of Order' cannot be allowed to the Members of the Treasury Benches only. How can it be? … (*Interruptions*) We also asked for `Point of Order'. Every time, permission to raise `Point of Order' is given to Dr. Nishikant Dubey. … (*Interruptions*) How can it be?

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115 यह कहता है कि कोई मेंबर यदि गलत बयानी कर रहा हैं, तो मंत्री ही नहीं, कोई मेंबर भी उसमें सुधार कर सकता है। वह जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 'कालेश्वरम प्रोजेक्ट' में भारत सरकार ने 86 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। वह गलत बयानी कर रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : नामा नागेश्वर जी, आप कृपया अपनी बात रखें।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Why are you so much agitated? आप कृपया इनको बोलने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : नामा नागेश्वर जी, आप कृपया अपनी बात रखें।

… (व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): चेयरमैन सर, 'मिशन भागीरथ' के लिए नीति आयोग ने 24 हजार करोड़ रुपये रिकमेंड करके आपके पास पैसा देने के लिए भेजा, लेकिन एक रुपया भी नहीं दिया गया है। पूरे देश में हरेक राज्य को हर घर जल के तहत पैसा दिया जाता है, लेकिन हर घर पानी देने के नाम पर तेलंगाना को एक रुपया भी नहीं दिया गया है। उसी तरीके से आज के समय में 24 घंटे पावर किसानों को फ्री देने वाला एक ही राज्य है, जो तेलंगाना है। हमारा राज्य 24 घंटे फ्री करेंट देता है। आप भी वह स्कीम पूरे देश में लगा दीजिए। अमेरिका में पावर कट हो सकती है, मगर तेलंगाना में एक दिन के लिए भी पावर नहीं जाती है। जब तेलंगाना नहीं बना था, उस समय वह पूरा अंधकार में था। तेलंगाना बनने के बाद हम लोगों ने 18 हजार 600 मेगावाट का पावर प्लांट लगा दिया है,

जिसकी वजह से हम लोग पंजाब को क्रॉस करके अब नंबर वन हैं। पहले तेलंगाना में जमीन का रेट 2 लाख रुपये प्रति एकड़ था, जो अब 30 लाख रुपये हो गया है।

(1525/MK/MMN)

इसलिए, हम लोग यह मानते हैं कि हमारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं, आप उनको सपोर्ट करें। अगर हम इसी तरीके से देखें तो आपके फेल्योर्स भी बहुत हैं। आपने लोगों से बहुत वायदे किए थे। अभी पर कैपिटा इनकम के मामले में हम इंडिया में नम्बर वन हैं। तेलंगाना आने से पहले हम लोग 12 वें रैंक पर थे। अभी तेलंगाना आने के बाद हम लोग पर कैपिटा इनकम के मामले में नम्बर वन हैं। अभी यह 3,12,319 रुपये है। हम लोग बड़े स्टेट्स में भी नम्बर वन हैं। … (व्यवधान) आपका सपोर्ट नहीं है, फिर भी हम लोग नम्बर वन हैं। हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इसी तरह से सबको सपोर्ट कर दीजिए।

अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे एरियाज में फेल हो गई है। पेट्रोल, डीजल के प्राइस काफी बढ़ गए हैं। उसी तरह से गैस सिलेंडर का प्राइस भी काफी बढ़ गया है। इसी तरह से हर साल दो करोड़ जॉब देने की बात की गई थी। अभी आप लोग नौवें साल में हैं। इस हिसाब से 18 करोड़ जॉब्स मिल जाने चाहिए थे, मगर अभी देश में बहुत अन-एम्पलॉयमेंट है। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए।

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : आप कृपया कन्क्लूड कीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, आप अभी भी कम से कम तेलंगाना को ठीक ढंग से देखिए।… (व्यवधान) न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, न इधर का है और न उधर का है। हम लोग भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के हैं। हम लोग देश के लोगों के साथ रहेंगे। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, मुझे दो मिनट दे दीजिए।

सर, अभी जिस तरीके से मुणिपुर में हुआ है। यह एन्टायर कंट्री में इंडियन पीपल के लिए बहुत ही शर्मनाक है। हम लोगों को विदेशों में अपना सिर झुकाना पड़ रहा है। यह बात हम इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट में उन लोगों ने एक रिजॉल्यूशन लगा दिया है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कन्क्लूड कीजिए। मैं अब सेकेंड स्पीकर का नाम बोलूंगा।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 फॉर्मर जजेज़ की एक कमेटी बनाई है। मैं आखिर में एक बात बोलना चाहता हूं। पन्द्रहवीं लोक सभा में ये लोग उधर थे और वे लोग इधर थे। इधर ऑपोजिशन लीडर सुषमा जी थीं। फारूख अब्दुल्ला साहब भी बैठे थे। उस समय कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हुआ था। उसमें 100 बच्चों की डेथ हो गई थी। हम सारे ऑपोजिशन वालों ने सुषमा जी के साथ गर्वमेंट से डिमांड की थी कि पूरे डेलिगेशन को कश्मीर लेकर चलिए। वे 39 ऑल पार्टी डेलिगेशन को लेकर गए थे। हम लोग तीन दिन जम्मू-कश्मीर में थे। हम लोगों ने सभी सेक्शन वालों के साथ बात की थी। हम लोगों ने एक कांफिडेंस क्रिएट की थी। उससे कुछ न कुछ

फायदा तो हुआ है। उसी तरह से अभी मणिपुर के लिए यही काम प्रधान मंत्री जी करेंगे तो अच्छा रहेगा। … (व्यवधान) हम लोग प्रधान मंत्री जी की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रधान मंत्री जी की बात से शांति आ जाएगी। देश के प्रधान मंत्री जी की बात सबके लिए रेस्पेक्टेबल होगी। इसी वजह से हम लोगों ने डिमांड की है। मणिपुर में तुरंत शांति बहाल करने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी है।

माननीय सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के. सुब्बारायण जी ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका समय खत्म हो गया।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly take your seat. He has already started his speech.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, हमने जो नो कांफिडेंस का नोटिस दिया है, उसी की वजह से ये सब बातें हुई हैं। हम नो कांफिडेंस मोशन का सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।

(इति)

(1530-1535/SJN/VR)

1530 hours

*SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Hon Chairman Sir, Vanakkam. Hon. Members of the Opposition, particularly of the I.N.D.I.A Alliance, have expressed their views in this House. I support and second all the views expressed by them. We have experienced from the rule of this Government during last 9 years that they do not have faith in the democratic institutions and particularly in democracy. The ruling dispensation do not have tolerance towards any resistance from the opposition parties in a democratic way and in a democratic set-up. I wish to cite three examples here. In the morning, Shri Rahul Gandhi delivered his speech in this House. Hon. Minister is there, they have the majority. They could have responded by patiently listening to what he spoke. But they had no tolerance to listen to his speech. They preferred to disturb hs speech by way of interventions. This is not a good practice in a healthy democracy. Similarly what is the need to bring a legislation to snatch away the powers of the elected Government in Delhi? This is a democratic set-up. People elect their representatives to power. People's representatives are the ones who should be powerful. Snatching away the rights and powers of the elected representatives of the people in a democracy shows that the ruling dispensation is not comfortable with the democratic set-up. Similarly, since 20th of last month only one demand was raised in this House. Why was there disruptions or logjam in the House? Who is the Head of the Government? Prime Minister. Prime Minister leads the Council of Ministers. He has the responsibility to give reply to any issue raised in this House. Prime Minister should address this House and give reply on issues raised by Hon MPs. Refusing to accept this democratic demand has led to logjam of the House. This is reflective of the fact that the rulers have no inclination towards upholding democratic values and credentials. Next issue is that of the assurances given by this Government. Why the No-Confidence motion was brought in this House? What was the assurance given by them? They assured to give 2 Crore jobs every year. If that's so they should have given employment for 18 Crore people in last 9 years. The irony is 5 Crore people who were employed have lost their jobs during this period. There is nothing about

---

* Original in Tamil

giving new employment opportunities by this Government. As many as 5 Crore people lost their jobs during this period. MSMEs provide more employment in our country. But MSMEs are in a sorry state of affairs. They are devastated. They are in crisis. Those institutions which provide employment are being destroyed by this Government. But on the contrary the corporate giants are given importance and encouragement. The economic advisor of Hon Prime Minister says that the nation can grow only when Adani and Ambani grow. Who will create wealth in the society? Will the Adanis and Ambanis create? Farmers and workers create wealth in the society. But the Prime Minister says that only the Adanis and Ambanis create and ensure wealth in society. Due to this misunderstanding of their wrong economic policy has led to destruction of our country's economy. I wish to state that the projection of this Government by being corruption-free and their determination to uproot corrupt practices seem to be untrue. PMCares fund was created by using your power. How much amount was collected? What was the spending pattern? In a democratic set-up if we question, why the current PM Office is afraid of answering to our questions? What is the reason? Are they not supposed to answer? It shows their dictatorial attitude. It shows their fascist attitude. A party which was in power for several decades could not collect party funds as much as that of BJP. BJP has collected more than Rs 6000 Crore. How was this amount collected? How much was the amount collected through electoral bonds? Who were the donors? Whether BJP will disclose in this august House the details of funds collected by them? Similarly 14 lakhs and 56000 Crore.

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Kindly conclude.

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Within two minutes I will conclude Sir. Please allow.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): I will conclude. Please allow me to speak. An amount to the tune of 14 lakhs and 56000 Crore have been written off. They said they have not written off anything. Who was benefitted? Farmers and workers are severe distress under this Government. This amount which is written off by the present Government has only benefitted the corporate giants alike Adani and Ambani. This Government snatches away the rights of the

States. BJP is known for its way of creating disturbances due to its intolerance. This is an attempt to induce anger. They have been doing this for long. Minorities, SCs, STs, Muslims, Christians and others are being attacked. They are being attacked in an unprecedented manner. They have not fulfilled any of the assurances given by them. They are into disinvesting PSUs. Who gave them the power to disinvest PSUs.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Pandit Nehru created and the successive Governments protected these PSUs. But the present Government has taken a decision to disinvest these PSUs. This is a wrong precedence. Sir, kindly give me one minute to conclude. There is no relationship between Hindu religion and Hindutva. Whether this word Hindutva is found in the four Vedas namely Rig, Yajur, Sama and Atharvana Veda. There is no word called Hindutva. They have coined a new word Hindutva.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. I am announcing the next name.

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): The foreign policy of Pandit Nehru has been given up. This Government has shown its submissive approach towards USA. As mentioned by Hon Member Shri Dayanidhi Maran, the present ruling dispensation will not even gain sufficient number of seats in this House to qualify themselves to sit atleast in the Opposition benches in the 2024 elections. With this I conclude.

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much.

Shrimati Harsimrat Kaur Badalji.

1539 बजे

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): सर, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस चीज का दुख प्रकट करना चाहती हूँ कि इस सेशन को चलाने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने की जरूरत हुई। क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का यह हाल हो गया है कि इस सदन में कोई चर्चा ही नहीं होती है? अब नो कॉन्फिडेंस जैसे मोशन को लाकर, मणिपुर पर चर्चा करके हाउस काम कर रहा है। यही कारण है कि इस सरकार के पिछले नौ सालों में 16वीं लोक सभा में सबसे कम सीटिंग्स हुई थीं और यह वाली तो मुझे लगता है कि सन् 1957 के बाद सबसे कम सीटिंग्स होंगी। यह बहुत दुख की बात है। Sir, the agenda today, I would say, is not a question of votes; it is a question of confidence. यह सिर्फ एक सिम्पल मैथेमेटिक कैलकुलेशन की बात तो है ही नहीं, क्योंकि मैथेमेटिस से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो इनके पास है। So, the Motion will fall. I think, the key word here is ‘confidence’. क्या इस देश में सबका साथ और सबका विश्वास इनके साथ है या नहीं है? किसके साथ है, इनके साथ या इनके साथ? हकीकत यह है कि आज इस देश के किसान, इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश के माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी हिंदू, सिक्ख, मुसलमान तथा ईसाई, क्या इन सबका विश्वास इनके पास है या नहीं है? Do they have the confidence in this Government? क्या आज के नौजवान और आज की महिलाओं को इस सरकार के ऊपर विश्वास है? अगर मणिपुर की बात करें तो यह बिल्कुल साफ है कि मणिपुर की औरतों का इस डबल इंजन की सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। मैं एक बात कोट करती हूँ।… (व्यवधान) आप कैमरा छोड़िए, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। यह डेमोक्रेसी कहां रह गई है। अब तो कैमरा भी ऊपर से चलता है। सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने on the 50^{th} anniversary of India’s Independence पर इस पार्लियामेंट में कहा था, ‘it is *abhishaap* to take birth as a girl in this country.’

(1540/RAJ/SNT)

सर, कितनी दु:ख की बात है कि आज अमृतकाल चल रहा है। आजादी के 75 साल हो गए हैं और आज भी हम वही एट्रोसिटी को डिसकस कर रहे हैं, जो उस समय डिसकस कर रहे थे। What happened in Manipur is totally shameful. यह ह्यूमनिटी के ऊपर एक कलंक है और इसकी जितनी सख्त निंदा की जाए, वह कम है।

मैं पूछना चाहूंगी की सरकार की माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रही है? ये इस पर बोले, नहीं बोले। ये वहां गए, ये वहां नहीं गए। माइनॉरिटी कमीशन के हेड क्या कर रहे हैं। वे कितनी बार मणिपुर गए हैं, कितनी बार नूंह गए हैं। हमारे पंजाब में, धार्मिक मसलों में इंटरफेयर करने के लिए पूरा टाइम है। उधर जाने के लिए टाइम क्यों नहीं है? मैं हाथ जोड़ कर सरकार से विनती करती हूं कि इस अमृतकाल में राम के लिए धर्म की राजनीति हर इलेक्शन के पहले बंद करिए। यह जहर देश में मत घोलिए। आज हम यहां बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई पर चर्चा करें। इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए हम ये सब काम न करें।

सर, मैंने दोनों पक्षों को सुना है। आज मुझे इतनी हैरानी हो रही थी कि काश बीच में आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया होता। राहुल जी यहां पर बोले। उनके दिल में बहुत दर्द था। उन्होंने यहां से वहां तक की यात्रा की है। भारत माता के कातिलों के बारे में बताया है, भारत माता का हत्यारा बताया। उन्होंने केरोसिन की बात की है। इन्होंने सारा देश घूम लिया। काश! आप यहां की विधवा कॉलोनी में जा कर घूम लेते। जहां वर्ष 1984 में आपने सिखों के ऊपर कैरोसिन डाल कर, उनके गले में टायर साड़-साड़ कर उनकी औरतों को विधवा किया। हजारों-लाखों औरतों को विधवा करने के बाद, वे हथियार सज्जन कुमार के घर के पास..। आपने विधवा कॉलोनी बसाई। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह पर विधवा कॉलोनी है। विडो कॉलोनी सिर्फ दिल्ली में है। वहां कौन रहती हैं? जिनका कत्ल इनके पुरखों ने किया। इस कांग्रेस पार्टी ने किया और फिर उधर उन औरतों को बसाया। क्या यात्रा वहां से गुजरी? आज वे केरोसिन की बात करते हैं। मुझे दु:ख इस बात का है कि आज इनको वर्ष 1984 बहुत याद आ रहा था। जब इनको कटाक्ष करना होता है, तभी इनको वर्ष 1984 याद आता है। अरे भइया! नौ सालों में वर्ष 1984 के पीड़ितों को इंसाफ देने के लिए आपने इनको जेल के अंदर क्यों नहीं ठूंसा? आप कितनी बार विधवा कॉलोनी गए हैं।

सर, दु:ख इस बात का है कि जब मणिपुर की बात होती है, तो वे राजस्थान की बात करते हैं। वे राजस्थान की बात सुन कर, दोनों मिल कर वर्ष 1984 की बात करते हैं। सर, यह बहुत हो चुका है। अब दोनों जने सारा नाटक बंद करें। हम पूछना चाहते हैं कि हम किस पर कॉफिडेंस करें। इन्होंने जो किया, वह आपके सामने है। हमारा कत्लेआम किया। हमारी धार्मिक संस्था, अकाल तख्त, गोल्डन टेम्पल को टैंक, आर्मी से नुकसान पहुंचाया गया। हमारे पंजाब के टुकड़े-टुकड़े करके, पंजाबी स्पीकिंग एरिया निकाल कर दूसरा स्टेट बना दिया। हमारी राजधानी हम से खो ली। हमारा पानी हम से खो लिया। उन्होंने कौन-सा अत्याचार नहीं किया है? लेकिन इन्होंने क्या किया है? ये कौन-से कोई कम हैं? मैं यहां पर यह पूछना चाहती हूं कि जिन सिखों ने वर्ष 1947 में देश की आजादी में साथ दिया। देश की आजादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां हमने दी है। हरेक अल्पसंख्यक ने कुर्बानी दी है। सभी माइनॉरिटीज ने देश की आजादी में योगदान दिया है, लेकिन मुझे मान है कि हमारे सिखों ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। आप फांसी पड़ने वाले लोगों की लिस्ट गिन लें। कालापानी की सजा पाने वालों को देख लीजिए। सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों को यह सजा दी गई है, जिन्होंने देश को आजाद किया है। आजादी के बाद जब वर्ष 1966 में खाने के लिए अन्न पूरा नहीं होता था। The country was looking at starvation. हमारे किसानों ने ग्रीन रेवोल्यूशन ला कर, इस देश के लोगों का पेट भरने का काम किया है।

सर, जब हमारे सिखों का कत्लेआम हुआ, उस समय कोई ज्यूडिशियरी नहीं बोली, कोई पार्टी नहीं बोली, कोई पेपर नहीं बोला।… (व्यवधान) आप डिटेल्स निकालिए। नवम्बर, 1984 के बाद जब वर्ष 1985 का बजट सेशन हुआ, इस दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ था, तो उसमें एक का भी मेंशन नहीं किया गया था। सभी चुप्पी लगा कर बैठे हुए थे। मुंह पर टेप लगी हुई थी, किसी ने सिखों की बात तक नहीं की। यही कारण है कि आज तक सिखों को इंसाफ नहीं मिला। कभी मणिपुर में घटना घटती है, नूंह में घटना घटती है, कभी राजस्थान में घटना घटती है। अगर

उस समय ऐक्शन ले लिया गया होता तो ये सब नहीं होते। जम्मू-कश्मीर और गुजरात में सब कुछ होता है।

सर, सिखों के नौवें गुरू ने अपनी कुर्बानी दी। कश्मीर के पंडितों की बात हुई है। उस समय की हिन्दू माइनॉरिटी को बचाने के लिए, उस समय की मुस्लिम मेजॉरिटी से बचाने के लिए हमारे सिख गुरू ने अपनी कुर्बानी दी। उनको हिंद की चादर का खिताब मिला है, लेकिन उनकी तो बात तक नहीं की गई। जब उनके लोगों को मारा जा रहा था, तब भी बात नहीं की गई। मैं पूछना चाहती हूं कि उस समय हमारे लोग ने भावुक होकर इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उनको जेलों में फेंक दिया। हमारे सिख 30-30 सालों से जेल में सड़ रहे हैं। इस सरकार ने रिटन में कहा था कि उनको छोड़ा जाएगा?

(1545/KN/KKD)

आज तक उनको क्यों नहीं छोड़ा है? मैं इनसे जवाब मांगना चाहती हूं। सिखों के खिलाफ हमेशा यह बेइसांफी रही है, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी, उनके साथ ही यह होता है। इन्होंने जो किया, वह बताया। पिछले तीन सालों से ये क्या कर रहे हैं? जब से अकाली दल से गठबंधन टूटा है, आप हमारी राजधानी के बारे में सोचिये। एक पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था। आप विधान सभा को उठा कर हरियाणा में बना रहे हैं और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जमीन दे दी। बीबीएमजी में हमारा जो मैम्बर था, उसको बाहर निकाल दिया। हमारा पानी चुराकर दूसरे राज्यों को दे दिया। हिमाचल प्रदेश जो पानी दिल्ली को देता है, वह सेस लेता है। हमारा पानी जो राजस्थान आता है, तो पंजाब को कोई सेस नहीं देता है। एक ही चीज तो हमारी है। चंडीगढ़ के ऊपर हमारा हक है, उसके ऊपर सेंट्रल सर्विस रूल्स डाले जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पर भी आरएसएस कब्जा करने की कोशिश कर रही है। पानी तो यह मामला है कि पानी हमारा चुरा कर ले गए, लेकिन आज जब सारा पंजाब पानी में डूबा हुआ है, तो उस पंजाब के हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं है। आपको हैरानी होगी कि जब हिन्दुस्तान में कोई आपदा होती है, जब कोविड हुआ तो यहां लंगर सिखों ने लगाया। जब यहां पर लॉकडाउन हुआ तो सिखों ने लंगर लगाया। जब कोविड हुआ तो आप दोनों से, किसी से ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हुई। हमने लंगर लगाये। आज जब पंजाब को जरूरत है, अगर कहीं आपदा हो जाए, चाहे उत्तराखंड में हो, तो हम लोग जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया?… (व्यवधान) सर, मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म करती हूं। हमारे किसानों के साथ क्या किया? किसानों ने सबसे पहले इस देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाकर इस देश का पेट भरने का काम किया। ये कह रहे हैं कि इन्होंने किया, लेकिन 70 साल से तो हम पेट भर रहे हैं। आप उनके ऊपर काले कानून लेकर आए। अपने मंत्री की, अपने आला की बात नहीं पूछी। सुना नहीं। जब बोलते थे कि मत लाओ, तो नहीं सुना। आखिर में मानना पड़ा, किसानों ने मजबूर किया कि गलत बिल थे, आपको वापस लेने पड़े। ये डबल इनकम तो क्या करेंगे? आज आप बता दीजिए कि कौन से राज्य में डबल इनकम हो गई है। पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, हर चीज में महंगाई की मार सब झेल रहे हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : आप कनक्लूड कीजिए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): सर, कभी हमारे बच्चों पर, नौजवानों पर एनएसए लगाकर उनको असम की जेलों में फेंक देते हैं। हमारे किसान वहां पर जो आंदोलन में थे, उन पर एनआईए लगा देते हैं। खालसा, जो मदद करता है, उनके ऊपर एनआईए लगा देते हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैडम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): सर, मैं दो सैकेंड में अपनी बात पूरी करती हूं। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि मानस की जात सभै एकै पहिचानबो। मानस की एक ही जात होती है। एक पिता एकस के हम बारिक, यह हमारी गुरबानी ने सिखाया है। प्रकाश सिंह बादल पांच बार मुख्य मंत्री रहे, लेकिन एक दिन फिर कोई हिंसा नहीं हुई। चाहे पंजाब का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब उनको अपना समझते थे, क्योंकि मुख्य मंत्री होकर वे हर एक का स्पेशल दिन खुद मनाते थे। हर एक के धार्मिक स्थान, चाहे भगवान वाल्मीकी हो, गुरू रविदास हो, दुर्गियाना मंदिर हो, हर एक का उन्होंने सत्कार और आदर किया। यही कारण है कि उस समय सन् 1990 में जब वाजपेयी जी की भाजपा की सरकार थी तो कोई हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि सब इनको फेनेटिक समझते थे। सबसे पहले सरदार बादल जी थे, जिन्होंने इनका हाथ थामा।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

... (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): उसके बाद एनडीए बनी। सर, लास्ट पॉइंट है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. हिना विजयकुमार गावीत जी।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): आज मैं इनसे यही विनती करूंगी कि ये नफरत की राजनीति छोड़ दें। ये मरहम लगाने का काम करें, चाहे सिख हों या चाहे दूसरे धर्म के लोग हों, क्योंकि इसमें हर एक का अपना हिस्सा है। मैं एक शेर से अपना भाषण समाप्त करूंगी।

लगाकर आग शहर को,
बादशाह ने ये कहा,
उठा है आज दिल में तमाशे का शौक़ बहुत
झुकाके सर सभी शाहपरस्त बोल उठे
हुज़ूर का शौक सलामत रहे
शहर और बहुत हैं।

In the end, I would like to say that all humanity is one. There is only one God. We all are created from one God.

Thank you.

(इति)

माननीय सभापति : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत जी।

1549 बजे

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): सभापति महोदय, आज इस अविश्वास प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मेरा यह सौभाग्य है कि आज विश्व आदिवासी दिवस है और मैं पूरे विश्व के और भारत के सभी आदिवासी भाइयों व बहनों का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूं तथा उनके योगदान को प्रणाम करती हूं। अपनी बात शुरू करते समय मैं स्वामी विवेकानंद जी को क्वोट करना चाहूंगी।

He said, and I quote:

> “Every nation has a message to deliver, a mission to fulfil, a destiny to reach. The mission of India has been to guide humanity. Arise, awake and stop not till the goal is achieved.”

सर, जब सरकार बिना मिशन की बनती है तो क्या हालत होती है, यह हमने वर्ष 2004 से 2014 के बीच देखा है।

(1550/VB/AK)

जब कोई सरकार विज़न और मिशन, दोनों के साथ बनती है, तो हम विश्व की पाँचवी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनते हैं।

आदिवासियों को संविधान ने संरक्षण दिया। लेकिन अपोजिशन के लोग, जो बार-बार आदिवासी समाज के बारे में बोल रहे हैं, इन्होंने पिछले 60 वर्षों में आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों के लिए कुछ नहीं किया। यह मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। इन्होंने तो आदिवासी लोगों के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना भी नहीं की। हमारे जो इंस्पिरेशन हैं, हमारी पार्टी के जो इंस्पिरेशन हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देश में पहली बार जनजातीय मंत्रालय की स्थापना इस देश में की और तब से सही मायने में, आदिवासी समाज को न्याय देने का काम हमारी पार्टी की ओर से हो रहा है।

सर, देश में पहली बार 10 ट्राइबल म्यूजियम्स की स्थापना हुई है। इसके कारण आज हमारी जो संस्कृति और गौरवशाली इतिहास है, इसे केवल हमारे देश के ही नहीं, बल्कि विदेशों के लोग भी देख पा रहे हैं।

हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुण्डा जी की जयंती के दिन, 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।

वह पथ क्या,
पथिक कुशलता क्या,
जिस पथ में बिखरे शूल न हों,
नाविक की धैर्य कुशलता क्या,
जब धाराएं प्रतिकूल न हों।

ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रासंगिक हैं क्योंकि वह नाविक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपनी कुशलता से भारत को आज 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना दी है और हम विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2031 तक हम पाँच ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भी प्राप्त करेंगे।

सर, मैं महाराष्ट्र के एक आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ, जिसका नाम है- नंदूरबार। नंदूरबार में लगभग 70 से 75 प्रतिशत लोग आदिवासी समुदाय के हैं। स्वतंत्रता के बाद से वर्ष 2014 तक वहाँ कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं। पहली बार नंदूरबार की जनता ने मुझे चुना और इस देश की सबसे युवा आदिवासी महिला और सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका दिया है।

सर, जिस तरह से बाकी आदिवासी क्षेत्रों की समस्याएं हैं, वैसे ही मेरे क्षेत्र की समस्याएं भी बहुत जटिल थीं। हर गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना खुद का घर हो। उसी तरह से, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग भी अनेक वर्षों से प्रतीक्षा में थे कि उनका अपना मकान हो, जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है।

वर्ष 2016 से पहले हमारे देश में आवास के लिए इंदिरा आवास नाम की योजना थी। इस योजना में लोगों को घर मिलेंगे, ऐसा गरीब लोगों को लगता था। वे बेचारे इसी उम्मीद में जीते थे कि आज नहीं तो कल उनका नाम उस सूची में आ जाए। लेकिन वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी इन सब आदिवासी गरीब लोगों को आवास नहीं मिला। आप जानते हैं क्यों? वह इसलिए कि इस योजना में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं थी, किसी भी प्रकार का मापदण्ड तय नहीं था। केवल एक ही पार्टी के लोगों को बार-बार आवास दिये जाते थे, जिनके पास पहले से ही आवास था, उनका नाम बार-बार सूची में आता था और उन्हीं लोगों को बार-बार आवास मिलता था। सचमुच जिन लोगों को इसकी जरूरत थी, ऐसे लोग इस योजना से वंचित रहे। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ध्यान में यह बात आयी, तो उन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल का निर्णय लिया और यह निर्णय लेने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनायी।

सर, जो इंदिरा आवास योजना थी, वह इंदिरा आवास योजना नहीं थी, वह कांग्रेस आवास योजना थी, इसलिए ये सामने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनायी और पूरी पारदर्शिता से, वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित बेनिफिशियरीज की सूची तय की गई। वे केवल यहीं पर नहीं रुके। जिन लोगों का नाम उस सूची से छूट गया था, जो जरूरतमंद हैं, जिनको आवास की जरूरत है, उनका नाम उस सूची में ऐड करने के लिए एक अलग से डी-लिस्ट हर ग्रांम पंचायत से बनाकर ग्रामीण विकास विभाग ने उसे मंगवाकर, उसकी स्क्रूटनी करके देश के हर जरूरतमंद को, हर गरीब को, हर आदिवासी को, हर दलित को, हर पिछड़े को आवास देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है।

सर, मैं कुछ आँकड़े यहाँ बताना चाहूँगी। जनवरी, 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.7 करोड़ घरों की मंजूरी मिली है।

(1555/PC/UB)

इनमें से 2.1 करोड़ घर बन चुके हैं, आवास तैयार हो चुके हैं। जिन गरीबों का आवास का सपना था, वह सपना अब साकार हो रहा है।

सर, मैं यहां बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने केवल आवास की नई योजना ही नहीं बनाई, बल्कि आवास बनाने के लिए लगने वाली राशि को भी बढ़ाने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है। आज इस योजना के तहत इन आवासों के लिए 1.5 लाख रुपए सब गरीबों को दिए जा रहे हैं।

चेयरमैन सर, 'स्वच्छ भारत' विषय के ऊपर हमारे विरोधी पक्ष की एक सांसद यहां बोल रही थीं। वे कह रही थीं कि हमारा देश ओडीएफ नहीं हुआ है। मैं उनकी जानकारी के लिए यहां बताना चाहूंगी कि 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत, जो कि उनके टाइम पर यह 'स्वच्छ भारत मिशन' की स्कीम थी, तो ओडीएफ की जो डेफिनेशन इस योजना के अंतर्गत दी गई थी, वह बेसलाइन सर्वे, जो कि उनके समय में हुआ था, वह था कि अगर 100 परसेंट मकान बन गए हैं, तो हम उनको ओडीएफ कहते थे।

जो आज की स्थिति है, कई लोग जो उस सर्वे में नहीं थे और जिनके पास शौचालय नहीं थे, उन्हें भी शौचालय उपलब्ध कराने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने ओडीएफ प्लस योजना की निर्मिति की। … (व्यवधान) 100 परसेंट शौचालय हर गरीब को, जिसको जरूरत है, उसको देने का काम हमारे देश में हो रहा है। … (व्यवधान)

सर, आज तक देश में 11 करोड़ टॉयलेट्स बन चुके हैं। … (व्यवधान) 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बन चुके हैं। … (व्यवधान) 6,03,175 गांव ओडीएफ डिक्लेयर हो गए हैं। ओडीएफ प्लस का जो काम है, वह बहुत ही फास्ट पेस के साथ चल रहा है। मैं 'स्वच्छ भारत मिशन' के बारे में बोलना चाहूंगी कि इसके माध्यम से हमारे देश में जिन लोगों की डायरिया, मलेरिया इत्यादि इस तरह की बीमारियों से मृत्यु हो जाती थी, उसका प्रमाण आज कम हो गया है। … (व्यवधान)

सर, मैं इसी के साथ एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगी कि रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब की जरूरत होती है। … (व्यवधान) हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर गरीब, हर आदिवासी व्यक्ति को ये तीनों चीजें मिलें। … (व्यवधान)

सर, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे कांग्रेस के साथी आदिवासी लोगों के बारे में बार-बार बोलते रहते हैं। … (व्यवधान) मैं उनकी जानकारी के लिए यहां कुछ आंकड़े

बोलना चाहूंगी। ... (व्यवधान) वे चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं और बाद में जाकर वैरिफाई भी कर लें।

सर, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए, जब वर्ष 2013-14 में इनकी सरकार थी, तब इन्होंने आदिवासी विकास के लिए जो टोटल बजट दिया था, वह 4,295 करोड़ रुपए था। ... (व्यवधान) हमारी सरकार वर्ष 2023-24 में आदिवासी समाज के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो बजट दे रही है, वह 12,462 करोड़ रुपए है, जो कि तीन गुना ज्यादा है। ... (व्यवधान) आदिवासी समाज के विकास के लिए हमारी सरकार ने यह बजट दिया है। ... (व्यवधान)

सर, इतना ही नहीं, शेड्यूल ट्राइब कॉम्पोनेंट में फंड्स दिए जाते हैं। ... (व्यवधान) यह बजट तो आदिवासी समाज के विकास के लिए हो गया, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों को अलग-अलग योजनाओं के तहत ट्राइबल डिपार्टमेंट जो फंड देता है, उसकी राशि मैं यहां बताना चाहूंगी। वर्ष 2013-14 में जब इनकी सरकार थी, तब 24,598 करोड़ रुपए दिए गए थे। हमारी सरकार आने के बाद इस राशि में पांच गुना बढ़ोत्तरी हुई। ... (व्यवधान) वर्ष 2023-24 में 1,19,509 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ... (व्यवधान)

सर, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहब अंबेडकर जी ने आदिवासी समुदाय को समान हक मिलें, समान अधिकार मिलें, इसके लिए उन्होंने संविधान में एससी और एसटी समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। ... (व्यवधान) मैं यहां बोलना चाहूंगी कि पिछले नौ वर्षों में हमारी सरकार ने आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वसमावेशी विकास के लिए एजुकेशन, हैल्थकेयर और लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज पर विशेष रूप से ध्यान दिया है।

हमारे प्रधान मंत्री जी डॉक्टर बाबासाहब अंबेडकर जी के विचारों को आगे ले जाते हुए आदिवासी समाज के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसलिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की निर्मिति हर ट्राइबल ब्लॉक, हर ट्राइबल क्षेत्र में करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ... (व्यवधान) ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, जब इनकी सरकार थी, उस समय केवल 119 ईएमआरएस बने थे। जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने वर्ष 2023 तक 401 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए हैं, जो कि, इन्होंने जो किया था, उससे चार गुना ज्यादा है। ... (व्यवधान) जो स्टूडेंट्स इन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या भी मैं यहां बताना चाहूंगी। ... (व्यवधान)

(1600/CS/SRG)

सर, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जैसा कि उसका नाम है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही मायने में ये मॉडल स्कूल्स बनाने का काम यहाँ पर किया हुआ है। मेरे क्षेत्र में कई स्कूल्स हैं, क्योंकि मेरा एक जनजातीय क्षेत्र है तो हर ब्लॉक में यह एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, कई स्कूल बने हैं तो कई स्कूल बन रहे हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आज इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स से जो बच्चे पास हो रहे हैं, वे आज देश के एपेक्स इंस्टिट्यूट्स, चाहे एम्स हो, आईआईटीज हों, आईआईएम्स हों में एडमिशन ले रहे हैं। इतना ही नहीं आज देश में होने वाली जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसमें भी ये बच्चे एक्सेल कर रहे हैं। यहाँ मैं अपने पूरे आदिवासी समाज की तरफ से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि हमारे आदिवासी समाज के बच्चों को सही मायने में क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हमारे लाखों बच्चे, केवल हमारे देश में ही नहीं, देश के बाहर विदेश में भी जाकर शिक्षा ले रहे हैं। सर, मैंने अभी शिक्षा की बात की। अब मैं स्वास्थ्य की बात करना चाहूँगी। मैं हमारे सदन के सभी साथियों को एक बीमारी के बारे में बताना चाहूँगी, जो ट्राइबल एरियाज में ज्यादातर देखने को मिलती है। उसका नाम सिकल सेल एनीमिया है। हमारी सरकार ने सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम बाई 2047 का लक्ष्य तय किया है।

1603 बजे (श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

महोदया, सिकल सेल के कारण कई अलग-अलग बीमारियाँ, कई अलग-अलग तकलीफ हमारे उन पेशेंट्स को होती हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक कैरियर और एक डिजीज। इन दोनों को अलग-अलग कलर कोडेड कार्ड देने की व्यवस्था भी हमारी इस सरकार ने की है ताकि अगर कोई बीमार हो तो वह कार्ड बताकर, दिखाकर पता चल जायेगा कि उसे किस प्रकार का सिकल सेल हुआ है, उसे किस टाइप के इलाज की जरूरत है, उसे वहाँ दिखाकर वह इलाज ले सकता है। मैं हमारे विरोधी पार्टी के सभी सांसदों से पूछना चाहूँगी, हमारी सरकार के खिलाफ हर कोई उठकर बोल रहा है, मेरा आपसे सवाल है कि सिकल सेल एलिमिनेशन के लिए आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया? आदिवासी समाज के लिए तो आप बहुत, बार-बार उठकर बोल रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन के लिए आप लोगों को भी काम करना चाहिए था। सिकल सेल कोई आज आयी हुई बीमारी नहीं है, यह तो जेनेटिक बीमारी है, यह तो वर्षों से चलती आ रही है।

हमारे मोदी जी ने एक विजन से, आने वाले आगे के समय में किसी आदिवासी व्यक्ति को सिकल सेल न हो या अगर सिकल सेल है तो उसका ट्रीटमेंट हो, इसके लिए इस कार्यक्रम की निर्मिती, एलिमिनेशन का टारगेट हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। जब मैं आदिवासी लोगों की और आरोग्य की बात करती हूँ तो सबसे पहली बात जो हमारे जेहन में आती है, वह कुपोषण की है। मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि कुपोषण निर्मूलन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चीज सोची कि जब हम बोलते हैं कि हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें क्या करनी चाहिए, तो हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं।

अगर इन बच्चों की कुपोषण से मृत्यु हो रही है तो उसे किस तरह रोकें और इसके कारण देश में हर क्षेत्र में आँगनवाड़ियों का जो नेटवर्क है, जो पहले से चलता आ रहा है, जो केवल नाम के लिए था, उसमें प्रॉपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था, तो इन आँगनवाड़ियों को स्ट्रेंग्थेन करने के लिए, इन्हें सक्षम करने के लिए सक्षम आँगनवाड़ी का कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और दो लाख आँगनवाड़ियां पूरे देश भर में इस सक्षम आँगनवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत बनायी जा रही हैं। इसमें हर वर्ष 40 हजार आँगनवाड़ियों की निर्मिती हो रही है। इसी के साथ-साथ मिशन पोषण 2.0 भी हमारी सरकार ने शुरू किया। इस मिशन पोषण 2.0 का उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोर, लड़कियों और गर्भवती महिलाओं के साथ स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना और स्वास्थ्य कल्याण और प्रतिरक्षा, पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरण परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

(1600/CS/SRG)

सर, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जैसा कि उसका नाम है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही मायने में ये मॉडल स्कूल्स बनाने का काम यहाँ पर किया हुआ है। मेरे क्षेत्र में कई स्कूल्स हैं, क्योंकि मेरा एक जनजातीय क्षेत्र है तो हर ब्लॉक में यह एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, कई स्कूल बने हैं तो कई स्कूल बन रहे हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आज इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स से जो बच्चे पास हो रहे हैं, वे आज देश के एपेक्स इंस्टिट्यूट्स, चाहे एम्स हो, आईआईटीज हों, आईआईएम्स हों में एडमिशन ले रहे हैं। इतना ही नहीं आज देश में होने वाली जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसमें भी ये बच्चे एक्सेल कर रहे हैं। यहाँ मैं अपने पूरे आदिवासी समाज की तरफ से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि हमारे आदिवासी समाज के बच्चों को सही मायने में क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हमारे लाखों बच्चे, केवल हमारे देश में ही नहीं, देश के बाहर विदेश में भी जाकर शिक्षा ले रहे हैं।

सर, मैंने अभी शिक्षा की बात की। अब मैं स्वास्थ्य की बात करना चाहूँगी। मैं हमारे सदन के सभी साथियों को एक बीमारी के बारे में बताना चाहूँगी, जो ट्राइबल एरियाज में ज्यादातर देखने को मिलती है। उसका नाम सिकल सेल एनीमिया है। हमारी सरकार ने सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम बाई 2047 का लक्ष्य तय किया है।

1603 बजे (श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

महोदया, सिकल सेल के कारण कई अलग-अलग बीमारियाँ, कई अलग-अलग तकलीफ हमारे उन पेशेंट्स को होती हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक कैरियर और एक डिजीज। इन दोनों को अलग-अलग कलर कोडेड कार्ड देने की व्यवस्था भी हमारी इस सरकार ने की है ताकि अगर कोई बीमार हो तो वह कार्ड बताकर, दिखाकर पता चल जायेगा कि उसे किस प्रकार का सिकल सेल हुआ है, उसे किस टाइप के इलाज की जरूरत है, उसे वहाँ दिखाकर वह इलाज ले सकता है। मैं हमारे विरोधी पार्टी के सभी सांसदों से पूछना चाहूँगी, हमारी सरकार के खिलाफ हर कोई उठकर बोल रहा है, मेरा आपसे सवाल है कि सिकल सेल एलिमिनेशन के लिए आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया? आदिवासी समाज के लिए तो आप बहुत, बार-बार उठकर बोल रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन के लिए आप लोगों को भी काम करना चाहिए था। सिकल सेल कोई आज आयी हुई बीमारी नहीं है, यह तो जेनेटिक बीमारी है, यह तो वर्षों से चलती आ रही है। हमारे मोदी जी ने एक विजन से, आने वाले आगे के समय में किसी आदिवासी व्यक्ति को सिकल सेल न हो या अगर सिकल सेल है तो उसका ट्रीटमेंट हो, इसके लिए इस कार्यक्रम की निर्मिती, एलिमिनेशन का टारगेट हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। जब मैं आदिवासी लोगों की और आरोग्य की बात करती हूँ तो सबसे पहली बात जो हमारे जेहन में आती है, वह कुपोषण की है। मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि कुपोषण निर्मूलन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चीज सोची कि जब हम बोलते हैं कि हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें क्या करनी चाहिए, तो हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं। अगर इन बच्चों की कुपोषण से मृत्यु हो रही है तो उसे किस तरह रोकें और इसके कारण देश में हर क्षेत्र में आँगनवाड़ियों का जो नेटवर्क है, जो पहले से चलता आ रहा है, जो केवल नाम के लिए था, उसमें प्रॉपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था, तो इन आँगनवाड़ियों को स्ट्रेंग्थेन करने के लिए, इन्हें सक्षम करने के लिए सक्षम आँगनवाड़ी का कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और दो लाख आँगनवाड़ियां पूरे देश भर में इस सक्षम आँगनवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत बनायी जा रही हैं। इसमें हर वर्ष 40 हजार

आँगनवाड़ियों की निर्मिती हो रही है। इसी के साथ-साथ मिशन पोषण 2.0 भी हमारी सरकार ने शुरू किया। इस मिशन पोषण 2.0 का उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोर, लड़कियों और गर्भवती महिलाओं के साथ स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना और स्वास्थ्य कल्याण और प्रतिरक्षा, पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरण परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

(1605/RV/RCP)

महोदया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS-4 की डेटा के अनुसार हमारे देश में इन्फैंट मॉर्टैलिटी रेट प्रति 1000 लाइव बर्थ में 40.7 था। आज NFHS-5, जो कि हर पाँच साल में होता है, उसमें यह 35.2 हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे देश में बच्चों की मृत्यु दर कम हो गयी है।

इसी के साथ मैं नियो-नैटल मॉर्टैलिटी रेट के बारे में भी बोलना चाहूंगी, जिसमें NFHS-4 में 29.5 प्रति 1000 लाइव बर्थ था, आज NFHS-5 में यह 24.9 है, जो कि कम हो गया है।

महोदया, मैं यहां एक और चीज बोलना चाहूंगी कि आंगनबाड़ियों को सक्षम करते समय हम आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी हेल्पर्स को किस तरह टेक्नोलॉजी से जोड़ें। इन सभी पोषण योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारे देश में 11 लाख स्मार्ट फोन्स आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिए गए हैं।

Madam, 12.5 lakh growth monitoring devices such as infantometer, stadiometer, weighing scale for mother and infant, weighing scale for children have been procured by the States.

मैडम, टेक्नोलॉजी के साथ-साथ पोषण ट्रैकर का भी उपयोग किया जा रहा है। जो माताएं हैं या गभर्वती माताएं हैं, जो कहीं पर माइग्रेट हो रही हैं तो वहां उनको ट्रैक करना आसान हो, इसके लिए पोषण ट्रैकर बनाया गया है। हर पोषण ट्रैकर में 10 करोड़ महिलाओं को रजिस्टर कर लिया गया है।

मैडम, मैं यहां पर एक चीज विशेष रूप से बोलना चाहूंगी कि कई सांसदों ने बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में यहां बोला। लेकिन, जब इनकी सरकार थी, तब इन्होंने बाल विकास के लिए केवल 90 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। जब हमारी सरकार आई, हमने 1600 करोड़ रुपये केवल बाल विकास के लिए दिए। इससे हमारे विज़न और इनके विज़न में जो अन्तर है, वह साफ-साफ दिखता है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे सुदृढ़ हों, उनका अच्छी तरह से विकास हो। ये लोग केवल बोलते हैं। इनके एक्ट में हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि इन्होंने बच्चों के लिए कुछ किया है।

मैडम, हमारी सरकार की एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना मिशन वात्सल्य है, which is envisaged to be done by strengthening the institutional framework of Child Welfare and Protection Committees and the statutory and service delivery structure in all districts of the country. This scheme also provides for non-institutional care of vulnerable children by way of kinship care, sponsorship, foster care and aftercare.

पहले सी.पी.एस. नाम की इनकी जो योजना थी, उसमें दो हजार रुपये दिए जाते थे। आज हम लोग इस योजना में चार हजार रुपये दे रहे हैं।

कोविड के समय कई बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिए। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इन बच्चों के लिए एक नई स्कीम शुरू की, जिसका नाम है - पी.एम. केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम। हमारे प्रधान मंत्री जी

इन सभी अनाथ बच्चों के सही मायने में पालक बने। आज हमारे देश में जो बच्चे अनाथ हुए हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन इस स्कीम में हुआ है, तो जब उनकी आयु 23 साल होगी, तब उन्हें दस लाख रुपये मिलेंगे।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): अब अपना भाषण एक मिनट में समाप्त कीजिए।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): मैडम, हमारे प्रधान मंत्री जी हमेशा यह कहते हैं कि हमारी सरकार गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए समर्पित है और उनकी नीतियों में हमें यह साफ-साफ दिखाई भी देता है। आज हमारे देश में 65 प्रतिशत से ज्यादा लोग ग्रामीण भारत में रहते हैं, 47 प्रतिशत से ज्यादा लोग पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं।

यहां हमारे कुछ सांसद साथी इम्प्लॉयमेंट की बात करते थे तो इन्हें मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी। रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो इनके समय में शुरू हुई थी, इन्होंने कितने लोगों को इम्प्लॉयमेंट दिया है और हमने कितने लोगों को दिया है, वह भी मैं इन सब लोगों को बताना चाहूंगी। इनके समय वर्ष 2006-07 से वर्ष 2013-14 तक इन्होंने 1,107 टोटल पर्सन डेज किए थे। हमारी सरकार आने के बाद 2,596, करीब-करीब दोगुना, हमने इसमें काम किया है।

इनके समय में महिलाओं की भागीदारी केवल 48 प्रतिशत थी। हमारी सरकार आने के बाद अभी यह करीब 60 प्रतिशत तक जा चुकी है।

मैडम, हम लोग जो वेजेज पे करते हैं, तो इनके समय में कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, जहां हम वर्कर्स को डायरेक्ट पे कर सकें, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने 27 राज्यों और 3 केन्द्रशासित प्रदेशों में यह व्यवस्था की हुई है।

(1610/GG/PS)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि गांवों को जोड़ती है, इसमें हमारी सरकार द्वारा 3,53,991 kilometres of road length has been constructed in the country with an amount of Rs. 1,87,425 crore.

मैडम, मैं इसके साथ यहां पर यही कहना चाहूंगी कि आज कांग्रेस और उनके बाकी साथियों द्वारा सरकार के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। लेकिन एक आदिवासी क्षेत्र की प्रतिनिधि होने के नाते मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि इन्हें भले ही सरकार पर कॉन्फिडेंस न हो, लेकिन हमारे आदिवासी समाज को मोदी जी और उनकी सरकार पर पूरा कॉन्फिडेंस है।... (व्यवधान)

मैडम, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती हूँ और अपनी बात कुछ पंक्तियां कह कर समाप्त करूंगी। ... (व्यवधान)

"मंज़िल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है।
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।"

धन्यवाद।

(इति)

1611 hours

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): Madam Chairperson, thank you for giving me this time to speak.

I am here not to create differences or bitterness. Nation is for all of us. If nation survives, we all will survive. That is the first thing we all must remember. I need to correct the Minister who spoke recently. She said about child marriage that since they came, child marriage has been stopped in Kashmir. She is completely wrong. Maharaja Hari Singh of Kashmir, in 1928, passed the Act that no child marriage will take place in his State, and that was put into order. They completely gave wrong information which I want to be corrected.

Secondly, we are a part of India. Yes! She spoke about Kashmiri Pandits. It is the biggest black mark in the history of Jammu and Kashmir. In 1947, when the Kabalis and Pakistani Army came -- Maharaja's army was very small and they could not defend the State -- they walked in. At that time, who had defended the people, the minority? Everyone -- the Hindus, Muslims, Sikhs, Christians -- stood together and said that they will fight them. We had no weapons, but we only had the will that they cannot take us. I must inform the leader of the Shiromani Akali Dal that we are proud of your people. The Patiala Regiment was the first that came to defend us. I remember that as a child I was behind my father when I went to the airport, and I saw those six-footers with the ring around their head. I hid behind my father and asked, 'Who are they?' He said, 'They are the Punjab Regiment that has come to defend us'. To them, I pay my homage for their bravery. Many died in my land; hardly any returned.

Today, we stand proud to be a part of this nation. But this nation has a responsibility not only to Hindus but also to Muslims, Christians, Sikhs and everybody that lives in India. The Prime Minister does not represent only one colour. He represents India. He represents 1.4 billion people of India. Let us not ignore that. You make mistakes and we make mistakes. Yes! Who says we are perfect? We make mistakes. You remember, when I was the Chief Minister, I tried to bring Kashmiri Pandits back home. Gujral Sahab was the Prime Minister here, and when we tried to do so, the forces from across the border killed innocent Kashmiri Pandits in a village near Ganderbal.

(1615/SMN/MY)

Immediately, we stopped those 50 vehicles that had to bring them back home. And to this day, I must ask you, how many Kashmiri Pandits had you brought back in these ten years? None. Do not forget. I was Chief Minister sitting in the Assembly. They came to attack the Assembly. Five minutes before, I had left the Assembly because I had to meet the Governor. What happened then? … (*Interruptions*) Please listen. They came to Assembly searching where is Farooq. They did not know me where I was. They killed 40 people. Do you ever remember that? Do you ever talk of them? Do you ever say what happened to them? We stood because we wanted to stand by this nation. Please remember. Do not say that we are not part of India. Do not say we are Pakistanis. Do not say we are traitors. It is unfortunate that you do not realise that we are part of this nation. We are responsible as much as you are for everyone in this country.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय, फारुख अब्दुल्ला जी इतने सीनियर सदस्य है, मैं उनका आदर करता हूं।… (व्यवधान) लेकिन, यह कहना कि इस सरकार ने नौ वर्षों में कश्मीरी पंडित और हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया है।… (व्यवधान) वहां कश्मीरी पंडितों की जमीन वापसी हो रही है।… (व्यवधान) लोग वहां जा भी रहे हैं। उनको रोजगार भी मिल रहा है। माननीय सदस्य यहां सदन को गुमराह कर रहे हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है।… (व्यवधान) यह बात ठीक नहीं है। यह गलतबयानी है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): माननीय सदस्य, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): मिनिस्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए।… (व्यवधान) आप सुनने की कुछ आदत भी डालिए। क्या आप यह जानते हैं कि किस तरह से हमारे मिनिस्टर्स को बमों से उड़ाया गया था।… (व्यवधान) मैंने उनके गोश्त को हाथों से उठाया था।… (व्यवधान) क्या आपने ऐसा सुना है? क्या आपने इस बात का पता लगाया है? … (व्यवधान) यह इसीलिए था कि हम लोग इस वतन के साथ रह सकें। आपका जो प्रभाव है, आपका जो तरीका है, वह इस मुल्क को खतरे में डाल रहा है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: इनको बोलने दीजिए।

… (व्यवधान)

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): You are trying to create a tragedy for this nation. … (*Interruptions*) Remember, you are creating tragedies. Love people. It is not the force that will win you. It is not the power of the gun that will keep you. It is the love of the people that will keep us together. Create that love.

Create that affection. Have some tears in your eyes and not mere shouting. Enough of shouting has been done. Listen.

Maharaj of Kashmir was not a fool. Maharaj of Kashmir wanted to remain independent. He wanted to be between these two nations – a Switzerland. But Pakistanis did not want that. Pakistanis invaded and he had to come to India for help. Do not forget. And the agreement that was signed held only three things – Defence, Communication and Foreign Affairs. Final decision was to be done of the State by a plebiscite. That is history. Do not forget the history. And the real plebiscite was never held. When plebiscite was not held, was Article 370 not a permanent issue? But you abrogated it. Thank God, it is in the Supreme Court today. I do not want to say much about it. But create love, not hate. Do not hate us by selling us tourism. Ah! What tourism is going in Kashmir? What development is taking in Kashmir? It is not tourism and development, it is love that you have to give. You have to understand. आप मुहब्बत सीखो, नफरत मत सीखो।… (व्यवधान) बहुत नफरत हो गई। अब आप नफरत को छोड़ दो।… (व्यवधान) आप मुहब्बत की बात करो। आप मेरी बात सुनिए।… (व्यवधान) Please have the courage to listen. I did not speak when you people were speaking. I did not raise my voice. So, listen. And listen good. … (*Interruptions*) Listen good. … (*Interruptions*) You had G20 meeting and you said to the whole world, what a great tourism meet you held.

(1620/RU/CP)

Do you know that you could not take the members of G-20 to Gulmarg and you could not take them to Dachigam? And you say that there is peace and that there is no terrorism there. Look at the situation yesterday in Kulgam and Rajouri. Our neighbour is still playing there. Do not forget that. And that is why, I say this to you. Remember I say it to this Government and to the people of India.

याद रखिए, वाजपेयी जी ने क्या कहा।… (व्यवधान) मेरी बात सुनिए।… (व्यवधान) अपने लीडर की बात सुनिए।… (व्यवधान) वे पाकिस्तान के बार्डर के पास बरना में आए और कहने लगे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती में रहें तो हम दोनों तरक्की करेंगे। अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम होगी।…(व्यवधान) यह आपके लीडर की बात है।… (व्यवधान) आप सुनिए।…(व्यवधान) आप इसको मानें या न मानें।…(व्यवधान) मैं इस हाउस से आपसे कहता हूं कि अगर आपमें दम है तो युद्ध कर लीजिए।…(व्यवधान) हम तो रोक नहीं रहे हैं। हम कभी नहीं रोकते हैं।…(व्यवधान) मगर हम पर शक करो कि हम पाकिस्तानी हैं।…(व्यवधान) कब तक हम पर शक करोगे? …(व्यवधान) मैं आपसे कहता हूं कि इस शक को

छोड़िए। ...(व्यवधान) हमें भी गले लगाइए, जो इस वतन के साथ खड़े हैं और इस वतन के साथ खड़े रहेंगे।... (व्यवधान) हमने गोलियां खाईं, हमने अपने जिस्म दिए, इसके लिए कि हिंदुस्तान वहां जिंदा रहे।... (व्यवधान) यह कभी भूलिए मत।... (व्यवधान)

जहां तक मणिपुर की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि वहां भी हमें मोहब्बत से काम करना पड़ेगा और लोगों के दिलों को जीतकर इस मुल्क को बचाना पड़ेगा।...(व्यवधान) आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।... (व्यवधान) I hope that these people will realise that love is the only way forward.

(ends)

श्री नित्यानन्द राय: मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ताकत है कि आज हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश कोई पड़ोसी नहीं कर सकता है। ...(व्यवधान) आज पूरा हिंदुस्तान इस विषय पर अपने प्रधान मंत्री जी और अपनी सरकार पर गर्व करता है।...(व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह): फारूख साहब, प्लेबिसाइट इसलिए नहीं हुआ कि उसमें एक शर्त थी। वह शर्त यह थी कि जब दस साल के बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तब पाकिस्तान अपनी सेनाओं को पीओके से हटाएगा। वह शर्त थी। So, let us not talk about plebiscite and that it was not held. शर्त जब पूरी नहीं हुई, तो वह नहीं हो सकता।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): अनुप्रिया पटेल जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : बैठ जाइए, लड़िए मत।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : जब आपका नंबर आए, तब सब नोट करके बोलिएगा।

... (व्यवधान)

1623 बजे

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) : सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे विपक्षी खेमे, इंडिया एलायंस के साथियों द्वारा इस लोक सभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपने विचार रखने का अवसर दिया। यह अविश्वास प्रस्ताव कितना आधारहीन और निरर्थक है, यह केवल इस तरफ के ही नहीं, बल्कि उस तरफ के लोग भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। स्वयं हमारे विपक्ष के साथियों की, हमारे इंडिया एलायंस के साथियों की स्वीकारोक्ति है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या है, समर्थन है और इस प्रस्ताव से सरकार की स्थिरता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।

सभापति जी, इस देश की जनता को ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देशों की जनता को आज के इस उभरते हुए नये भारत की शक्ति पर यकीन है। आज भारत दुनिया के तमाम देशों के लिए एक उदाहरण बन चुका है।

(1625/NK/SM)

यही कारण है कि आज दुनिया के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौदह देश ऐसे हैं, जिन्होंने अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री जी को अलंकृत किया है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी परेशान हैं। … (व्यवधान) दानिश जी, अपनी व्याकुलता को थोड़ा विश्राम दीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। मैं सबकी बात बिना किसी को हैकल किए धैर्यपूर्वक सुनती हूं।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि करोड़ों भारतवासियों को सरकार पर विश्वास है। दुनिया के देशों में भारत उदाहरण बन रहा है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस लोक सभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपकी लोकतंत्र में कोई आस्था ही नहीं है। यह पूरा देश जानता है कि सदन में आपका आचरण कैसा है। आप किस तरह से संसदीय परंपराओं का अपमान करते हैं, शोरगुल करते हैं, बहिष्कार करते हैं, सदन चलने नहीं देते हैं, कोई न कोई नया बहाना बनाकर हर चर्चा से आप भागते हैं। यह पूरा देश आपको देख रहा है।

मैं सोलहवीं लोक सभा में पहली बार सांसद बनकर आई थी। वर्ष 2019 में चुनाव से ठीक एक वर्ष पूर्व अविश्वास प्रस्ताव इसी प्रकार हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा लाया गया। वर्ष 2024 में चुनाव है, वर्ष 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव आ गया। बार-बार अविश्वास प्रस्ताव चुनाव से पहले आता है, यह बड़ा खास हथकंडा है।

हमारे विपक्ष के साथी इस समय बहुत निराश हैं। आज हमारी एनडीए गठबंधन की जो स्थिति है, हमारे विपक्ष के साथियों के अंदर हताशा है, यह बात हम सभी जानते हैं। फिर इस चुनावी हथकंडे का प्रयोग किया जाता है कहीं न कहीं इनको लगता है कि शायद ऐसा करके हमारी राजनीतिक जमीन मजबूत हो जाएगी। शायद चुनाव से पहले कोई न कोई अप्रत्याशित चुनावी लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण बार-बार इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं अपने विपक्ष के विद्वान साथियों से इतना ही कहना चाहती हूं कि यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जब-जब आप हमारी सरकार के ऊपर या एनडीए गठबंधन और मोदी जी की लीडरशीप के ऊपर अविश्वास व्यक्त करते हैं, तब-तब देश की

जनता आने वाले चुनाव में अपने और भी बड़े विश्वास से आपके अविश्वास को खारिज करने का काम करती है।

वर्ष 2014 से बड़ा जानादेश हमें 2019 में प्राप्त हुआ। यह मैं अहंकारवश नहीं कह रही हूं, यह सत्य है। वर्ष 2019 से बड़ा जनादेश 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त होगा। यह अहंकार नहीं है और कोई जुमला भी नहीं है। यह मैं जनता के विश्वास के कारण कह रही हूं।

मैं अपने विपक्ष के विद्वान साथियों से कहना चाहती हूं कि जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए जनता के मन में उतरना पड़ता है। नौ वर्षों में हमारी सरकार ने अपने कार्यों से जनसेवा के कार्य किए, जनता के कल्याण के कार्य किए और हमने जनता के दिल में जगह बनाई है। जनता के मन में जगह बनाने के कारण ही मैं कह रही हूं कि वर्ष 2019 से भी बड़ा जनादेश 2024 में लेकर आएंगे। मैंने पहले भी कहा, आपके आचरण और आपके रवैये को भी देश ने देखा है, देश की जनता देख रही है और हमारे विकास के मॉडल को भी देखा है। हमारे विकास मॉडल के केन्द्र में गरीब का कल्याण है। हम इस वर्ष आजादी के 76 वर्ष पूरे करेंगे।

(1630/SK/RP)

संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। आजादी के 76 वर्षों के बाद क्या देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास मूलभूत सुविधाओं की गारंटी न हो? मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने इस बारे में सोचा। तीन करोड़ से ज्यादा प्रधान मंत्री आवास, 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ 'नल से जल' योजना के तहत कनैक्शन, कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज, 48 करोड़ से ज्यादा बैंकों में खाते, तीन करोड़ से ज्यादा बिजली कनैक्शन्स, दस करोड़ से ज्यादा 'उज्ज्वला' योजना के तहत गैस सिलेंडर और 23 करोड़ लोगों का आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा दिया गया।

माननीय सभापति जी, मैं सदन से पूछना चाहती हूं कि ये कौन लोग हैं, यह समाज का कौन सा तबका है, जिसके पास आजादी के बरसों बाद सिर पर छत नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जहां महिलाएं शौचालय के लिए तरसती हैं, जिनके पास बैंकों में खाते नहीं हैं, जिनके लिए बैंकों के दरवाजे बंद हैं, जो बीमारी में इसलिए मरते हैं क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं? यह कौन सा तबका है? यह समाज का वह वर्ग है, जो दलित है, पिछड़ा है, कमजोर है और सालों से वंचित रहा है। माननीय मोदी जी की सरकार ने इनके हितों के बारे में सोचा है।

सभापति जी, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, जो शायद हमारे विपक्ष के साथी समझकर भी समझना नहीं चाहते हैं। देश के दलित, पिछड़े, गरीब और वंचितों ने सही मायने में समझा नहीं कि भारत की आजादी और लोकतंत्र का सुख क्या होता है? उन्हें ही इन आंकड़ों की समझ में आ सकती है, इन आंकड़ों का महत्व समझ में आ सकता है। हमारे विपक्ष के साथी स्वीकार करें या न करें, लेकिन एनडीए सरकार के गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को वैश्विक संस्थाओं द्वारा मान्यता मिली है।

महोदया, आईएमएफ ने हाल ही में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का श्रेय माननीय मोदी जी की सरकार को दिया है। दुर्भाग्य है कि आप इन उपलब्धियों को देख नहीं सकते हैं, न हमारे प्रयासों को देख सकते हैं और न ही हमारी मंशा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्या सच से मुंह

फेर लेने से सच बदल जाता है? दबी जुबान से ही सही, खुले मन से न सही, लेकिन विपक्ष के साथी यह स्वीकार तो करेंगे कि हमारी सरकार ने गरीबों का कल्याण किया है और सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर जीने वाले लोगों की पीड़ा को समझा है। माननीय मोदी जी के राज में यह राजनीति का वह योग है, जहां वंचित वर्गों को सबसे निचले पायदान से उठाकर मुख्यधारा में लाने के एक नहीं अनेक प्रयास हुए हैं। सामाजिक न्याय के मापदंडों पर हमारी सरकार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिसका आने वाली सरकारों द्वारा अनुसरण करने की आवश्यकता है।

महोदया, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति के पद को कौन सुशोभित कर रहा है? सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान से आने वाली परम श्रद्धेय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु जी। यह लोकतंत्र की ताकत नहीं है तो और क्या है? सवाल यह है कि पहले की सरकारों ने ऐसी पहल क्यों नहीं की? एक आदिवासी महिला लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर आसीन हो, ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? क्या भारत का लोकतंत्र चंद अभिजात वर्गों की बपौती है? माननीय मोदी जी की सरकार ने इस भ्रम को तोड़कर रख दिया है।

महोदया, हमारे मंत्रिमंडल को देखिए, इसमें पिछड़े, वंचित, दलित की भागीदारी देखिए। पूर्व की सरकारों के मंत्रिमंडल को भी स्मरण कर लीजिए। मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि कितने पिछड़े, दलितों, आदिवासियों को आपने मंत्री बनाया था? इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पीछे की पंक्ति में बैठने का काम नहीं करेगा, अग्रिम पंक्ति में आकर बैठेगा, माननीय मोदी जी ने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में पिछड़े, वंचित समाज के बच्चे भी पढ़ें, यह पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा? क्या आपको किसी ने रोका था? यहां हमारे विद्वान साथी बैठे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कितने वर्षों से इस संसद में उठी?

(1635/KDS/NKL)

क्या उस पर कुछ काम हुआ? अगर नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? मैं जो सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब दीजिए। वर्ष 2011 में आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको किसने रोका था? आप अपने गिरेबान में झांककर कर देखिए। … (व्यवधान)

सभापति महोदया, नीट की परीक्षा में, पीजी के एडमिशन में ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले, यह मांग भी कब से उठ रही है। वर्ष 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, लेकिन यह विषय तो उससे भी पहले से उठ रहा है। आखिर क्यों चिंता नहीं की गयी? क्या आप मोदी जी का इंतजार कर रहे थे? आज मैं कहना चाहती हूं कि इस देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी समुदाय से आने वाले युवा अभ्यर्थी राज्यों की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य से ज्यादा कट ऑफ अंक लाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी योग्यता का अभाव नहीं है, कहीं भी काबिलियत का अभाव नहीं है। अभाव है अवसरों का, इच्छा-शक्ति का। इस सदन में मैं कहना चाहती हूं कि दलित, पिछड़े, कमजोरों के हक में फैसले लेने की इच्छा-शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है।

महोदया, इस देश के वंचित तबके को, पिछड़ों को, दलितों को, कमजोरों को मोदी जी के नेतृत्व में यकीन है, विश्वास है, चाहे आपको हो न हो। हमें युवाओं के भविष्य की चिंता है। … (व्यवधान)

भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आपको युवाओं की ताकत पर भरोसा हो न हो, हमें है। हमारी सरकार जिस दिन से आई, युवाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन पर हमने ध्यान दिया। … (व्यवधान) आपमें सुनने का धैर्य नहीं है, आप सुनिए। इस वर्ष दिसम्बर, 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियों के नियुक्ति-पत्र भारत सरकार देने का काम कर रही है। हमने मिशन रिक्रूटमेंट के तहत इसकी शुरुआत की है। सात रोजगार मेलों का आयोजन हो चुका है। हर रोजगार मेले में 75 हजार सरकारी नौकरियों के नियुक्ति-पत्र बांटने का हमने काम किया है। आप मुझे बताएं कि क्या आपने एक साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं? हर संकल्प को हमने सिद्धि में बदला है।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : आप कृपया जल्दी कम्प्लीट कीजिए।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारी सोच है कि हमारे युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में तब्दील हों। मेरा अपना मंत्रालय, जिसके अंदर हमने वर्ष 2016 से स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू किया। उससे पहले इस देश के अंदर कुछ सौ स्टार्ट-अप्स हुआ करते थे, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि वर्ष 2016 के बाद हमारे मंत्रालय, हमारी सरकार के प्रयासों से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप बनकर उभरा है। … (व्यवधान) आज हमारे यहां डीपीआईआईटी रिकग्नाइज्ड एक लाख के करीब यानी 99 हजार 380 हैं। एक सौ से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जो हमारे देश के युवाओं ने बनाकर खड़े किए हैं। इससे किस हद तक रोजगार सृजन हो रहा है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

सभापति महोदया, हमने 1.37 करोड़ युवाओं का कौशल प्रशिक्षण करके उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने का काम किया है। खेलों के बारे में कल हमारे मंत्री जी बोल चुके हैं, अत: उस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती। इन्फ्रास्ट्रक्चर के बिना आर्थिक प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती और मैं इस सदन में कहना चाहती हूं कि जिस स्केल और जिस स्पीड पर, जिस स्पेस और जिस मैग्नीट्यूड से हमारी सरकार ने पूरे देश के कोने-कोने में देश के समग्र, संतुलित और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, फिर चाहे वह हाईवेज का निर्माण हो या मेट्रो का विस्तार हो, वह देखने योग्य है। 74 हवाई अड्डों से आज हम 148 हवाई अड्डों के संचालन पर पहुंच गए हैं। 3.28 लाख किमी हमने ग्रामीण सड़कें बना दीं। जिस बड़े पैमाने पर हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वह भी रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है।

(1640/MK/SPR)

सभापति महोदया, एक्सपोर्ट प्रमोशन, exports of the key drivers of economy. हमारे एक्सपोर्ट्स इस वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 770 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गए। पिछले वर्ष हमने 676 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स प्राप्त की थी। पिछले वर्ष से इस वर्ष में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर मैं इस क्वॉर्टर की बात करूं, तो अप्रैल से जून के बीच में हम ऑलरेडी 182 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हम दो ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स करके दिखाएंगे। यह भारत की क्षमता है। इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने हमें कहा है कि “Local goes global”. इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। हम अपने

एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के साथ ही अपने एक्सपोर्ट बॉस्केट्स को भी डायवर्सिफाई करने में निरंतर लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। वर्ष 2014 में जो हमारा 1941 करोड़ का रक्षा निर्यात था, वह आज वर्ष 2022-23 में 16 हजार करोड़ पहुंच चुका है।

सभापति महोदया, क्या मैं थोड़ा और बोल सकती हूं?

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आपका टाइम पूरा हो गया है। आप थोड़ा शॉर्ट में बोलिए। क्या आप दो घंटे तक बोलते रहेंगी?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: सभापति महोदया, मैं थोड़ा सा कृषि पर जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि किसानों के लिए बहुत दर्द और पीड़ा यहां पर हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा व्यक्त की जाती है। इसलिए, मैं कहना चाहती हूं कि किसानों के लिए सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है। उसके लिए बजट बनाना पड़ता है और योजनाएं लानी पड़ती हैं। हमने 11 करोड़ से ज्यादा की धनराशि 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके दिखाया। हमने एक लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खड़ा किया और कृषि बजट में हमने वर्ष 2013-14 से आज वर्ष 2023-24 में 5.7 गुना की वृद्धि की है। जो हमारा बजट वर्ष 2013-14 में 21,933 करोड़ हुआ करता था, आज वह बढ़कर 1 लाख 25 हजार 36 करोड़ हो चुका है। आज देश में खाद्यान्न का रेकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। आज यह 265 एमएमटी से बढ़कर 323 एमएमटी हो चुका है।

माननीय सभापति: अब आप बैठ जाइए।

श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: सभापति महोदया, मैं कन्क्लूड कर देती हूं।

माननीय सभापति: अब आप बैठ जाइए। आपका समय हो गया है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: सभापति महोदया, 9 वर्षों के सुशासन में हमारी सरकार ने देश को विकास की राह पर लाकर खड़ा किया है और देश को बदलकर रख दिया है। इस बदले हुए भारत की तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे परिदृश्य में हमारे विपक्ष के साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं।

सभापति महोदया, यह हास्यास्पद है। … (व्यवधान) यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा है। … (व्यवधान) लेकिन, यह प्रस्ताव लाकर आपने स्वयं अपनी कलई खोलने का काम किया है। आने वाले चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो हमारे विपक्ष के साथियों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हमारा एनडीए वर्ष 2014 के बाद वर्ष 2019 और उसके बाद वर्ष 2024 में हैट्रिक बनाकर मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए दोबारा वापस आएगा। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1644 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, Madam. This No-Confidence Motion is moved by the Opposition Parties. It reflects the sorrows, agonies, and all kinds of hardships faced by millions of Indians.

Regarding Manipur, everybody has explained. I myself had gone there two times; once with my party and once with our INDIA team. I do not want to narrate too much. You cannot even imagine the hardship they are facing; the hellish experience they are facing. We had visited a place where 1,300 inmates were there. That is in Imphal. Four months in a camp! We are all human beings. We can very much imagine how deplorable the situation is. We went there; our team went there. What was your approach?

(1645/MMN/SJN)

You pooh-poohed it. You made it as a joke. You even went up to say that ours was a kind of what is called 'show-off' and political tourism. When we went there, you described it as political tourism. I was thinking how hardened is your heart as if it is made out of cast iron and rock. Such was the cruelty of your heart. So, we have to think very seriously about this.

Now, I come to atrocities against the SC, ST, and minorities. What is happening in Nuh in the State of Haryana? It is anarchy there. People cannot go there. We used to think it as a very nice place. Cordiality among the people was there. It was spoiled by some interested party which wants to catch fish out of the troubled water. That is what is going on there.

Another thing I would like to say is about a new danger, that is, economic boycott of minorities. This House should hear about that. I am not quoting any other thing, except an article from today's *The Hindu* newspaper. It has written an article. The title of the article is, 'Economic boycott of minorities, a new form of untouchability.' It says: -

> "Muslim meat traders in Haryana's Gurugram have been gripped by fear since the happening of August 1 when a Vishva Hindu Parishad (VHP) rally in Nuh district turned violent and led to stone-pelting and clashes between different groups. Despite the passing of a week, meat traders are afraid to open their shops which are shuttered in the aftermath of the clashes.

One of the traders say that a Maha panchayat by local Hindu community members in Gurugram's Tigra village witnessed calls to boycott Muslims-run business."

How bad is the situation! This country is going to dogs. They are not even bothered about that. Such a situation is prevailing there. So, you have to be very careful on this kind of an issue.

Now coming to Gyan vapi, what for are you making it an issue? Your idea is to make that as another Babri Masjid. You want to make capital out of that. In 2024, the election is coming. You feel that if you raise this kind of an issue, in that way, you may cash in on. But I am telling you this kind of activity should not be there. It is totally against the interest of the people.

In this House, our forefathers passed a legislation. What is that legislation? The 1991 legislation was that whatever was the *status quo* as on August 15, the day of Independence, that will continue as it is. Nobody can have any further claim on that. That was the *status quo.* That was the intention of that legislation. It was a noble kind of legislation we passed in the best interest of the nation. Now, what is happening? You have opened the floodgate of troubles there. That is why, this is happening.

In a country like ours where pluralistic form of society is prevailing, this kind of activity should not be there. It is very easy to make an issue out of that, but what kind of calamity we are going to face is to be discussed thoroughly. Now, with due respect to the BJP leaders, I am saying they have started a propaganda by saying that that legislation should be annulled. What for? That is only to create confusion and unrest. … (*Interruptions*)

I am bringing before this House certain very important things. This country, a good country with all its tolerance, is now going from bad to worse. I am coming to saffronisation of the education system. What is the danger in that? All the institutions like the NCERT, UGC, ICHR are polluted. They are saffronised. We are injecting poison in the veins of the budding generation. You are doing that kind of things.

(1650/VR/SPS)

Madam, recently the Government has made another announcement with regard to Uniform Civil Code. I do not want to go into the detail. But the Law Minister once said that various States can have legislation on Uniform Civil

Code. What wonder are you saying? Andhra Pradesh will make one law. Haryana will make another law. Kerala will make another one. Then, what is the meaning of Uniform Civil Code? These kinds of things are happening in our country. *....(Interruptions)*

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): बशीर जी, कृपया बैठ जाइए।

श्री ए. आर. रेड्डी जी।

....(Interruptions)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Just finishing in a minute. *....(Interruptions)*

You are spitting venom of communalism. You are ruining the concept of secularism. You are spreading Islamophobia. *....(Interruptions)*

It goes without saying that all of your activities in the last nine years are dangerous and injurious to the system of administration. These kinds of things are going on.

If you go through the international indices and do a comparative study with respect to India, you will get only a diminishing picture. That is all happening here.

माननीय सभापति: बशीर जी, कृपया बैठ जाइए।

....(Interruptions)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): I want to appeal before the Government – the Law Minister is here; the Home Minister is here – not to spoil this country. You may have some gain out of it. But you are spoiling this country. You are spoiling the harmony in the country. You have to be very careful. Once the greatness of this nation is lost, you may not be able to regain it. *....(Interruptions)*

माननीय सभापति: श्री ए. आर. रेड्डी जी।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): With these words, I conclude my speech. Thank you very much. *....(Interruptions)*

(ends)

1652 hours

*SHRI ANUMULA REVANTH REDDY (MALKAJGIRI): Madam Chairperson today is 9th August which is observed as International Tribals' Day. From this platform I extend my warm greetings to the brothers and sisters from tribal communities. When there is a blood bath, beheadings in Manipur, where women are being raped and killed, where tribals are being subjected to attacks, atrocities and killings - on this occasion of International Tribals' Day, the Prime Minister should have came to the House to offer his apologies to the tribals in Manipur, by doing so, he would have gained respect. But the Prime Minister does not have respect for tribals and adivasis that is the reason why he did not attend the House. This is not only about incidents that are happening in Manipur but this is also about how the Prime Minister for the last 9 years did not fulfill his promises and betrayed people of this country, in this context I am here on behalf of Congress Party to support the motion of no-confidence in the Council of Ministers moved by my colleague Gaurav Gogoi from I.N.D.I.A team. People of this country lost confidence in the Prime Minister Shri Narendra Modi and Council of Ministers therefore on behalf of 140 crore Indians we are here to speak on motion of no confidence in the Prime Minister and Council of Ministers.

In Manipur and in tribal areas, Britishers followed the policy of 'divide and rule' by dividing the people on the lines of language, caste, community and religion. This 'divide and rule' policy followed by Britishers is now being implemented by the British Janata Party i.e. BJP by creating rift amongst Kukis, Nagas and Meiteis in Manipur. Implementing Britishers' policy of 'divide and rule', to retain power in Manipur as well as in the country, will be opposed by the Congress Party and I.N.D.I.A team. This is the reason why we introduced the Motion of no-confidence in the Council of Ministers.

When Manipur was boiling, women were being attacked; there was blood bath and killings, but our Prime Minister and Home Minister instead of taking help of Central forces to contain the situation and establish law and order in Manipur they were touring in Karnataka to seek votes of people of Karnataka. Even though they tried to use Ram and Bajrangbali for their political gains, people of Karnataka rejected BJP in Karnataka. This Judgment of the people of Karnataka will serve as a guide for the people of this country. When the country was suffering, there were bloodbaths and killings of tribals but the Prime Minister and the Home Minister did not visit Manipur and were in Karnataka seeking votes of the people of Karnataka. This shows

*Original in Telugu

that they are only interested in elections, political gains and financial gains. This government is not interested in protecting the lives of the people or in the welfare of the people. That is the reason why, even after 90 days of disturbances in Manipur, responsible Prime Minister has not come to the House. NDA means Nation Divide Alliance. BJP is using the Nation Divide Alliance for their political gains. We are questioning the Nation Divide Alliance by introducing a motion of no confidence in the Council of Ministers. Had the Prime Minister listened to the concerns of the Members and tried to mitigate the problems of Manipur, his respect would have increased. But he is only concerned about political gains and he has no respect or concerns for the country, it's people or communities. Today we are observing International Tribals' Day; still the Prime Minister did not attend the House. I request you Chairperson on behalf of 140 crore Indians to ask honorable Prime Minister to come to the House and fulfill his responsibilities for the State of Manipur and instill a sense of confidence and trust amongst the people of Manipur. Honourable chairperson you have the right to call the Prime Minister to the House. You are the custodian of this House and you can ask the Prime Minister to come to the House.

Honourable Chairperson, I regularly travel from Hyderabad. Whenever my flight gets delayed I visit Book stores at the airport. I casually asked the sales person in the book store about a book which consists of several lies. That book store owner offered me not one but two such books. The first book's name was 'Ek Bharat, Shreshth Bharat' which is the election manifesto of BJP in 2014. Second book is Sankalpit Bharat and Sashakt Bharat. If you look at the first book you can see the pictures of Vajpayee ji, Advani ji, Rajnath Singh Ji, Murali Manohar Joshi ji, Sushma Swaraj ji, Arun Jaitley ji, and all these leaders were part of election manifesto of BJP in 2014. In 2019 election manifesto, except Narendra Modi no other leader is part of this manifesto. The BJP led NDA government which started in 2014 with 10 leaders, has left with only one leader Narendra Modi in 2019. After introducing one Nation one election, one Nation one tax, now it is one Nation only one person which is being introduced by BJP. This is a matter of concern and this is an insult to our country.

Respected Madam, I would like to remind them of what they promised in their manifesto. They promised 2 crore jobs every year. By now they have received 22 crore job applications but they have given only 7,22,311 jobs. This is not the figure I am quoting, this was the answer given to my question. They had also promised pucca houses for the poor. They have promised doubling of income of farmers. They also promised to bring back black money and deposit Rs 15 lakh in every poor person

s account. They are going to complete 10 years of their tenure but they could

not fulfill any of their promises and that is the reason why we are coming up with motion of no confidence in the Council of Ministers and we say that this Government does not have any right to continue for even a minute and this Government should resign immediately. Narendra Modi ji has come up with an easy technique of Swachh Bharat; we will have to clean with our own broom.

(1700/YSH/SNT)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): श्री अमित शाह जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैंने आपको पूरा टाइम दिया है। अब आप बैठिए।

... (व्यवधान)

1700 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी): इस देश में लिकर पार्टी और निक्कर पार्टी एक हो गई हैं और तेलंगाना को लूटने में लग गई हैं। वह लिकर पार्टी है और यह निक्कर पार्टी है। ये दोनों मिलकर तेलंगाना को लूटने में लग गए हैं इसलिए आज इन दोनों के खिलाफ हम इस सभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं।... (व्यवधान) तेलंगाना को जो आश्वासन दिए, इन्होंने वे आश्वासन पूरे नहीं किए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप क्यों कह रहे हैं। वे खुद ही कह रहे हैं कि हम एक हो गए तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चलिए बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका समय पूरा हो चुका है। प्लीज, कंक्लूड कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी): स्पीकर सर, मैं अमित शाह जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। Dr. Keshav Baliram Hedgewar, who had started RSS in 1925 belongs to Kandakurthi, Nizamabad District, Telangana State. तेलंगाना से जो हैं, वे नागपुर के नहीं हैं। वे निजामाबाद-कान्दाकुर्थी, तेलंगाना के ही हैं इसलिए तेलंगाना के ऊपर आप गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं।... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

... (व्यवधान)

1702 बजे

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): भाई, अब बैठ जाइए। माइक बंद हो गया है। अध्यक्ष जी ने मुझे खड़ा किया है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त मौका दिया है।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष के सदस्य, श्री गौरव गोगोई, जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में उपस्थित हुए थे, उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोक सभा के प्रति जवाबदेह है। इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबिंबित करने के लिए लोक सभा के नियमों के नियम 198 (1) से 198 (5) तक मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई।

माननीय अध्यक्ष जी, हम जब से आजाद हुए हैं, तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन-आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आते हैं। यह अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है, जिसमें प्रधान मंत्री और मंत्रीमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करना है। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो इस पर जो चर्चा होती है, उस चर्चा में आप सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते।

(1705/RAJ/KKD)

मैंने पूरे भाषण को ध्यान से सुना है और पूरे भाषण को ध्यान से सुनने के बाद, मैं निश्चित रूप से इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है। यह प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं है। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है। अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है कि अब तक जो अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं, मतदान होगा, जब कराएंगे, तब होगा, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है, वह बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है। मान्यवर, जनता में भी विश्वास है। जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधान मंत्री और एक सरकार ने किया है, तो वह नरेन्द्र मोदी सरकार है।

मान्यवर, मैं डिटेल बात बाद में करूंगा। मैं भी देश भर में घूमता हूं, जनता के बीच में जाता हूं। मैंने जनता के साथ कई जगह संवाद किया है। कहीं पर भी अविश्वास की ओछी, पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती है।…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मणिपुर में क्या दिखा?

श्री अमित शाह : मैं उसके बारे में बताता हूं। मैं बंगाल के बारे में भी बताता हूं।…(व्यवधान)

मान्यवर, आपके और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में है। दो-तिहाई बहुमत से दो-दो बार एनडीए को चुना गया। पूर्ण मत से, पूर्ण बहुमत से दो-दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया है। 30 सालों के बाद, पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम, इस देश की जनता ने लगातार दो बार किया है।

मान्यवर, आजादी के बाद देश में अगर कोई सबसे लोकप्रिय प्रधान मंत्री हैं, तो वह नरेन्द्र मोदी जी हैं और यह मैं नहीं कहता हूं। यह दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते हैं। आजादी के बाद सबसे ज्यादा, एक भी छुट्टी लिए बगैर, 24 घंटों में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधान मंत्री है, तो वे नरेन्द्र मोदी जी हैं।

मान्यवर, आजादी के बाद देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधान मंत्री है, तो वे नरेन्द्र मोदी जी हैं। मान्यवर, कोई सरकार कई सालों तक चलती है। काँग्रेस पार्टी की सरकार 35 सालों तक अक्षुण्ण रूप से चली। कई सालों तक सरकार चलती है, तब दो-तीन-चार निर्णय ऐसे होते हैं, जिनको युगों तक याद किया जाता है।

मान्यवर, नरेन्द्र मोदी सरकार को नौ साल हुए हैं और नौ सालों में 50 से ज्यादा ऐसे फैसले हैं, जो युगांतकारी फैसले हैं। जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से निबंधित हैं। मान्यवर, आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी जी ने हमारी अजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। उन्होंने नारा दिया था कि ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’, ‘क्विट इंडिया’ का नारा दिया था। मोदी जी ने वर्ष 2014 से 2023 तक, लगभग साढ़े नौ सालों में, एक नए प्रकार के राजनीतिक युग की शुरुआत की है।

मान्यवर, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के नासूर से ग्रसित रही है।

(1710/KN/AK)

सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय-पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारी जय-पराजय को देख लें। मोदी जी की वर्ष 2014 की विजय के पहले सारी जय-पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थी, भ्रष्टाचार किया, इसको हटाने के लिए आए या तो परिवारवाद से प्रभावित थे। परिवारवाद के पीछे जातिवाद की एक अनवरत संतान भी होती है और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश भी था। भारतीय लोकतंत्र को इन तीन नासूरों ने घेर लिया था। नरेन्द्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटा कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी। आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं-कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखाई ही पड़ता है और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है कि भ्रष्टाचार – क्विट इंडिया, परिवारवाद – क्विट इंडिया, तुष्टीकरण – क्विट इंडिया।

मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण क्विट इंडिया कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने वर्ष 2014 से विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। वह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना के भारत की निर्मिती वर्ष 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, विपक्ष का यह अधिकार है कि वह अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आए। मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव से पार्टियों और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि कई बार अविश्वास के प्रस्ताव आए। मैं तीन अविश्वास के प्रस्ताव का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। दो अविश्वास प्रस्ताव यूपीए सरकार के खिलाफ थे, जब हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे। एक अविश्वास प्रस्ताव एनडीए सरकार के खिलाफ था, जब यूपीए विपक्ष में थी तब वे लेकर आए थे। जुलाई, 1993 में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी। उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचाने होती है और नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। येन-केन-प्रकारेण कांग्रेस का मूल सिद्धांत है कि सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। इसके लिए न सिद्धांत होते हैं, न नीतियां होती हैं और न औचित्य होता है। मान्यवर, नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई। स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास

प्रस्ताव पर विजय प्राप्त की थी। आज कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है।

मान्यवर, वर्ष 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार देश में बराबर वातावरण बन गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है और बहुमत था भी नहीं। इस सदन को उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी, सांसदों को करोड़ों रुपये की घूस देनी पड़ी। हमारे ऑनेस्ट सांसद वह रुपये लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए। हमें रुपये ऑफर किए गए हैं। वह सरकार बचा ली। एक तो यूपीए का चरित्र है, सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाए, इसलिए वे विश्वास का प्रस्ताव स्वयं लाए। इससे बचने के लिए सारे सिद्धांत, सारा चरित्र, लोक सभा के सारे नियम-कानून, हमारी परंपराओं को त्याग कर येन-केन-प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबिज रहना। इसके सामने और एक दूसरा उदाहरण है। वर्ष 1999 में अटल जी की सरकार थी और अविश्वास का प्रस्ताव आया। यह जो कांग्रेस ने किया, वह हम कर सकते थे। क्योंकि वर्ष 1993 में नरसिम्हा राव जी ने देश के सार्वजनिक जीवन का एक एग्जाम्पल पूरा कर दिया था कि सरकार ऐसे भी बचाई जा सकती है।

(1715/VB/UB)

करोड़ों रुपए देकर भी सरकार बचाई जा सकती है। यह हम भी कर सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हमने हमारी बात रखी। देश के प्रधानमंत्री श्री अटल जी ने अपनी बात रखी। इसी सीट पर बैठकर सांसदों के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने जो कहा कि संसद का जो फैसला है, उसे मैं सर पर रखूँगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

मान्यवर, सिर्फ एक वोट से सरकार गयी, सिर्फ एक वोट से। क्या हम यूपीए और कांग्रेस की तरह सरकार नहीं बचा सकते थे? हम बचा सकते थे। मगर मैंने कहा न, कई बार संकट के समय गठबंधन और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है।

मान्यवर, उस वक्त मैं संसद में नहीं था, मैं संसद का सदस्य नहीं था। उस वक्त बहुत-से सीनियर सदस्य होंगे। उस वक्त एक ही वोट का फर्क था। अंत में, गिरिधर गमांग के वोट को, जो उस वक्त ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे और यहाँ वोट डालने आए थे। उस वोट को वैलिड गिनना या न गिनना, मगर मान्यवर, आप जिस आसन पर बैठे हैं, इस आसन की गरिमा का भी एनडीए ने पालन किया था। हमने कोई दबाव नहीं बनाया।

एक वोट हमारे विरुद्ध गया। हमारी सरकार चली गयी। मगर आज मैं गौरव गोगोई जी को फिर से कहना चाहता हूँ कि जनता है, जो सब देखती है, जनता है, जो सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गयी, एक वोट से हमारी सरकार जरूर गयी, परंतु अंत में क्या हुआ, बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने।

मान्यवर, हमारे एनडीए का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, देश में सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्थापित करने के लिए राजनीति में है, येन-केन-प्रकारेण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति में नहीं है। ये दो चरित्र वाले हैं। मैं आज इस अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के माध्यम से, इस देश की 130 करोड़ जनता को याद कराना चाहता हूँ कि एक ओर करोड़ों रुपए खर्च करके बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक ओर सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग बैठे हैं। इसका निर्णय देश की जनता को लेना है।… (व्यवधान) अभी शुरुआत है, आप धैर्य रखें, अभी काफी सुनना पड़ेगा।… (व्यवधान) सुरेश जी, यह तो अभी ट्रेलर है।… (व्यवधान)

मान्यवर, अभी गरीब कल्याण की बात निकली। हमारी साथी मंत्री अनुप्रिया जी, गरीब कल्याण के बारे में सारी बातें बता रही थीं। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। सालों तक गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर देश की भोली-भाली गरीब जनता का विश्वास प्राप्त किया और वोट लेते रहे, जीतते रहे, लेकिन गरीबी जस की तस रही। नरेन्द्र मोदी जी ने कोई बड़े-बड़े वायदे नहीं किये। परंतु नरेन्द्र मोदी जी के जेहन में गरीबी का डंक भी था, दंश भी था क्योंकि वे स्वयं गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में आ गये।… (व्यवधान) इन्होंने गरीब कल्याण के लिए… (व्यवधान) मान्यवर, इन्होंने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे… (व्यवधान) मान्यवर, सुरेश जी इतने सीनियर मेम्बर हैं, उनको अविश्वास प्रस्ताव का कैरेक्टर मालूम नहीं है।… (व्यवधान) आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो सरकार के समग्र कामकाज पर क्वेश्चन मार्क करते हैं। चूंकि यह क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए मुझे सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा करनी पड़ेगी।… (व्यवधान)

मान्यवर, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक इस देश के करोड़ों गरीबों के नसीब में धुएँ से भरे हुए घर थे। मोदी जी ने 9.6 करोड़ यानी नौ करोड़ साठ लाख गरीब महिलाओं के घरों में गैस के सिलिंडर भेजे और उनकी झोपड़ी को धुएँ से मुक्त कराने का काम किया।

(1720/PC/SRG)

मान्यवर, 11 करोड़ परिवार ऐसे थे कि दुनिया में कोई विचार नहीं कर सकता था। कई देशों की आबादी 11 करोड़ से आधी भी नहीं है, पांचवे हिस्से की भी नहीं है। परंतु, 11 करोड़ परिवार ऐसे थे, जिनके पास शौचालय नहीं था। हर रोज उन घरों की महिलाएं आहत होती थीं। उनका दर्द 55 सालों तक यूपीए – कांग्रेस ने नहीं जाना। … (व्यवधान) जब श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने, तब उन्होंने नौ सालों के अंदर 11.72 करोड़ परिवारों को शौचालय देने का काम किया। … (व्यवधान)

मान्यवर, देश के बहुत बड़े तबके में, विशेषकर गरीब के घर में, दलित के घर में, आदिवासी के घर में, पिछड़े के घर में, झोपड़पट्टी में रहने वाले के घर में पीने का शुद्ध पानी नहीं था। वे फ्लोराइड युक्त पानी पीते थे। भरी जवानी में बूढ़े हो जाते थे, बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थीं। मान्यवर मोदी जी ने 'हर घर जल' के माध्यम से 12.65 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। … (व्यवधान)

मान्यवर, ये हमेशा बोलते हैं, अभी भी चुनाव में कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि दस सालों में इन्होंने कितना कर्ज माफ किया? वर्ष 2004 से वर्ष 2014, दस सालों तक आप रहे। आपने कितना कर्ज माफ किया? 70,000 करोड़ रुपए माफ किए। इसमें से भी 35,000 करोड़ रुपए तो नीचे बाकी रह गए हैं, लेकिन चलो, मान ही लें कि 70,000 करोड़ रुपए ही माफ किए हैं। हम किसी का कर्ज माफ करने में विश्वास नहीं करते हैं, उसको कर्ज ही न लेना पड़े, ऐसी व्यवस्था उसे देते हैं। … (व्यवधान)

मान्यवर, इस देश के 14.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 2,40,000 करोड़ रुपए डाले। … (व्यवधान) अब देश के किसान तय करें कि एक और 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज की लॉलीपॉप देने वाली यूपीए सरकार है और एक ओर किसान के घर में सम्मान के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2,40,000 करोड़ रुपए देने वाली सरकार है। … (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आज और स्पष्टता करना चाहता हूं। यह रेवड़ी नहीं है। हमने यह करने से पहले एक सर्वे किया कि ढाई एकड़ से कम जिसकी जोत है, उस किसान को कितना खर्च बेसिक खेती के काम के लिए आता है? क्योंकि वह तो मजदूर नहीं रखता है, स्वयं ही बेचारा मेहनत करता है। इरीगेशन, बीज और खाद का कितना खर्चा आता है? ढाई एकड़ से कम जिसकी जोत है, उसका खर्चा छः हजार रुपए आता है, मोदी जी ने छः हजार रुपए उनको दे दिया कि भैया, तुम ऋण ही मत लो। … (व्यवधान) आपने तो एक बार किसान को ऋण मुक्त किया, मोदी जी ने पूरे जीवन के लिए उसको ऋण मुक्त करने का काम किया है। … (व्यवधान)

मान्यवर, इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे थे, करीब-करीब 60 करोड़ लोग ऐसे थे, जिनके घर में बीमारी आ जाए, तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, इसका डर नहीं लगता था, इलाज का खर्च कितना आएगा, इसका डर लगता था। वह पूरा परिवार ऋण के बोझ के तले दब जाता था। मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा माफ कर दिया है। … (व्यवधान) आज देश के किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती है, तो पांच लाख रुपए तक का सारा इलाज, चाहे ऑपरेशन करना हो, चाहे दवाइयां लेनी हों, चाहें टेस्ट्स कराने हों, यहां तक कि अस्पताल से घर जाने के लिए रिक्शे के 200 रुपए भी हम दे रहे हैं। पांच लाख रुपए हर परिवार को दे रहे हैं। मान्यवर, जब हम बैंकों में अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए, तब मजाक उड़ाया जाता था। बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतिश कुमार जी ने हमारा कड़ा मजाक उड़ाया कि अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालोगे, ज़रा बोनी तो कराओ। नीतिश बाबू, आज मेरी बात सुन लीजिए।

(1725/CS/PS)

हमने 49 करोड़ 56 लाख अकाउन्ट खोले, जिनमें 2 लाख करोड़ रुपये गरीबों के जमा हैं। राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जन-धन अकाउन्ट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब ये जन-धन योजना का विरोध क्यों कर रहे थे, यह समझने वाली बात है। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे पहुँचते हैं। वह तो ठीक है, स्वीकृति की, सच्चे आदमी थे, नए-नए राजनीति में आए थे, बोल गए, मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं। ये 85 पैसे कौन ले जाता था?… (व्यवधान) ये 85 पैसे कौन ले जाता था? … (व्यवधान) मान्यवर, 85 पैसे ये ले जाते थे, जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी। जो जन-धन योजना का विरोध कर रहे हैं, वे 85 पैसे एन्जॉय करने वाले लोग हैं। अब भारत सरकार रुपया भेजती है तो सीधा रुपया पहुँच जाता है, कांग्रेस की तरह 15 पैसा नहीं, सीधा रुपया गरीब के घर में पहुँच जाता है।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): डीबीटी की शुरुआत किसने की? … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : भई! आप योजना तो बनाते हो, लेकिन करते नहीं हो।… (व्यवधान) आप बैठिए, मैं बताता हूँ।… (व्यवधान) आप बैठो, मैं बताता हूँ।… (व्यवधान) आप बैठिए।… (व्यवधान)

मान्यवर, ये कह रहे हैं कि डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे कि जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीबी हटाओ किसने कहा, आपने कहा सब-कुछ, किया कुछ नहीं, किया हमने है। आप तो कहते ही रह गए।… (व्यवधान) आप तो कहते ही रह गए।

मान्यवर, 25 लाख करोड़ रुपया, इस देश की 130 करोड़ की जनता इसका सीधा प्रसारण देख रही है, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि एक पैसे के कमीशन के बगैर, कटकी के बगैर 25 लाख करोड़ रुपया देश के गरीबों के बैंक अकाउन्ट में सीधा ट्रांसफर हुआ है।

मान्यवर, कोरोना आया। मोदी जी ने शुरूआत की। पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठकर, संघ भावना से शुरूआत की। यह पूरे समाज की लड़ाई है, पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है, पक्ष-विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए। सबको साथ में रखकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई की शुरूआत हुई। मैं आज भी कहता हूँ, मैं आज भी मानता हूँ कि कोरोना के खिलाफ सफलता से लड़ पाया है, उसका एकमात्र कारण है कि सभी जगह दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ीं, भारत में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ लड़े हैं, इसलिए हम सफल हुए हैं। मगर जब वैक्सीनेशन आया और

उनको लगा कि यह तो देश बच जाएगा, तो मोदी वैक्सीन-मोदी वैक्सीन कहा गया। मुझे दो नेताओं का बराबर याद है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और राहुल जी, दोनों ने कहा कि यह तो मोदी वैक्सीन है, लेना मत।... (व्यवधान) आप बैठ जाइए।... (व्यवधान)

मान्यवर, जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया।... (व्यवधान) मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी।... (व्यवधान) फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी।... (व्यवधान) पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का काम किया।... (व्यवधान)

मान्यवर, इसके साथ-साथ उस वक्त रोजगारी के प्रश्न खड़े हुए।... (व्यवधान) लॉकडाउन का भी विरोध किया गया।... (व्यवधान)

(1730/RV/SMN)

मान्यवर, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। सबने कहा कि यदि लॉकडाउन लगाएंगे तो गरीब क्या खाएगा? हमारे सामने दो रास्ते थे - लॉकडाउन न लगाना और पूरे देश की जनता कोरोना में फँस जाए, लाखों-करोड़ों लोगों की मृत्यु हो, हमने लॉकडाउन भी लगाया और उसको भूखा भी नहीं रखा। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज, लॉकडाउन के समय हमने गरीब के घर पहुंचाया। उसका चूल्हा जला और वह आज भी चल रहा है।... (व्यवधान) प्रधान मंत्री में और मंत्रिमंडल में अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को, देश की जनता को यह नहीं है, क्योंकि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पी.एम. किसान योजना के तहत ढाई लाख करोड़ रुपये मोदी जी ने पहुंचाए, तीन करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को पाँच-पाँच लाख रुपये उनके स्वास्थ्य के लिए खर्च राशि दी, 49 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपये भेजे, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को यह अविश्वास नहीं है, वह मोदी जी के साथ है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता हैं, जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया और वे 13 बार ही फेल कर गए। उनकी एक लॉन्चिंग मैंने देखी है। उनकी एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुई थी। एक गरीब माँ, जिसका नाम कलावती था, बुंदेलखण्ड की बहन कलावती के घर वे नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठ कर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन कि लोग द्रवित हो जाएं, ऐसा वर्णन उन्होंने किया। यह ठीक है, आपने अच्छा किया कि आप इतने बड़े व्यक्ति होकर उस गरीब कलावती के घर भोजन करने गए, उसके यहां भोजन कर लिया और उसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर, बाद में उनकी सरकार छः साल चली। मैं पूछना चाहता हूं कि उस कलावती के लिए क्या किया? उस कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेन्द्र मोदी ने किया। इसलिए, जिस कलावती के घर आप भोजन के लिए गए थे, उसको भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, आज वह मोदी जी के साथ खड़ी है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़े वर्गों को संवैधानिक मान्यता दी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत का रिजर्वेशन, इतने सालों के बाद, पहली बार मिला।

महोदय, हमें राष्ट्रपति बनाने के लिए उम्मीदवार को चयनित करने का दो-दो बार मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एन.डी.ए. ने, बी.जे.पी. ने एक बार दलित और एक बार आदिवासी, भारत में पहली बार, हमने बनाया।

महोदय, यह सरकार गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। नरेन्द्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, उससे अगर गरीब के घर में जाते हैं तो वे 'दीन-मित्र' कह कर नरेन्द्र मोदी जी को बुलाते हैं। अब गरीब, मोदी जी में अपना मित्र ढूँढ़ता है। इसलिए, मैं कह रहा हूं कि अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है।

(1735/GG/RU)

मान्यवर, अटल जी इस देश को विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़ कर गए थे। … (व्यवधान) अटल जी तो जननेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता के नाते काम करते-करते, आइडोलॉजी का प्रचार करते हुए देश के प्रधान मंत्री बने थे। उन्होंने 6 सालों तक सरकार चलाई और 6 सालों में 15वें नंबर से 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर ले कर आए। फिर एक अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री बने, यूपीए की सरकार आयी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए। उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा और फिर नरेंद्र मोदी जी आए। ढेर सारे अर्थशास्त्री पंडित कहते थे कि मोदी जी देश का लोकतंत्र कैसे संभालेंगे, मनमोहन सिंह जी चौपट कर के गए हैं, सारे ग्राफ उलटे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ यह आदमी, संघर्ष कर के राजनीति में आया हुआ यह आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्य मंत्री बनने वाला यह आदमी - नरेंद्र मोदी, इसने 9 सालों में देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया है। … (व्यवधान)

मान्यवर, मुझे तो भरोसा है कि मेरे ज्यादातर साथी चुन कर भी आएंगे। वे भी देखेंगे कि फिर से एक बार मोदी जी प्रधान मंत्री बनेंगे और देखते ही देखते वर्ष 2027 तक देश इस दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। … (व्यवधान) मान्यवर, यह मैं नहीं कहता हूँ। आईएमएफ भी कहता है, विश्व भर के सारे सर्वेक्षण वाले कहते हैं कि डार्क ज़ोन में ब्राइट स्पॉट अगर कोई है तो भारत का अर्थतंत्र है। … (व्यवधान)

अधीर जी, अभी नहीं कह सकते हैं, बैठ जाइए। … (व्यवधान) नियम आपको मालूम होना चाहिए। … (व्यवधान) नियम पढ़ लीजिए, अभी यील्ड नहीं कर सकते हैं। … (व्यवधान) अरे! भई, आपकी पार्टी ने आपको बोलने के लायक नंबर ही नहीं रखे हैं तो क्यों खड़े हो-हो कर बोलते हो? … (व्यवधान) न आप लीडर ऑफ ऑपोज़िशन हो, न आप चर्चा शुरू करते हो, न आपको बोलने देते हैं। … (व्यवधान) आप मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो? … (व्यवधान) आपकी पार्टी वाले आपको बोलने ही नहीं देते हैं। … (व्यवधान) आप बैठ जाओ। … (व्यवधान)

मान्यवर, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में और आने वाले दशकों में दुनिया के अर्थतंत्र का, दुनिया भर के अर्थतंत्र के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उन सब में दूरदर्शितापूर्ण फैसले ले कर, मोदी जी ने सटीक नीतियां बना कर, उसके अंदर एक फाउंडेशन डालने का काम समाप्त कर दिया है। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल वीकल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, चाहे

इलैक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वांटम इंजिनियरिंग के अंदर संवर्धन और आरएण्डडी करना हो और चाहे ऑर्गेनिक फूड का बाज़ार खड़ा करना हो, ये सातों जो इमर्जिंग क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र में माने जाते हैं, उन सातों क्षेत्रों में मोदी जी ने ऐसा फाउंडेशन डाला है कि आने वाले 5 सालों में ही भारत दुनिया के अर्थतंत्र में एक प्रमुख शक्ति बन कर उभरेगा। इसका मुझे विश्वास है।

मान्यवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर की गतिशक्ति के तहत सिर्फ वर्ष 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम पूर्ण कर देंगे। वर्ष 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रति दिन बनाए हैं। 148 हवाई अड्डे बने हैं। मोदी जी के आने के पहले 74 थे, अब 148 हो गए हैं। वंदे भारत, सेमी-हाइस्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है। 99 हज़ार करोड़ रुपये की सागरमाला परियोजना, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दूरगामी कदम है, वह पूरा हो चुका है। देश की कार्गो हैण्डलिंग की क्षमता 79 प्रतिशत बढ़ी है, जो कि अगले साल तक दोगुनी हो जाएगी। 27 शहरों में मेट्रो उपलब्ध कराई है। भारत-नेट को 6.20 लाख किलोमीटर तक फैला दिया है, लाखों गांवों तक भारत-नेट को पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

मान्यवर, इंटरनेट कनेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत ने दर्ज की है। 231 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पूर्वोत्तर के लिए भी ढेर सारे एयरपोर्ट्स बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।

(1740/MY/SM)

मान्यवर, स्वास्थ्य के बजट में भी 139 प्रतिशत की वृद्धि नरेन्द्र मोदी सरकार ने की है। पिछले आठ वर्षों में 4,85,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। एमबीबीएस की सीटों में 93 परसेंट की वृद्धि हुई है। पी.जी. की सीटों में शत-प्रतिशत की वृद्धि करके डॉक्टर की संख्या को दोगुना करने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, ढेर सारे विषयों को मेरे साथियों ने उठाया है। मुझे अभी मणिपुर पर भी बात करनी है। मान्यवर, नरेन्द्र मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। चाहे क्लाइमेट चेंज का विषय हो या टेररिजम, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का काम अगर आज कोई एक देश कर रहा है तो हमारा महान भारत कर रहा है।

मान्यवर, जी-20 का नेतृत्व जब हमें मिला, यह बहुत सारे देशों को मिला, लेकिन एक ही शहर में कार्यक्रम न करके देश के 55 स्थानों पर करके पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। यह सब इन लोगों को पसंद नहीं आता है। विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है, जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, वैसे तो उनको व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर मैं इस महान सदन में कहना चाहता हूं कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है कि इन 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, यह देश की 130 करोड़ जनता का सम्मान है। यह भारत का सम्मान है, जो नरेन्द्र मोदी जी को मिला है। आपको भले ही अविश्वास हो, लेकिन देश की जनता को अविश्वास नहीं है।… (व्यवधान)

दादा, इस चुनाव में आपको पता चल जाएगा। … (व्यवधान) इस चुनाव की काउंटिंग में आपको पता चल जाएगा और आप मुझे फोन करना।… (व्यवधान) मान्यवर, देश की सुरक्षा

कैसी थी? यूपीए की सरकार थी, वह वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक चली। आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे। आलिया, मालिया, जमालिया घुसते थे और जवानों के सर काटकर ले जाते थे।... (व्यवधान)

मान्यवर, सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं देता था। पाकिस्तान ने दो बार हिमाकत की। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी बार एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुस कर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया। श्रीमान राजनाथ जी यहां बैठे हैं। सीडीएस का मसला भी आपकी सोच थी, लेकिन इम्प्लीमेंट हमने किया। सीडीएस का मसला कब से लटक रहा था, भटक रहा था। मोदी जी ने सीडीएस का फैसला किया। राजनाथ जी ने सभी को विश्वास में लेकर उसको पार उतारा। वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में एयर स्ट्राइक किया गया। डिफेंस में खरीदी के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, मैं आपको बताता हूं कि जितने भी घोटाले हुए, मैं बाद में यूपीए के घोटाले के बारे में बताता हूं। जितने भी घोटाले हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा करप्शन रक्षा की खरीदी में हुआ है। मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री जी ने 4,100 आइटम्स को इम्पोर्ट की नेगेटिव लिस्ट में डालकर यहाँ पर उनका उत्पादन किया।

मान्यवर, आत्मनिर्भर भारत की रचना कैसी होती है, इसकी नींव कैसे डाली जा सकती है, डिफेंस जैसे अति टेक्नोलॉजी और स्पर्धात्मक क्षेत्र में इस काम को नरेन्द्र मोदी जी ने किया। आज भारत का रक्षा उत्पादन, न केवल भारत के लिए, बल्कि कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। आज भारत रक्षा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बना है। उतर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं। वर्ष 2022-23 में 16,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात किया गया है। अभी यह आंकड़ा लाखों-करोड़ों में जाने वाला है।

(1745/CP/RP)

मान्यवर, चार दशकों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधान मंत्री थीं तब से, देश की सेना का जवान चाहे सर्विंग हो, चाहे रिटायर्ड हो, वह वन रैंक, वन पेंशन की मांग कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेन्द्र मोदी जी ने सेना के सम्मान में निर्णय किया और 42 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वन रैंक, वन पेंशन में दी।

मान्यवर, दुनिया में अस्थिरता बढ़ी। चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसे हुए हमारे भारतीय हों, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ानें कराके दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात करके तीन दिन तक युद्ध बनकर 23 हजार भारतीयों को घर पर लाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। ऑपरेशन राहत में 5 हजार भारतीय और 2 हजार विदेशी नागरिकों को यमन से निकाला और 2 लाख उड़ानों के माध्यम से 2.97 करोड़, मतलब करीब 3 करोड़ यात्रियों को सकुशल कोरोना के वक्त वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाये। मान्यवर, चीन की सीमा पर हमारी आट्रिलरी न पहुंचे, ऐसी स्थिति थी। रोड ही नहीं बनाये गए थे। नक्शा ही देखते रहते थे। नरेन्द्र मोदी जी और राजनाथ जी की टुकड़ी ने सीमा के अंतिम गांव तक, भारत के प्रथम गांव में रोड पहुंचाने का काम किया। वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से, गांव खाली न हो, इसकी चिंता नरेन्द्र मोदी जी ने की।

मान्यवर, किसानों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। बजट में छ: गुना वृद्धि की। सुरेश जी, सुनिए। आप लोग 21,900 करोड़ रुपये छोड़कर गए थे, आप ध्यान से सुनना 21,900 करोड़ रुपये को 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपये का बजट नरेन्द्र मोदी जी ने दिया। खाद्यान्न का उत्पादन 265 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 323 मिलियन टन रिकार्ड उत्पादन हुआ। मैं प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना की बात कर चुका हूं। 14 करोड़ लोगों को 6 हजार रुपये, 2 लाख 41 हजार करोड़ रुपये इसमें दिए। ये एमएसपी, एमएसपी बहुत चिल्लाते हैं। आपके माध्यम से जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, उनसे मैं एमएसपी के बारे में जरूर पूछना चाहता हूं कि आपने एमएसपी की कितनी खरीदी की थी और एमएसपी के रेट में कितनी बढ़ोत्तरी की थी? जरा हिसाब-किताब लेकर जनता के सामने जाइए। मगर नहीं जाएंगे, बैठे-बैठे बोलेंगे कि एमएसपी का क्या हुआ? मैं बताता हूं कि सत्य क्या है। मैं इस सदन के माध्यम से इस देश की जनता को और 14 करोड़ किसानों को कहना चाहता हूं कि आपके घर में सबसे ज्यादा एमएसपी और एमएसपी पर सबसे ज्यादा धान खरीदने का काम किसी सरकार ने किया है तो नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

मान्यवर, सभी सभासदों से मेरी विनती है कि आप ध्यान से सुनिए। धान की खरीदी 475 लाख मीट्रिक टन मनमोहन सिंह जी ने अपने अंतिम साल में की। मैं फिर से आंकड़ा बोलता हूं 475 लाख मीट्रिक टन। नरेन्द्र मोदी जी ने अंतिम खरीदी 896 लाख मीट्रिक टन की। इसमें 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लाभार्थी किसान पहले 76 लाख थे, अब 1 करोड़ 31 लाख लाभार्थी किसान हैं।

मान्यवर, मैं गेहूं की एमएसपी पर खरीदी की बात करूं तो इसके अंदर मनमोहन सिंह जी और इनकी यूपीए की सरकार 251 लाख मीट्रिक टन छोड़कर गए थे। अब नरेन्द्र मोदी जी ने 251 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 433 लाख मीट्रिक टन पहुंचाने का काम किया। पहले 20 लाख किसानों का गेहूं खरीदा जाता था, अब 43 लाख किसानों का गेहूं खरीदा जाता है। मान्यवर, मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दो गुनी करेंगे। हमारा माखौल उड़ाते थे, अभी भी उड़ाते हैं, शायद पांच साल बाद भी उड़ायेंगे।… (व्यवधान) अभी समझ नहीं बढ़ी है। हम कहते थे कि हम किसानों की आय दो गुनी करेंगे, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। मोदी जी ने निर्णय कर दिया कि किसान की लागत से 50 प्रतिशत कम से कम अधिक एमएसपी रखेंगे। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक किसान हितैषी निर्णय है।

(1750/NK/NKL)

मैं एक बार फिर से माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार, जिनको हम पर अविश्वास है, यूपीए सरकार धान की एमएसपी 1310 रुपये पर छोड़ कर गई थी, कम खरीदते थे, लेकिन रेट 1310 रुपये एमएसपी था। हमने ज्यादा खरीदा और उसके दाम को 1310 से बढ़ाकर 2040 रुपये कर दिया।

मान्यवर, वर्ष 2013-14 में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार गेहूं की 1400 रुपये एमएसपी छोड़ कर गई थी, आज वर्ष 2023-24 में 1400 रुपये से बढ़कर 2125 रुपये एमएसपी है। हमने गेहूं ज्यादा खरीदा और गेहूं के दाम भी ज्यादा दिए। ये न किसान हितैषी हैं, न गरीब हितैषी हैं, न पिछड़ा

हितैषी हैं। इनको अपने परिवार के अलावा किसी का ध्यान नहीं आता है। इसलिए मोदी जी ने आज 9 अगस्त को कहा है, परिवारवाद –

कई माननीय सदस्य : क्विट इंडिया।

श्री अमित शाह : भ्रष्टाचार –

कई माननीय सदस्य : क्विट इंडिया।

श्री अमित शाह : तुष्टीकरण -

कई माननीय सदस्य : क्विट इंडिया। … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अभी भी सत्यता स्वीकारो, नहीं तो जितनी संख्या है, उसके भी आधे रह जाओगे। मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति इस देश की जनता का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट कराना चाहता हूं। पीएफआई कई सालों से देश को तोड़ने, देश की जनसांख्यिकी बदलने, देश के अंदर आतंकवाद के बीज बोने का काम कर रही थी। एक ही दिन में 22 सितम्बर को 15 राज्यों में 90 से ज्यादा स्थानों पर रेड करके पीएफआई पर बैन लगाकर पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला।

मान्यवर, देश भर में हमने पीएफआई को बैन किया। दुनिया भर में भागे हुए गुनाहगारों को वापस लाये, एनआईए के नौ घनघोर आतंकवादियों को दुनिया भर से वापस लाए, छह राज्यों की पुलिस ने भी उनको वापस लाये। सचिन बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आरोपी था, उसको भी वापस लाया। तहव्वुर राणा का भी केस हम अंतिम सुनवाई तक पहुंचाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। मुंबई बम हमले के आरोपी राणा भारत के कानून के कठघरे में लाया जाएगा।

मान्यवर, विदेशों में भारतीय दूतावास लंदन, ओटावा और सैन फ्रांसिस्को पर जो हमले हुए, उन तीनों मामलों को हमने एनआईए को सौंपा है। यूएपीए को कठोर करने का बिल हम लेकर आए थे तो इस सदन में और राज्य सभा में दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि इसका दुरुपयोग होगा। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यूएपीए का उपयोग टेररिस्ट कृत्य करने वालों के खिलाफ होता है, हम में से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उस वक्त भी मैं नहीं समझ सकता था, परंतु जिन्होंने टेररिस्ट कृत्य नहीं किया है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। लगभग 54 व्यक्तियों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया और इसे इंटरनेशनली मान्यता दी। एक मामले में भी विवाद नहीं हुआ है, इसका कोई राजनीतिक दुरुपयोग नहीं हुआ है।

मान्यवर, अभी गोगोई जी नारकोटिक्स की बात करते थे। वह कहते है कि नारकोटिक्स का चलन बढ़ गया है। इनकी समझ में थोड़ा फर्क है, इसे मैं बाद में दुरुस्त करूंगा। वर्ष 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय के अधीन पहले श्री राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, अब मैं गृह मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। हमने नारकोटिक्स पर जीरो टॉलेरेंस की नीति अपनायी है।

(1755/SK/SPR)

वर्ष 2019 में एनकॉर्ड बनाया गया फिर इसे चार स्तरीय किया गया। एनकॉर्ड पोर्टल डेटा इंटीग्रेशन और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल बनाए गए। मादक पदार्थों की तस्करी की विस्तृत जांच के लिए जेसीसी, जिसमें ढेर सारे डिपार्टमेंट्स और सरकारें होती हैं, राज्यों में ANTF का गठन

किया गया। राज्यों में के9 पूल की स्थापना की गई और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1 लाख 65 हजार किलोग्राम नारकोटिक्स को जलाया गया। अब आजादी के अमृत महोत्सव के एक वर्ष में टोटल 10 लाख किलो तक पहुंच गया है।

महोदय, गोगोई जी ने जो कहा, अब मैं उसका जवाब दूंगा। आंकड़े किसी की शर्म नहीं रखते हैं, आंकड़े बेशर्म होते हैं। आंकड़े हमारे कामों से खड़े होते हैं और आंकड़ों को बाद में बदला भी नहीं जा सकता। वर्ष 2006 से यूपीए सरकार थी, जिसे हम पर थोड़ा अविश्वास है। वर्ष 2006 से वर्ष 2013 का समय उनका ही था, उसमें क्या हुआ? तब जब्त की गई ड्रग्स 1 लाख 52 हजार किलो थी। मैं फिर से सदन का और सदन के माध्यम से देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जब्त की गई ड्रग्स 1 लाख 52 हजार किलो थी और वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक 1 लाख 52 हजार किलो से बढ़कर 3 लाख 73 हजार किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई। गोगोई जी 181 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गांजा पकड़ लेना, भांग पकड़ लेना एक बात है, लेकिन महंगे, शरीर को ज्यादा नुकसान करने वाले और पैसे की दृष्टि से नुकसान करने वाले नारकोटिक्स पदार्थ कीमत से आइडेंटिफाई होते हैं। वर्ष 2006 से वर्ष 2013 में 768 करोड़ रुपये की ड्रग्स पकड़ी गई। मैं फिर से कहना चाहता हूं 768 करोड़ रुपये की पकड़ी गई ड्रग्स से यूपीए सरकार संतुष्ट थी, उन्होंने इसे अपनी रिपोर्ट कार्ड में भी लिखा है। वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक के कालखंड में 18,000 करोड़ रुपये की ड्रग्स को नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पकड़ा। ये हम पर सवाल उठा रहे हैं? मैं इसलिए कहता हूं कि आपको भरोसा नहीं है, लेकिन देश की जनता को विश्वास है। 1257 कुल मामले दर्ज किए गए थे, अब 3700 हो गए हैं।

महोदय, इन्होंने कल यहां ज्ञान बांटा कि पहले 1257 केस थे, अब बढ़ गए हैं, 3700 हो गए हैं। नारकोटिक्स के खिलाफ केस अच्छे हैं या इसे बुरा माना जाएगा? हम पकड़ते हैं, आप पकड़ते ही नहीं थे, चलने देते थे। हमने पकड़ना शुरू किया इसलिए 1257 से बढ़कर 3700 केस हो गए। आपने 1363 गिरफ्तारियां की थीं, हमने 5400 गिरफ्तारियां की हैं। टोल फ्री नंबर भी दिया।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो गृह मंत्री जी के भाषण की समाप्ति तक सभा की कार्यवाही बढ़ा दी जाए?

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

श्री अमित शाह: मान्यवर, तीन करोड़ युवा और दो करोड़ महिलाओं को नशामुक्त अभियान में, समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अलग-अलग विभाग इकट्ठा होकर साथ जुड़े हैं, इससे लगभग साढ़े नौ करोड़ लोगों तक नशामुक्त भारत अभियान की शपथ और टोल फ्री नंबर पर मिस काल करने की पहुंच बढ़ी है। यह हमारे प्रयासों को दर्शाता है। मैं इसलिए कहता हूं भले ही आपको अविश्वास हो, देश की जनता को विश्वास है।

महोदय, इस देश की आंतरिक सलामति की दृष्टि से तीन बड़े हॉटस्पॉट माने जाते हैं – कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र और नॉर्थ-ईस्ट। कांग्रेस की सरकार सालों तक रही और यह चलता रहा। आज मैं स्पष्ट रूप से इस सदन में कहना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या का कारण वोट बैंक की राजनीति, समस्या से आंख मूंदना और सरकारों का ढुलमुल रवैया था। कश्मीर में वर्ष 2014 से हमारी नीतियों में परिवर्तन आया। … (व्यवधान)

(1800/KDS/MMN)

मान्यवर, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से 2019 तक राजनाथ सिंह जी और मैं गृह मंत्री रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्ण तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने का हमने काम किया है। कश्मीर में 40 हजार लोग मारे गए। … (व्यवधान) मेरा एक निवेदन है। मैं जानता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी मेरे निवेदन का विरोध नहीं करेंगे। अधीर जी को कांग्रेस पार्टी ने टाइम नहीं दिया है। आप इन्हें हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दीजिए। वह कृपया बीच में न बोलें। वह बीच में खड़े हो जाते हैं। उनको बोलने दीजिए। वह इसलिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने उनको टाइम ही नहीं दिया है।

माननीय अध्यक्ष : कश्मीर तो सारी संसदीय समितियां गई हैं। कश्मीर सभी ने देखा है न?

माननीय गृह मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अधीर बाबू, हमारा 10 मिनट आपको दे दिया जाएगा। अभी बैठिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हैं? कृपया बैठिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगान्तरकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जवाहर लाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 को 5 और 6 अगस्त, 2019 को इस महान सदन ने समाप्त कर दिया। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से दो झंडे चले गए, दो संविधान खत्म हो गए और सम्पूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है।

मान्यवर, इनके ही प्रेरित एनजीओ की मीटिंग अभी हुई, जिसकी रिपोर्ट मैंने देखी। रिपोर्ट कहती है कि हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम न हुर्रियत से चर्चा करेंगे, न जमीयत से चर्चा करेंगे, न पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर हम चर्चा करेंगे, तो घाटी के युवाओं से करेंगे। वे हमारे अपने हैं। हुर्रियत पर हमने पाबंदी लगा दी। जमीयत-ए-इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी लगा दी। आतंकवादियों के समर्थकों को चुन-चुनकर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है, वहीं दफन किया जाता है।

मान्यवर, लखनपुर टोल टैक्स, जो हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को शूल की तरह हृदय में चुभता था, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अरेस्ट किया गया था, उस लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया गया और 2 दरबार व्यवस्था हटाकर 200 करोड़ रुपये बचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। वहां दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को आरक्षण नहीं था। यह सारा आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वहां पर महिला आयोग नहीं था, बाल आयोग नहीं था, दलित आयोग भी नहीं था। ये सारे आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। वहां सफाई कर्मचारी सात-सात पीढ़ी से मुगलों के जमाने से रह रहे थे, मगर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं

मिलता था। पाकिस्तान से शरण में आए हुए, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए हिंदू, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोगों को डोमिसाइल नहीं मिलता था। इन सबको डोमिसाइल देने का काम इस देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया।

(1805/MK/VR)

मान्यवर, ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और डेमोक्रेटिक वैल्युज को मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? कश्मीर पर शासन तीन परिवारों ने किया। महबूबा मुफ्ती, फारूख साहब और गांधी परिवार, इन तीन परिवारों ने कुल शासन किया। लेकिन, वे पंचायत चुनाव नहीं करा पाए। नरेन्द्र मोदी जी ने, नवम्बर-दिसम्बर, 2018 में, उस समय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को सम्पन्न कराया। 4,483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35000 पंच चुने गए। … (व्यवधान) आज 40,000 लोग डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जम्हूरियत का फायदा उठा रहे हैं।

स्टोन पेल्टिंग, मैं आप सबसे पूछता हूं कि क्या पथराव की घटना अब टीवी पर दिखाई पड़ती है? कहीं नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि पथराव बंद हो गया है। … (व्यवधान)

मान्यवर, जम्मू-कश्मीर पुलिस 1990 के दशक के बाद पहली बार आज एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है। हमने जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिन्दू संपत्ति वापस देने के लिए कानून लेकर आए और टूरिज्म का भी विकास हुआ है। अधीर रंजन जी, सुन लीजिए आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, वर्ष 2022 में 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट्स जम्मू-कश्मीर गए। … (व्यवधान) बैठ जाइए।

मान्यवर, 33 सालों के बाद थिएटर चालू हुआ है नरेन्द्र मोदी जी के शासन में, 33 सालों के बाद नाइट शो चालू हुआ नरेन्द्र मोदी जी के शासन में, 33 सालों के बाद शिकाराओं की स्पर्द्धा चालू हुई है, वह बंद कर दी गई थी, वह भी चालू हुई नरेन्द्र मोदी जी के शासन में। दानिश अली जी सुन लीजिए, 33 सालों से मुहर्रम बंद था, पहली बार नरेन्द्र मोदी सरकार में मुहर्रम चालू हुआ है।

मान्यवर, हम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए होम स्टे नीति लेकर आए, हिम निर्माण की नीति लेकर आए, हाउस बोट की नीति लेकर आए और इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए और आज उससे रोजगारी बढ़ रही है। 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मूलभूत ढांचे का विकास हो रहा है। 5 हजार मेगावाट, 3 हजार मेगावाट, 624 मेगावाट और 540 मेगावाट की जल विद्युत की योजनाएं वहां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ 850 मेगावाट और 1000 मेगावाट की दो जल विद्युत योजनाएं शुरू हुई हैं। सिंचाई योजना, शाहपुर कंडी बांध योजना, जो पचास साल पहले शुरू हुई थी, वह मोदी जी के शासन में चालू हुई और मोदी जी के शासन में पूरी होगी। 62 करोड़ रुपये की मुख्य रावी नहर का 90 परसेंट काम पूरा कर दिया गया है। झेलम-तवी बाढ़ वसूली परियोजना संगठन द्वारा 250 मिलियन यूएस डॉलर विश्व बैंक से लाकर गरीबों के पुनर्वसन का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है और उधमपुर-बारामूला रेल लिंक भी प्रगति पर है।

मान्यवर, अब मैं सुरक्षा का आंकड़ा बताना चाहता हूं। मैं यहां तुलनात्मक आंकड़े इसलिए रख रहा हूं, क्योंकि अविश्वास का जो प्रस्ताव है, इससे देश की जनता में कहीं भ्रांति न खड़ी हो जाए।

यह बहुत जरूरी है। इसलिए, मैं 9-9 साल के दो टूकड़े लेकर आया हूं। ये कौन से 9 साल के टूकड़े हैं? एक परिवारवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर चुनी गई यूपीए की सरकार के 9 साल हैं और दूसरा देशभक्ति और समर्पण के आधार पर चुनी गई नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। 9 साल की दोनों की तुलनात्मक अध्ययन में आतंकवाद की कुल घटनाओं में 68 प्रतिशत की कटौती हो चुकी है। सिक्युरिटी और नागरिक, दोनों को मिलाकर कुल मौतों में 72 प्रतिशत की कमी हुई है। सिर्फ नागरिकों की मौतों में 82 प्रतिशत की कमी हुई है।

मान्यवर, सिक्युरिटी फोर्स की मौतों में 56 प्रतिशत कमी हुई है और अब स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है।

(1810/SJN/SAN)

मान्यवर, इसी सदन में कहते थे कि अगर जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाई, तो खून की नदियां बह जाएंगी। किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। यह नरेन्द्र मोदी सरकार है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको भले ही अविश्वास हो, जनता को तो विश्वास है।

मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था, जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से 10 साल की यूपीए सरकार के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। उसके हिंसा के आंकड़े देखिए। वर्ष 2005 से 2014 और वर्ष 2014 से 2022 के आंकड़े हैं। हिंसा - कुल 14,000 घटनाएं हुई थीं। अब 6,900 हुई हैं, 52 प्रतिशत की कमी हुई। मृत्यु - 5,790 थीं, अब 1,811 हुई हैं, 69 प्रतिशत की कमी हुई। हिंसाग्रस्त जिले 96 थे, उसके बाद 22 नए जिले बने। अब 118 जिले हैं, जो घटकर 45 जिले बचे हैं। नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद सिमटकर रह गया है। हिंसाग्रस्त पुलिस स्टेशंस 465 थे। 80 नए पुलिस स्टेशंस बनने के बाद, यानी लगभग 550 हुए। उनमें से अब 176 पुलिस स्टेशंस बचे हैं यानी 62 प्रतिशत की कमी हुई है। हमने वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसी है। वर्ष 2014 से सातत्यपूर्ण तरीके से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति नरेन्द्र मोदी सरकार लाई है।

मान्यवर, जब राजनाथ जी गृह मंत्री थी, तभी एक योजना बन गई थी, विकास की योजना। वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र का विकास गृह मंत्रालय के तहत आता है। हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाना, रोड पहुंचाना, स्कूल पहुंचाना, सस्ते अनाज की दुकान पहुंचाना, दवाइयों की दुकान पहुंचाना, स्किल डेवलेपमेंट के प्रोग्राम्स पहुंचाना, ये काम होते गए। पहले विकास पहुंचा और फिर 195 नए सुरक्षा वैक्यूम भरने के लिए सीएपीएफ के कैंप्स खोलने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

मान्यवर, एनआईए और ईडी को जोड़ा गया। इनके फाइनेंस की कमर तोड़ी गई। वामपंथी उग्रवाद और उसके केसों की जांच के लिए एनआईए में एक अलग वर्टिकल बनाया गया। एक बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया। सारे वामपंथी उग्रवादी एफआईआर्स की कंप्यूटराजेशन करके आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस से इसका एनॉलिसिस किया जा रहा है और बस्तरियां बटालियन भी बनाई गई है।

मान्यवर, आज मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं कि वामपंथी उग्रवाद आया, तब वे काठमांडू से तिरुपति का स्वप्न देखते थे, लेकिन आज तीन जिलों में सिमटकर रह गए हैं। उनका दायरा क्या था? झारखंड, बिहार, ओडिशा, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और

छत्तीसगढ़। आज क्या बच गया है? झारखंड मुक्त, बिहार मुक्त, ओडिशा मुक्त, एमपी मुक्त, महाराष्ट्र मुक्त, आंध्र प्रदेश मुक्त, तेलंगाना मुक्त, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के तीन जिले बचे हैं।

मान्यवर, यह अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है। जनता फिर से मोदी जी को चुनने वाली है और अगले टर्म में ये तीन जिले भी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। वामपंथी उग्रवाद पर जबरदस्त नकेल कसने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको भले ही अविश्वास हो, देश की जनता को विश्वास है।

मान्यवर, अब मैं पूर्वोत्तर की बात करना चाहता हूं। नॉर्थ-ईस्ट भी तीसरा हॉटस्पॉट माना जाता था। मैं उसी कालखंड की घटनाओं के आंकड़े लेकर आया हूं, ताकि इन लोगों को ऐसा कुछ न लगे। हिंसक घटनाएं 10,000 होती थीं। अब उसकी जगह 3,238 हुई हैं। 68 प्रतिशत की कमी है। हताहत सुरक्षा बल - 397, अब 128 हैं, 68 प्रतिशत की कमी हुई। मृत्यु नागरिक – 2,298 थीं, अब 420 हैं, 82 प्रतिशत की कमी हुई है। हर हेड में नॉर्थ-ईस्ट के अंदर हिंसा कम हुई है।

मान्यवर, इसके पहले किसकी सरकारें थीं? 10 साल तक नॉर्थ-ईस्ट के सभी राज्यों और यहां पर यूपीए की सरकार थी। मगर कुछ नहीं होता था। निवेदन करना, पॉलिटिक्स करना और अंदर ही अंदर झगड़ा लगाना, यही काम था। नरेन्द्र मोदी जी ने नॉर्थ-ईस्ट को मन से भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। हमारे कई डेवलेपमेंट के पंडित कहते हैं कि मोदी जी ने नॉर्थ-ईस्ट को…(व्यवधान) मैं यह भी बताता हूं।…(व्यवधान)

(1815/SPS/SNT)

मान्यवर, कई विकास के पंडित कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, दूरी कम हो गई, कई विकास के पंडित कहते हैं कि आठों राज्यों में रेल पहुंच गई, दूरी कम हो गई, कई विकास के पंडित कहते हैं कि इतने हजार किलोमीटर रोड बन गया, दूरी कम हो गई। अरे भाई, दूरी रोड, रेलवे और विमान से कम नहीं होती है, दूरी दिल से कम होती है। मोदी जी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है और नॉर्थ ईस्ट को मेनस्ट्रीम में लाने का काम किया है। आज मैं कहता हूं कि मोदी जी को 9 साल हुए हैं, लेकिन इस देश में 15 साल और 18 साल प्रधान मंत्री रहे हुए लोग हैं, जिन पर इनको नाज़ है और हम पर अविश्वास है, मगर वे कभी 50 बार नहीं गए, मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं। यह बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसक हमारे मन में है। उत्तर प्रदेश से बड़ा भू भाग किस तरह से छोड़ दिया, आगजनी, टेरेरिस्ट, नस्लीय हिंसाएं थीं और आप हमारा हिसाब मांगते हो। आप बोलो मणिपुर पर, मैं बताता हूं और मैं मणिपुर पर फिर बोलूंगा।

मान्यवर, इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया है, न विकास किया है, न कुछ किया है। मैं आपको बताता हूं कि अटल जी नेसैक (एनई-सैक) की स्थापना करके गए, इसरो जैसी एक संस्था बनाई, पदेन मैं इसका अध्यक्ष होता हूं। मोदी जी ने नेसैक (एनई-सैक) को एक्टिवेट किया और पूरे नॉर्थ ईस्ट की स्टडी की है। ब्रह्मपुत्र के पूर्व को बड़े-बड़े मैदानों में तालाब बनाकर, इसके अंदर डायवर्ट करके सिंचाई भी होगी, बाढ़ का रास्ता भी होगा और पर्यटन भी होगा। आने वाले वर्षों में बाढ़ मुक्त नॉर्थ ईस्ट होगा। हम नॉर्थ ईस्ट को बाढ़ मुक्त बनाकर रहेंगे, क्योंकि आपका अविश्वास

प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता हमें चुनने वाली है। आपको भले ही अविश्वास है, मगर जनता को तो विश्वास है।

मान्यवर, मैं जब यह कहता हूं, तो हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति ऐसे ही भावनाओं से नहीं की है। यह कागजी शांति नहीं है। इसके पीछे रणनीति है, इसके पीछे कड़ी मेहनत है और इसके पीछे लगन भी लगी है। वर्ष 2014 में अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल का समाधान किया, उसमें लगभग 674 लोगों का आत्म-समर्पन हुआ। अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल की हिंसा में 224 लोग मारे गए। एनएलएफटी के साथ वर्ष 2019 में समाधान हुआ, 88 लोगों ने सरेंडर किया और इसमें 144 लोग मारे गए थे। वर्ष 2020 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ समाधान हुआ। एनएलएफटी के साथ वर्ष 2019 में हुआ और वर्ष 2020 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ हुआ। इसमें 1,630 लोगों ने सरेंडर किया तथा 4,362 लोग बोडोलैंड की हिंसा में मारे गए थे और इन्होंने हथियार डाले। कार्बी समूह में 197 लोग मारे गए थे और 1,000 उग्रवादियों ने आत्म-समर्पन किया। असम आदिवासी सशस्त्र समूह में 1,182 लोगों ने सरेंडर किया और 329 लोग मारे गए थे। दिमासा नेशनल लिबरल आर्मी में 168 लोगों ने सरेंडर किया, जिसमें 25 लोग मारे गए थे।

मान्यवर, कुल 8,000 सशस्त्र उग्रवादियों ने नरेन्द्र मोदी जी के 9 साल में सरेंडर किया है। हमारे सम्माननीय सदस्य गौरव जी कह रहे थे कि हिंसा से त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है, आग की लपटें हैं। मणिपुर में आग की लपटें क्यों हुई, मैं उस बात पर आता हूं, परंतु आपके समय में तो आठों राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे और हिंसा में 6 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो अब सरेंडर होकर मेनस्ट्रीम के अंदर आए। मैं इसलिए आपको यह कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर के अंदर हमने हिंसक घटनाओं में 68 प्रतिशत, सुरक्षा बलों की हत्याओं में 68 प्रतिशत और हताहत नागरिक में 82 प्रतिशत की कमी की है। जो मैंने यह सब कहा है, वह समझौते किए हैं। असम के अंदर 70 परसेंट से अधिक अफस्पा का क्षेत्र मुक्त, मणिपुर के अंदर 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन हटाए गए, अरुणाचल में केवल एक जिला और तीन पुलिस स्टेशन बच गए, नागालैंड में 8 जिलों के 18 पुलिस स्टेशन हटाए गए और त्रिपुरा तथा मेघालय में पूर्णत: अफस्पा हटा दिया गया है।

(1820/RPS/KKD)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहता हूं कि जो बचा-खुचा काम बाकी है, वह भी हम ही पूरा करेंगे, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि आपको भले अविश्वास हो, लेकिन जनता को मोदी जी पर विश्वास है। … (व्यवधान)

मान्यवर, अब मैं मणिपुर की बात करना चाहता हूं।… (व्यवधान) अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूं। मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, वे क्यों हुई हैं, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परन्तु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। हम भी सहमत नहीं हैं। उनसे ज्यादा दुख हमें है, परन्तु यह परिस्थितिजन्य है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई। इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। जो घटना हुई है, वह

शर्मनाक है, परन्तु उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। ... (व्यवधान) मान्यवर, मैं बताता हूं।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हम लोगों ने राजनीति नहीं की, हम लोग पूछना चाहते थे। यह गलती आपकी है और आप सारे इल्ज़ाम हम पर थोपना चाहते हैं। ... (व्यवधान) गलती आपकी है, हम तो सवाल पूछने वाले हैं और आप हमारे ऊपर दोबारा इल्ज़ाम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत तो आप कर रहे हैं, हम कहां सियासत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गए नहीं।...(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, एक भ्रान्ति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था, मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय-मर्यादा मत रखिए। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): इसमें प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था।... (व्यवधान) हमारी मांग आप जानते हैं। ... (व्यवधान) हमारी मांग आप जानते थे।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार हूं, मगर वे चर्चा नहीं चाहते थे, उनको विरोध करना था। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वे मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते कि प्रधानमंत्री जी चर्चा करें। प्रधानमंत्री जी उस पर विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो, मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दें, तो किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था आप चाहते हैं? ... (व्यवधान) क्या आप सोचते हो कि शोर-शराबा करके आप मुझे चुप कर दोगे? ... (व्यवधान) आप चुप नहीं करा सकते हो, 130 करोड़ जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है। हमें सुनना पड़ेगा, आप चुप नहीं कर सकते हो। ... (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी संवेदना के साथ, आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि मणिपुर की हालिया हिंसा क्यों हुई है, क्या चल रहा है और सरकार ने क्या उपाय किए हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं।

मान्यवर, पास्ट में मणिपुर में क्या हुआ, मैं यह भी बताऊंगा। जब मैं यह बताऊंगा, तब ये कहेंगे कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो। नहीं जी, नहीं। मैं संवेदनशील आदमी हूं, मान्यवर। मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब-किताब के लिए नहीं सुना रहा हूं। इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि आपके समय में भी हुआ था, हमारे समय में भी हुआ, होता है। यह 'होता है' का एप्रोच हमारा नहीं है, यूपीए का है। हमारा एप्रोच 'होता है' का नहीं है। हम टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं पुरानी हिंसाओं को इसलिए बताना चाहता हूं कि मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के स्वभाव को जनता को जानना पड़ेगा। नस्लीय हिंसा मणिपुर में जब-जब होती है, तब किस प्रकार से होती है, वह भी जानना पड़ेगा। इसलिए मैं पुरानी हिंसाओं को भी रखूंगा।

(1825/YSH/AK)

आपके मन में यह भ्रांति न हो, सवाल न आए कि पुराना क्यों बता रहे हैं। करीब-करीब साढ़े छ: सालों से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की

सरकार बनी, तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं लगा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कह रहा हूँ। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छ: साल पूरे हो चुके हैं। इन छ: सालों में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं लगा था। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर एक भी दिन ब्लॉक्ड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग-लगभग समाप्त हो गई थी। इन छ: सालों का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का यह इतिहास रहा है।

वर्ष 2021 में हमारे देश के पड़ोसी देश म्यांमार में सत्ता का परिवर्तन हुआ और वहां पर मिलिट्री का शासन आ गया। वहां पर डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई। वहां पर एक पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट है। उसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू किया। जब पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू किया तो वहां की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई से कार्रवाई करना शुरू कर दिया, इन पर दबिश करना शुरू कर दिया। चूँकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है। वहां पर फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं आजाद हुए, तब से नहीं है। वहां पर फेंसिंग नहीं है तो बहुत बड़ी संख्या में मिजोरम और मणिपुर में कुकी भाइयों का शरणार्थी के रूप में आना शुरू हो गया।

मान्यवर, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनका झगड़ा म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वे यहां पर आए। हजारों की संख्या में कुकी आदिवासी भाई यहां पर आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहां पर बसने लगे, जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई कि हमारी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। हमने उसे देखा और उसी वक्त हमने गृह मंत्रालय में वर्ष 2022 में निर्णय किया कि अब हम इस बॉर्डर को खुला नहीं रख सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर की फेंसिंग पूरी कर दी है। 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने वर्ष 2014 तक कभी भी फेंसिंग नहीं की। हमने दूरंदेशी से वर्ष 2023 में दंगे हुए, लेकिन हमने वर्ष 2021 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर की ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है। 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी है, जिससे घुसपैठ को रोका जा सके। फिर एक अंदेशा खड़ा होने लगा, क्योंकि वहां पर जनसांख्यिकी बहुत निर्णायक होती है।… (व्यवधान) वहां पर घाटी में मैतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं तो जनसांख्यिकी के बदलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हम अल्पमत में आ जाएंगे। इसके लिए हमने लगभग-लगभग जनवरी महीने से वहां पर जितने भी शरणार्थी आए थे, उनको परिचय पत्र देने की शुरूआत की। उनका थम्ब इंप्रेशन लिया, आई इंप्रेशन लिया और थम्ब इंप्रेशन और आई इंप्रेशन को वोटर लिस्ट तथा आधार कार्ड की नेगेटिव लिस्ट में लाने का काम किया।

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आँख मूंदकर सो रहा था। वर्ष 2023 में दंगा हुआ, वर्ष 2021 में हमने फैंसिंग चालू की और वर्ष 2023 की शुरूआत में हमने थम्ब इंप्रेशन और आई इंप्रेशन लेने की शुरूआत की और उसको भारत के वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। फिर भी जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना मैतई लोगों में फैलती गई।

मान्यवर, वहां पर नेपाल की तरह पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब यह मत कहना कि हमने क्यों नहीं किया। यह सन् 1968 से किया हुआ है। सन् 1968 से एक समझौता है कि भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में बॉर्डर के 40 किलोमीटर एरिया में जो अंदर आएगा या यहां से 40 किलोमीटर तक वहां जाएगा, उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए। यह समझौता है। किसी को रोकना भी असंभव है और इतनी हजारों किलोमीटर की बॉर्डर में फेंसिंग भी नहीं हो रखी थी।

(1830/RAJ/UB)

वहां संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा भी बढ़ती गई। इतने में 29 अप्रैल को एक अफवाह फैल गई कि जो शरणार्थियों की कुछ बसावटें थीं, वे गांव घोषित कर दिए गए। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ। हमने वहां अनेरस्ट में माइक वाली जीपें चलाईं। यह बताया गया कि कोई गांव घोषित नहीं हुआ है, मगर, अफवाहें जब फैलती हैं तो वह फैलती है और अविश्वास का वातावरण बनता है।...(व्यवधान) जो वहां बसावटें थीं, जंगल गांव घोषित किए गए, उनको लगा कि अब ये परमानैंट यहीं बस जाएंगे, तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद आग में तेल डालने का काम माननीय हाई कोर्ट, मणिपुर के आए हुए एक फैसले ने किया। जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाकर, न भारत सरकार के ट्राइबल आयोग से शपथ-पत्र लिया, न भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट से लिया, न भारत सरकार के गृह मंत्रालय से लिया और न ही मणिपुर सरकार से लिया एवं अचानक ही कह दिया, 19 मई के पहले मैतेई जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया जाए। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ। ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मैतेई ट्राइबल बन जाएंगे। नौकरियों में स्पर्द्धा का भाव होता है और यह स्वाभाविक है। कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर दे दिया गया। वहां नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ और 3 तारीख को एक क्लैश हो गया और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए, जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अब इस परिस्थिति में, वह क्यों नहीं गया, यह क्यों नहीं गया, आप इस तरह से तुलना मत कीजिए।

मान्यवर, ये परिस्थितिजन्य दंगे हैं। मैं आगे भी कहना चाहता हूं। इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है। वहां मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलाई आ गई है। नारकोटिक्स की भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है। इस व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिनचिंग चीज थी, वह कोर्ट का जजमेंट था। उसकी अंतिम तारीख 19 मई थी। इसके विरोध में एक जुलूस निकला। जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई और देखते-देखते घाटी में और पहाड़ पर भी दोनों जगहों पर एक दूसरे पर हिंसा करना और हमला करना शुरू हो गया।

मान्यवर, अब दो सवाल हैं कि हिंसा शुरू होने के बाद क्या किया? मैं उस पर बाद में जाऊंगा। मैं इतनी ही शांति से बताऊंगा। मैं किसी भी चीज से भागना नहीं चाहता हूं, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है। मैं किसी भी चीज से भागना नहीं चाहता हूं। मगर, मणिपुर की नस्लीय हिंसा के इतिहास को समझना पड़ेगा। वर्ष 1993 में श्री पी. वी नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री थे। राजकुमार दोरेन्द्र सिंह कांग्रेस के नेता माननीय मुख्यमंत्री थे और नागा-कुकी संघर्ष हुआ। नागा-कुकी भी नस्लीय हिंसा थी।

उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45 हजार लोग शरणार्थी थे और डेढ़ साल तक यह हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी क्यों नहीं बोले। भाई, 750 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45 हजार लोग शरणार्थी बने, क्या आपको मालूम है कि जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है कि जवाब किसने दिया – एमओएस राजेश पायलेट और ये मुझे बोलने नहीं देते हैं।

मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, तो क्या भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की? ट्राइबल मिनिस्टर गया, ना जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए, ना जी, होम मिनिस्टर का question does not arise, ना जी और ये हम से पूछते हैं कि प्रधान मंत्री वहां क्यों नहीं गए? अरे भाई! आप नस्लीय हिंसा का इतिहास देखिए। मैं आपको पूरा बताता हूं। मुझे जल्दबाजी नहीं है। यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे इतिहास पूरा बताना है। संसद के अंदर विपक्ष बोलते-बोलते थक गया। गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, एमाओएस ने जवाब दिया और यह प्रधान मंत्री के जवाब देने की मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड किए हुए हैं।

मान्यवर, वर्ष 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ। मैतेई-पंगल संघर्ष हुआ। उसमें 100 लोग मारे गए। वह भी एक साल तक चला और राज्य सभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन लोक सभा में नहीं और ये कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री जवाब दें। क्या किसी ने मुलाकात की, किसी ने मुलाकात नहीं की।

(1835/KN/SRG)

न गृह मंत्री ने मुलाकात की और न एमओएस ने मुलाकात की। किसी ने मुलाकात नहीं की। फिर इन्द्र कुमार गुजराल जी आए। वर्ष 1997-98 में कुकी-पाइते संघर्ष हुआ। उसमें 350 लोग मारे गए। एक साल तक संघर्ष चला। यह भी नस्लीय हिंसा है। मैं टेरेरिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा हूं। मैं नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं। यह एक साल तक चला। उस पर चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुए, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए। ये कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी जवाब दें।

मान्यवर, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। यह मेरी ड्यूटी है। मैं देश के प्रति जवाबदेह हूं, संसद के प्रति जवाबदेह हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाबदेह हूं। मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे बोलने ही नहीं देते हैं। यह किस प्रकार का लोकतंत्र है?

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, अभी तो बोल रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : दादा, अब तो बोलने ही दोगे। मैं पहले की बात कर रहा हूं। हमारे गोगोई जी कहते हैं कि मौन तोड़ने के लिए यह लाया गया है। अरे भाई! मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए। हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते हैं, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छिपाना है। हमारा इसमें कोई आदमी इनवॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता हूं। गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम हैं... (व्यवधान) अगर आपको नाम सुनने हैं तो मैं बता दूं। आप खड़े होकर कह दो कि नाम बता दो तो मैं बता देता हूं। अगर नाम सुनने हैं तो... (व्यवधान)

मान्यवर, बाद में वर्ष 2004 में मनमोहन सिंह जी थे। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर इबोबी सिंह जी थे। वर्दी वालों से लगभग 1700 लोगों के एकतरफा एनकाउंटर हुए। ऐसा वहां मानते हैं, लेकिन मैं

नहीं मानता हूं। मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं। वहां लोग मानते हैं कि यह वर्दी से की हुई नस्लीय हिंसा है। उसमें लगभग 1700 लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और ढेर सारी एसआईटीज़ बनी थीं। मगर किसने जवाब दिया, किसी ने नहीं। एक चर्चा नहीं हुई, न एमओएस ने जवाब दिया, न मिनिस्टर ने जवाब दिया। आप मुझे बताइये। चिदम्बरम साहब, मुझसे राज्य सभा में हिसाब मांगते थे और मुझे बोलने नहीं देते थे। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं कि यह परिस्थितिजन्य नस्लीय हिंसा है। इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।

मान्यवर, 3-4-5 तारीख को, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि, देश के प्रधान मंत्री जी ने रात को 4 बजे मुझे फोन किया है और दूसरे दिन साढ़े 6 बजे फोन करके मुझे उठाया भी है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे हैं। मान्यवर, लगातार 3 दिन तक हमने यहां से काम करने का काम किया है। हमने 16 वीडियो कांफ्रेंसेज़ की हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के 36 हजार लोग वहां पहुंचाये। वायु सेना के विमानों का उपयोग किया। चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया। चीफ सेक्रेटरी को भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी को भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर को भारत सरकार ने भेजा। 3 तारीख को हिंसा हुई थी और 4 तारीख को लगभग समाप्त हो गई थी। ये कहते हैं कि 356 क्यों नहीं लगाई गई? 356 तब लगती है, जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करें। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के द्वारा भेजे गए चीफ सेक्रेटरी को… (व्यवधान) मैं यही कह रहा हूं कि अगर समझ न हो तो समझ में नहीं आयेगा। सीएम तब बदलना पड़ता है जब सीएम कोऑपरेट न करें। ये सीएम कोऑपरेट कर रहे हैं। डीजीपी, सुरक्षा सलाहकर, हमने इन सब को बदला है।… (व्यवधान) गौरव भाई, आप बैठ जाओ। आप खुफिया के बारे में इतनी चिंता करो कि मैं असम पर न जाऊं।

मान्यवर, यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेज लगाए जाते थे। एक साल में 30 दिन से 139 दिनों तक ब्लोकेज रहा और पाँच साल तक ब्लोकेज लगे। उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये लीटर तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में काम पूरा करके रेलवे को वहां पहुंचाया है और अबाधित रूप से आज वहां सप्लाई चालू है तथा दामों को बढ़ने नहीं दिया।

(1840/VB/PS)

वह भी इतनी कठिन परिस्थितियों में, जब कुकी एरिया में मैतेई ड्राइवर नहीं जा सकते थे और मैतेई एरिया में कुकी ड्राइवर नहीं जा सकते थे। ऐसी परिस्थिति में, हम असम से ट्रक भी लाये, ड्राइवर भी लाये, सेना को भी लगाया और हमने दामों को भी कंट्रोल करने का काम किया है।

मान्यवर, मैं हिंसा के आँकड़े भी देना चाहता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप राजनीति कर रहे हैं, मैं यह लॉजिक के साथ कह रहा हूँ। मान्यवर, अब तक 156 लोग मारे गये हैं। इसमें छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, यह सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। 156 लोग मारे गये हैं। इसकी एनालिसिस क्या है? मई महीने में 107 लोग मारे गए। आज हम अगस्त में हैं। जून में 30 लोग मारे गये, जुलाई में 15 लोग मारे गये और अगस्त में अब तक 4 लोग मारे गये हैं। मई में जो 107 लोग मारे गये, उनमें से 59 लोग 3, 4 और 5 तारीख को

पहले तीन दिन में ही मारे गए थे। मान्यवर, मैं इसके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हिंसा धीरे-धीरे कम हो रही है। इसलिए हम हिंसा की आग में तेल डालने का काम न करें। हम तेल न डालें।... (व्यवधान) उसमें तेल कैसे डाला जाता है, वह मैं बताता हूँ।

श्री राहुल गांधी जी यहाँ से वहाँ मुलाकात करने गये। मैं इसका स्वागत करता हूँ। उनकी संवेदना है, मणिपुर की चिंता है, इसलिए वे गये। एयरपोर्ट पर उतरे। उन्होंने कहा, हमें चुड़ाचाँद पुर जाना है। ठीक है। अगले दिन जाने वाले थे, लेकिन पहले दिन ही कहा। कोई बात नहीं, आप जाइए, जरूर जाइए। हमने कहा, हेलिकॉप्टर से चले जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं रोड से जाऊँगा, पुलिस हमें न रोके। फिर तीन घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर, यह नाटक देश को दिखाया। फिर दूसरे दिन चार बजे वे हेलिकॉप्टर से चले गये। अगर हेलिकॉप्टर से चले जाते तो हमें क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी। परंतु इस प्रकार का काम करने के लिए वहाँ जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहाँ जाते हैं, तो को-ऑपरेट करिए। आपको चुड़ाचाँदपुर जाने से कोई नहीं रोक रहा है। हम हेलिकॉप्टर से उनको भेज रहे हैं, लेकिन आप जाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं नहीं, मैं बाई रोड ही जाऊँगा। बाई रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गये, दूसरे दिन भी न जाते। वे दूसरे दिन भी गये। पहले दिन उनको सत्याग्रह दिखाना था। इस तरह की पॉलिटिक्स इस तरह की विषम परिस्थितियों में मत करिए।... (व्यवधान) आप क्या मानते हैं? ... (व्यवधान) आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे सरकार वहाँ की हो या यहाँ की हो, क्या जनता इसे नहीं जानती है? जनता इन सारी बातों को जानती है और पहचानती भी है, इसलिए मैं कह रहा था। अभी अधीर रंजन जी चले गए हैं, ... (व्यवधान) अगर वे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ कि वे पॉलिटिक्स कर रहे थे।... (व्यवधान)

मान्यवर, हमने लगभग 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है। हर केस की एफआईआर, लगभग 1106 एफआईआर रजिस्टर कर दी गई हैं।

अंत में, जो शर्मनाक विडियो आया, मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। यह विडियो 4 मई के दिन हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में है। दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है। इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। इसका समर्थन न ही यह सदन कर सकता है, न ही कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, न यहाँ की, न वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा-सा सवाल है, जो मेरे मन में तो नहीं आया। मीडिया के कुछ मित्र, जो ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने यह डाल दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि अमित भाई! 4 मई का विडियो, संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास विडियो था, तो उसे डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यदि किसी के पास विडियो था, तो उसे पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या उसको सार्वजनिक करना चाहिए था? उस महिला के सम्मान के बारे में तो सोचो।... (व्यवधान) इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था, वहाँ इतने हुड़दंग में।... (व्यवधान) एक मिनट, वह इंटेलिजेंस के पास नहीं आया।... (व्यवधान) मगर क्या वह आपको देना चाहिए था या नहीं? ... (व्यवधान) आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था।... (व्यवधान) हाँ, दादा का काम टीवी में बताने का है।... (व्यवधान)

मान्यवर, फिर भी मैं उसकी टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ... (व्यवधान) आप सुनिए भाई।... (व्यवधान) मैं उसकी टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। विडियो किसी के भी पास था, मैं इन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। वह किसी के भी पास था, अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता, तो 5 तारीख को ही वे लोग पकड़ लिये गये होते क्योंकि जिस दिन विडियो दिया गया, उसी दिन विडियो की कॉपी से फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, सरकारों के डेटा से मिलान करते हुए, उन 7 के 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और वे आज ट्रायल फेस कर रहे हैं। वे सारे जेल में हैं।

(1845/PC/SMN)

मान्यवर, मैं वहां शांति के लिए किए गए प्रयासों को भी सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं। ... (व्यवधान) मैं वहां तीन दिन रहा, तीन रात रहा। ... (व्यवधान) मेरे साथी नित्यानन्द जी, एमओएस, होम 23 दिनों तक लगातार वहां रहे। ... (व्यवधान) पहले कोई गया ही नहीं, पहली बार मैं ही गया हूं। ... (व्यवधान) इतने सारे दंगे, जो मैंने अभी बताए हैं, उनमें अब तक कोई नहीं गया है। ... (व्यवधान) एमओएस 23 दिन वहां रहे, तीन दिन मैं रहा। ... (व्यवधान) हमने इस सारे मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईएएस और आईपीएस अफसर भी हैं।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय को उसका अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां प्रस्थापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी, जहां मैतई समूह रहता है, जहां कुकी समूह रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई, क्योंकि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज़ दिन-रात तैनात हैं। इसलिए, हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बनाई है, क्योंकि वहां बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, असम राइफल्स भी है, सेना भी है और मणिपुर पुलिस भी है। पांचों सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यूनाइफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है और उसकी चेयरमेनशिप यहां से भेजे हुए सुरक्षा सलाहकार के हाथ में है। इस घटनाक्रम के पीछे षडयंत्र वाले जो छ: केसेज़ रजिस्टर किए गए हैं, छ: के छ: केसेज़ पहले सीबीआई को दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने और 11 केसेज़ सीबीआई को दिए हैं। इसके लिए भी एसआईटी आज गठित हो गई है।

मान्यवर, पीड़ित और पुनर्वसन पैकेज दिया गया है। सभी मृतकों के परिवार वालों को दस लाख रुपए चुकाने का काम समाप्त हो चुका है। लगभग 30 हजार मीट्रिक टन चावल रातों-रात पीयूष भाई ने यहां से वहां भेजे हैं, जो वहां बांटा जा रहा है। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं का अभाव न हो, इसलिए भारत सरकार की आठ टीमें अलग-अलग एम्स से वहां कैम्प कर दी गई हैं। कोर्ट में मुकदमों में किसी की एक्स पार्टी सुनवाई न हो, इसलिए चारों प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर्स के यहां वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा कर दी गई है, इसलिए हाई कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है। सबकी सुनवाई वहीं से हो रही है। बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गई है। घाटी में 98 प्रतिशत स्कूल्स खुल गए हैं, 80 प्रतिशत उपस्थिति रहती है। दो प्रतिशत स्कूलों में कैम्प चल रहे हैं, वहां भी हमने स्थाई शेल्टर्स बनाने की शुरुआत कर दी है। राहत सामग्री सुलभता से मिले, इसके लिए भी हमने

ढेर सारे प्रयास किए हैं। सुरक्षा की समीक्षा भी हर सप्ताह मैं यहां से वीडियो कांफ्रेंस से यूनिफाइड कमांड के साथ करता हूं। गृह सचिव हर दूसरे दिन करते हैं और डीआईबी हर रोज करती है।

मान्यवर, इतनी क्लोज़-वॉच के साथ वहां शांति बनाने का प्रयास चल रहा है। मैंने पहले कहा कि पुरानी सरकारों में, किसी में नौ महीने हुआ, किसी में डेढ़ साल हुआ, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कम से कम समय में इस हिंसा को शांत करने का काम हम कर पाएंगे। ऐसा मुझे भरोसा है। … (व्यवधान) आज इस सदन को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मणिपुर के अंदर … (व्यवधान) आप बाद में पूछना, बैठ जाइए। … (व्यवधान) ऐसे चर्चा नहीं होती है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर जी, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

(1850/CS/RU)

श्री अमित शाह : मान्यवर, सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाड़ बनाने का काम शुरू हो चुका है, बाकी बाड़ का सर्वे हमने और तेज गति से चालू किया है, बायोमीट्रिक्स लेने की गति भी हमने बढ़ा दी है।

मैं इस सदन के माध्यम से मणिपुर के दोनों समुदायों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए, अभी हम मैतई समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूँ। कुकी समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, आज भी की थी। मैं स्वयं कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि साथ में बैठकर, भारत सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। अफवाहों से ज्यादा अविश्वास का वातावरण पैदा हुआ है। भारत सरकार की जरा भी मंशा नहीं है कि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए। हम घुसपैठ को भी रोकेंगे। हमने राजद्वारी तरीके से म्यांमार के साथ भी बात की है। हर प्रयास हम करना चाहते हैं, जो हम कर पाते हैं।

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह विषय ऐसा है, जिसमें किसी की जान गई है, किसी का सम्मान गया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। वह व्यक्ति हमसे कितना भी दूर रहता हो, मगर वह भारत का है और उसके प्रति हम सबके मन में, पूरे सदन के मन में संवेदना होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस शान्ति की अपील में मेरी बात रखने के बाद सदन के दोनों ओर के सदस्य शान्ति की अपील में जुड़ेंगे। मैं बाकी सब का तो भरोसा नहीं दे सकता, मगर एनडीए के सारे सदस्य तो जुड़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है।

मान्यवर, इन लोगों ने जो पॉलिटिकल बात की है, मैं थोड़ा उसका भी जवाब देना चाहता हूँ। जो अब तक चर्चा हुई है, इसमें जो पॉलिटिकल बातें हुई हैं। गौरव गोगोई जी ने मणिपुर की नस्लीय हिंसा की ढेर सारी बात की, उन्होंने आंकड़े बताए। मैं आपके माध्यम से श्री गौरव गोगोई को कहना चाहता हूँ और रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के समय में हुए हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि असम में 15 फरवरी से 27 मार्च 1983 तक 750 लोग मारे गए। आन्ध्र प्रदेश में 6 दिसम्बर 1990 से 1991 तक, हैदराबाद में 143 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश 13 अगस्त

1980, मुरादाबाद में दो ही दिन में 1 हजार लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश 18 मई से 23 जुलाई 1927, मेरठ में 187 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश 7 से 31 दिसम्बर, अलीगढ़ में 112 लोग मारे गए। गुजरात फरवरी 28… (व्यवधान) से जुलाई 31, 1985… (व्यवधान) 206 लोग मारे गए। झारखंड में 183 लोग 1967 में मारे गए।… (व्यवधान) पश्चिम बंगाल 16 मार्च 1964,…(व्यवधान) राउरकेला,… (व्यवधान) कोलकाता में 1 हजार से अधिक लोग मारे गए।… (व्यवधान) बिहार, जमशेदपुर में 120 लोग मारे गए।… (व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह इसलिए बताता हूँ।… (व्यवधान) आप सुनिए।… (व्यवधान) मैं यही कहना चाहता हूँ।… (व्यवधान) शान्ति की अपील में सहयोग के लिए धमकी से मानोगे।… (व्यवधान) ऐसा करोगे कि मैं यह पढ़ूँगा तो शान्ति में सहयोग नहीं दोगे, आप ऐसा कहना चाहते हैं।… (व्यवधान) शान्ति की अपील और इसका क्या लेना-देना, यह तो मैं आपका राजनीतिक जवाब दे रहा हूँ।… (व्यवधान)

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दंगे हर बार हुए, मगर दंगों को हमने कभी पार्टी के साथ नहीं जोड़ा। हमने कभी दंगों का जवाब देते हुए किसी गृह मंत्री को नहीं रोका। हमने कभी सदन को बैन में नहीं लिया। हमने कभी 15-15 दिन तक सदन की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया है। हमने किया है तो विपक्ष में रहते हुए भी शान्ति की अपील का समर्थन किया है, शान्ति का समर्थन किया है।… (व्यवधान)

(1855/RV/SM)

माननीय अध्यक्ष जी, गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि संस्थाओं को टार्निश किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस तोड़े जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थीं, सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों को बाइपास करके श्री हंस राज खन्ना को जज बनाया गया और बाद में अपने मुकदमे में स्टे लिया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, सी. एण्ड ए.जी. को सरकारी कामकाज से दूर रखने का काम इन्दिरा गांधी जी ने किया। जे.एन.यू. पर ताला लगाने का काम इन्दिरा गांधी ने किया था। यू.पी.एस.सी. जैसी स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्था के अधिकारों को छीनने का काम इन्दिरा गांधी जी ने किया था।… (व्यवधान) क्या आपको इतिहास मालूम नहीं है?… (व्यवधान)

मान्यवर, मुझे मालूम है कि शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्हें शांति नहीं करनी है, ये अभी वॉक-आउट कर जाएंगे।… (व्यवधान)

सुप्रिया सुले जी ने कहा कि हमने सरकार गिरा दी। सुप्रिया जी से मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहली सरकार महाराष्ट्र में अगर किसी ने गिराई तो श्रीमान् शरद पवार जी ने गिराई। बसन्तदादा पाटील की सरकार गिराकर भारतीय जनसंघ का समर्थन लेकर वे मुख्य मंत्री बने।… (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, भारतीय जनसंघ का समर्थन लिया।… (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): मान्यवर, जोशी जी उसके कन्वीनर थे।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : कन्वीनर तो ठीक है, पर मुख्यमंत्री कौन बना? सत्ता किसने भोगी? सत्ता का सुख किसने प्राप्त किया?… (व्यवधान)

मान्यवर, गौरव गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। मोदी जी तो एक बहुराष्ट्रीय मीटिंग में चीन के राष्ट्राध्यक्ष से मिले थे। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर, मोदी जी ने 'हिन्दी-चीनी, भाई-भाई' के नारे नहीं लगाए थे, जिससे वर्ष 1962 जैसी करारी हार का सामना करना पड़ा। श्री जवाहर लाल नेहरू जी तो इसी सदन में, आकाशवाणी पर बोल गए थे - 'बाय-बाय, असम'। हमारे सेना के जवानों ने असम को बचाया। चीन ने एकतरफा समाधान किया, तब वह बचा।… (व्यवधान)

मान्यवर, वर्ष 2008 में बीजिंग के द ग्रेट हॉल ऑफ पिपुल में चीनी उप राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ समझौता हस्ताक्षर किसने किया था? वहां कौन था और ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं।

मान्यवर, चीनी दूतावास की वेबसाइट पर एक तस्वीर है जिसमें ओलम्पिक में चीन की मेजबानी में गांधी-वाड्रा परिवार की एक पूरी तस्वीर है, जिसमें पूरी मेज खाने की चीजों से भरी पड़ी है। यह कोई अन्तर्राष्ट्रीय संवाद या गोष्ठी नहीं थी।

मान्यवर, अभी-अभी 'न्यूजक्लिक' के बारे में खुलासा हुआ है। न्यूजक्लिक इन सारे लोगों को बहुत पसन्द है क्योंकि वे हमें गाली देते हैं, मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो ये बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ इनपुट्स भी देते हैं, वहां से ली गयी कुछ चीजों को फॉरवर्ड भी करते हैं। इसमें ये सब के सब हैं, पूरा यूपीए का गठबंधन है। परन्तु, यह न्यूजक्लिक किसके पैसे से चलता है? यह चीनी एजेंसी के पैसे से चलता है और ये हमसे सवाल पूछते हैं।

(1900/GG/RP)

मान्यवर, इनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। यूपीए अच्छा नाम था। 10 सालों तक सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम थी, नाम क्यों बदलना पड़ा? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देश की जनता को सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इतने सारे घोटाले इन्होंने किए थे, उनका टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ रुपये के बाद मैंने गिनती करना छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ रुपये के घपले-घोटाले यूपीए के नाम पर चढ़े हुए हैं तो बाज़ार में कैसे जाएं? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख़ खराब हो जाती है तब वह नाम बदल लेती है। बोर्ड बदल देती है। इन्होंने भी नाम बदल दिया। … (व्यवधान)

मान्यवर, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2जी स्पेक्टर्म घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। टाटा ट्रक घोटला किसने किया? यूपीए ने किया। नोट के बदले वोट का घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। चारा घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। गाज़ियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। आईपीएल का घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। एलआईसी हाऊसिंग का घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। मधु कोड़ा वाला घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। फायर प्रोन सबमरीन का घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। … (व्यवधान)

साहब, इनके पास नाम बदलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। … (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन 9 सालों में और अटल जी के 6 सालों

में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिससे सर झुकाना पड़े। … (व्यवधान) हम सीना तान कर मैदान में जाएंगे। … (व्यवधान)

मान्यवर, एनडीए ने स्थिरता दी। 10 सालों तक स्थितरता दी। 30 सालों तक कांग्रेस ने किसी भी सरकार को चलने नहीं दिया। चंद्रशेखर जी को सबसे पहले हटाया। चरण सिंह जी को समर्थन दिया, फिर सरकार गिरा दी। उसके बाद चंद्रशेखर को समर्थन दिया, फिर सरकार गिरा दी। देवेगौड़ा को समर्थन दिया, फिर सरकार गिरा दी। मान्यवर, इनकी फ़ितरत अस्थिरता है। मोदी जी ने, एनडीए ने, भाजपा ने देश को स्थिर शासन दिया है। इसलिए देश को हम पर विश्वास है।

मान्यवर, मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश के बच्चे-बच्चे में देशभक्ति का संस्कार सिंचित करने का काम किया है। मान्यवर, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने देश के एक-एक जन के मन में देश के प्रति सम्मान और सुनहरे भविष्य की आशा को निर्मित करने का काम किया है।

मान्यवर, मोदी जी ने शताब्दी के लक्ष्य तय किए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होते ही 15 अगस्त को अमृत-काल शुरू होगा। 25 वर्षों के अंदर हर क्षेत्र में भारत को विश्व में नंबर वन बनाने का लक्ष्य लिया है। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आपको अविश्वास है, लेकिन जनता को विश्वास है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भी अगर आप जनता के बीच में जनता के मुद्दों को ले कर नहीं जाएंगे, ऐसे गलत मुद्दे ले कर जाएंगे तो वहीं बैठना पड़ेगा, आपको कितना भी बुरा लगे।

मान्यवर, मैं आज इस सदन में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से देश की जनता को करबद्ध विनती करना चाहता हूँ कि देश को आगे ले जाना है। भारत को ऐसे mode में ला कर मोदी जी ने खड़ा किया है कि इसको कोई रोक नहीं सकता है। आजादी के अमृत वर्ष में हम सब ने, आने वाली शताब्दी में भारत कैसा होगा, इसका संकल्प लिया है। संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए ये 25 साल हैं। एक बार फिर 5 साल मोदी जी को दे दीजिए। आने वाले दिनों में भारत विश्व के सभी क्षेत्रों में एक नंबर का देश बनेगा।

(1905/MY/NKL)

मान्यवर, अंत में मैं फिर से मणिपुर के दोनों कम्युनिटीज से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि खुफिया हिंसा छोड़ दीजिए, भारत सरकार के साथ चर्चा में आइए।… (व्यवधान) आप अकेले चर्चा करते हैं, इसकी जगह आप साथ में चर्चा कीजिए, रास्ता निकालिए और जल्द से जल्द हम खुशहाल मणिपुर बनाएं। यही मेरी प्रार्थना है।… (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं पुन: सुबह की घटना के लिए माननीय सदस्य टी.एन. प्रथापन को अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं। सुबह टी.एन. प्रथापन ने जिस तरीके से सदन और आसन की गरिमा को कम करने का प्रयास किया है, यह सदन की गरिमा के लिए अनुकूल नहीं है। मैं किसी भी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहता, लेकिन अगर इस तरह की घटना घटेगी तो मैं कार्रवाई करूंगा।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मुझे लगता है कि आज लंबे समय के बाद मणिपुर पर चर्चा हुई है और सभी ने मुझे सुना है। इस सदन को मणिपुर में शांति के लिए प्रस्ताव करना चाहिए। मणिपुर की दोनों कम्युनिटीज को शांति रखने की अपील सदन के माध्यम से जाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अध्यक्ष के नाते मेरा आप सभी से आग्रह है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पहले आप बोल लीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हम तो सदन में चर्चा की मांग आज से नहीं, बल्कि शुरू के दिनों से करते आ रहे हैं।… (व्यवधान) सदन में चर्चा की मांग के साथ-साथ, हम लोग बार-बार गुहार लगाते आ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री सदन में आएं और चर्चा की शुरुआत करें।… (व्यवधान) हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, हम लोगों ने यह कभी नहीं कहा कि उनकी काबिलियत पर हमें कोई शक है।… (व्यवधान) लेकिन, हम यह बात जरूर कहेंगे कि जो जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है, वह कोतवाल कैसे देंगे।… (व्यवधान) इसीलिए, हम लोग बार-बार प्रधानमंत्री जी को आने के लिए कह रहे थे।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आप एक मिनट के रुकिए। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। आप एक मिनट के लिए बात सुनें। मैं आपको मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठिए।

… (व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मणिपुर पर चर्चा की मांग विपक्ष के द्वारा की गई थी। यहां पर मणिपुर की चर्चा हुई है और गृह मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया है। अविश्वास की प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है, उसका उतर देने के लिए कल प्रधानमंत्री जी भी स्वयं सदन में उपस्थित रहेंगे। लेकिन, गृह मंत्री जी ने आग्रह किया है कि पूरे सदन की तरफ से एक अपील होनी चाहिए, ताकि मणिपुर में शांति की बहाली हो सके। मैं समझता हूं कि इसमें सभी का सहयोग प्राप्त होना चाहिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए रूकिए। आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, मैं आपको बोलने के लिए मौका दूंगा। आप बैठिए। एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, मैं आपको मौका दूंगा। आप सभी विराजें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, प्लीज आप बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी ने सदन से जो अपील की है, आप इस पर सहमत हैं या नहीं हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप शांति की अपील पर सहमत हैं या नहीं हैं? मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह: आप प्रस्ताव रखिए, उन्हें नहीं करना है तो न करें। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमें ड्राफ्ट दिया जाए। सभी को ड्राफ्ट दिया जाए।… (व्यवधान) हम प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में करना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी को गवाह रखते हुए करना चाहते हैं। … (व्यवधान) यह हमारी मांग है।… (व्यवधान) यह मांग तो हमारी है।…(व्यवधान)

(1910/CP/SPR)

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन की तरफ से यह प्रस्ताव रखता हूं:

> “कि सम्पूर्ण सदन, जो कुछ भी घटना मणिपुर में घटी है, उस पर शांति की अपील करता है और सभी पक्षों से, सभी गुटों से, जो माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, उस पर सर्वसम्मति से सारा सदन सहमत है।”

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 10 अगस्त 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1911 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 10 अगस्त 2023/19 श्रावण 1945 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।